विषय सूची

सत्र–8 (भाग–01) शनिवार, 23 फरवरी, 2019 / 4 फाल्गुन, 1940 (शक) अंक–97

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–4
3.	प्रतिवेदन पर सहमति	4
4.	आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण	5
5.	माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	5–61
5.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)	62–148

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–8 (भाग–01) शनिवार, 23 फरवरी, 2019 / 4 फाल्गुन, 1940 (शक) अंक–97

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11:30 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुएः

1. श्री शरद कुमार
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री पवन कुमार शर्मा
4. श्री अजेश यादव
5. श्री सुखवीर सिंह दलाल
6. श्री ऋतुराज गोविन्द
7. श्रीमती बंदना कुमारी
8. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
9. श्री राजेश गुप्ता
10. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
11. श्री सोमदत्त
12. श्री आसिम अहमद खान
13. श्री विशेष रवि
14. श्री हजारी लाल चौहान
15. श्री गिरीश सोनी
16. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
17. श्री जरनैल सिंह
18. श्री राजेश ऋषि

19. श्री महेन्द्र यादव
20. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
21. सुश्री भावना गौड़
22. श्री सुरेन्द्र सिंह
23. श्री विजेन्द्र गर्ग
24. श्री मदन लाल
25. श्री सोमनाथ भारती
26. श्रीमती प्रमिला टोकस
27. श्री नरेश यादव
28. श्री करतार सिंह तंवर
29. श्री प्रकाश
30. श्री अजय दत्त
31. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
32. श्री सही राम
33. श्री नारायण दत्त शर्मा
34. श्री राजू धिंगान
35. श्री मनोज कुमार
36. श्री नितिन त्यागी
37. श्री ओमप्रकाश शर्मा
38. श्री एस.के. बग्गा
39. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
40. मो. इशराक
41. श्री श्रीदत्त शर्मा
42. चौ. फतेह सिंह
43. श्री जगदीश प्रधान
44. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र–8 (भाग–01) शनिवार, 23 फरवरी, 2019/4 फाल्गुन, 1940 (शक) अंक–97

सदन पूर्वाह्न 11:30 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत है।

मुझे कई माननीय सदस्यों से विभिन्न विषयों पर विभिन्न सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं लेकिन मैं पिछले सत्र के दौरान यह स्पष्ट कर चुका हूँ कि कार्य–सूची में सूचीबद्ध विषय के अलावा किसी अन्य विषय पर विचार कर पाना संभव नहीं होता क्योंकि सदन के समय का अधिकतम उपयोग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। अतः मैं किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं; विजेन्द्र गुप्ता जी, जगदीश प्रधान जी, ओमप्रकाश जी, नितिन त्यागी जी, जरनैल सिंह जी, विजेन्द्र गर्ग जी,

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

गुलाब सिंह जी और महेन्द्र गोयल जी। इन माननीय सदस्यों से सूचनाएँ प्राप्त हुई थी। भावना गौड़ जी को मैंने स्वीकृति दी है।

सुश्री राखी बिड़ला प्रस्ताव करेंगी कि यह सदन दिनांक 22 फरवरी, 2019 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रतिवेदन पर सहमति

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन दिनांक 22 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

...(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्माः दूसरे पक्ष की आप सुनते नहीं हैं। मैंने 55 में आपसे निवेदन किया था तो आप... को जब रिजेक्ट ही कर देते हैं तो फिर ये खानापूर्ति करने का लाभ क्या है?

आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2018–19 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।[2]

माननीय उप राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी

माननीय अध्यक्षः अब माननीय गोपाल राय जी, माननीय विकास मंत्री, दिल्ली 22 फरवरी, 2019 को उनके द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्री गोपाल राय जी।

अन्य सदस्य भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। वे अपना नाम भेज दें।

माननीय श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय उप राज्यपाल महोदय ने सरकार के कार्यों को लेकर के अपना अभिभाषण सदन के अंदर प्रस्तुत किया। उसके लिए हम उनका धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं।

---

2. पुस्तकालय में संदर्भ सं. 20463 पर उपलब्ध।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का चार साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कल उप राज्यपाल महोदय ने जो सरकार का लेखा जोखा सदन के सामने प्रस्तुत किया, वो इस बात को दिखाता है कि किस तरह एक सरकार एक इंसान की जिन्दगी को केंद्रित करके अपनी कार्य योजना बनाती है और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसे इस देश की राजधानी दिल्ली में क्रियान्वित करने का काम करती है; चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो; शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर के टेक्निकल एजुकेशन तक का जो व्यूह रचना दिल्ली सरकार ने बनाई और जिस तरह से लागू किया, खास तौर से आज पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि आहिस्ता–आहिस्ता आजादी के बाद से इस देश के अंदर इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि सरकारी तंत्र में जो शिक्षा व्यवस्था है, वो कॉलेप्स कर चुकी है, ठीक नहीं की जा सकती है। जिस गिरती हुई, बिगड़ती हुई व्यवस्था के सामने पूरा देश सरेंडर कर चुका था, दिल्ली के अंदर जिस तरह से एसएमसी के माध्यम से, जिस तरह से अलग अलग कार्य योजनाओं के माध्यम से न सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया बल्कि उसकी एजुकेशन क्वालिटी को ठीक किया गया है, आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना है। लोग कहते थे कि उल्टी गंगा नहीं बह सकती है लेकिन दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में आज उल्टी गंगा बह रही है। और आज न सिर्फ दिल्ली का बल्कि पूरे देश का एक कॉन्फिडेंस बन रहा है कि अगर सरकार चाहे तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन सरकारी तंत्र में किया जा सकता है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ।

साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिक हो, चाहे पॉलीक्लीनिक हो, चाहे स्पेशल हॉस्पिटल्स हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, आज मोहल्ला क्लीनिक को लेकर के इतनी बेचैनी है कि मोहल्ला क्लीनिक किसी तरह से रोक दिया जाए। इसके लिए सारे षडयंत्र हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल जिस तरह से दिल्ली के लोगों के दर्द को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और खास तौर से पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटलों के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज पूरी दिल्ली के अंदर चाहे गरीब हैं, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनकी जिंदगी में, उनके परिवार में रोजाना की जद्दोजहद से जिंदगी तो चलती है लेकिन अगर किसी की तबियत खराब हो जाए, अचानक कोई बीमार पड़ जाए तो सबके हाथ पाँव फूल जाते हैं; कर्जे लेने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई, आज दिल्ली के अंदर चाहे कोई भी हो, किसी तरह की अगर बीमारी हो जाए या तो सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज होने की जो गारंटी हो रही है और नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार ने अपने खर्चे पर जिस तरह से इलाज की गारंटी की है, आज निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर शिक्षा के बाद स्वास्थ्य को लेकर के दिल्ली के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है।

ठीक उसी तरह से दिल्ली के अंदर सोशल सिक्योरिटी को लेकर के जिस तरह से यहाँ पेंशन बढ़ी है, आज भी अगर हमारे आजू–बाजू अगर हम चले जाएँ, अलग–अलग राज्यों की सरकारें हैं। बगल में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। अभी राजस्थान

में काँग्रेस की सरकार बनी है। मध्य प्रदेश में बनी है। अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग सरकार है लेकिन आज देश के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, जिस तरह से दिल्ली के अंदर बढ़ाई गई है, वो इस बात को दिखा रही है कि दिल्ली की सरकार एक आम आदमी की जिंदगी के लिए कैसे काम करती है और सोचती है। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों की जिंदगी में एक सकारात्मक जो है, एक खुशहाली की एक किरण खुली है। उसी तरह से सामाजिक तौर पर अन्य हिस्सों को लेकर के भी सरकार ने योजना बनाई। जिस तरह से पिछड़े और दलित परिवार से आने वाले बच्चों के लिए कोचिंग के लिए जिस तरह से सिस्टम बनाया सरकार ने, वह एक साकारात्मक कदम है। उसी तरह से इस देश के अंदर दिल्ली राजधानी होने के नाते देश भर से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दिल्ली में आते हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से ये दिल्ली सरकार ने मिनिमम वेज बढ़ाने का काम किया और न सिर्फ बढ़ाया बल्कि उसके लिए संघर्ष करके अंततोगत्वा आज दिल्ली के अंदर साढ़े नौ हजार रुपये से बढ़ाकर के चौदह हजार रुपये मिनिमम वेज हुआ है और न सिर्फ मिनिमम वेज बढ़ाया है बल्कि दिल्ली के अंदर पिछले दिनों एक स्पेशल अभियान चलाकर के मिनिमम वेज न देने वालों के खिलाफ सरकार ने भी सख्त कदम उठाना शुरू किया है, उससे निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर मजदूरों की जिंदगी में एक खुशहाली का रास्ता खुला है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर किसानों के लिए, गांव के विकास के लिए जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कदम उठाए हैं, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से देश के अंदर आज दिल्ली को लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चर्चा हो रही है, उसी तरह से आज दिल्ली के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भी दिल्ली सरकार ने काम किया है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जिस तरह से आगामी दिनों में एक हजार क्लस्टर में और एक हजार डीटीसी में नई बसें आने का सिलसिला शुरू हुआ है, इलेक्ट्रिक बसें आने का सिलसिला शुरू हुआ है उससे निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर आवागमन को लेकर के एक साकारात्मक सुधार होगा और लोगों की जिंदगी में सहूलियत आएगी।

उसी तरह से पर्यावरण जो दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से एक समग्र नीति लेकर के और पिछली बार ग्रीन बजट लाकर के दिल्ली सरकार ने एक पहल किया, सभी चौतरफा पर्यावरण के सुधार के लिए सरकार काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा से लेकर के और बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा तक का हमें लगता है कि एक समग्र विकास का जिस तरह का खाका दिल्ली सरकार ने पिछले चार साल में न सिर्फ खींचा है, बल्कि उसे जमीन पर लागू किया है, आज पूरे देश के अंदर इस बात की हर जगह चर्चा है। चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो किसी भी समाज का रहने वाला हो, कि अगर सरकार की नीतियाँ ठीक हो और नीयत ठीक है तो नीतियाँ बनाई भी जा सकती हैं और सभी विपरीत परिस्थितियों में आधा राज्य होने के बावजूद भी उसे लागू किया जा सकता है। इसका उदाहरण, इसकी एक खाका के रूप में कल सदन के अंदर उप राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया सर।

माननीय अध्यक्षः सुश्री राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे कल जो उप–राज्यपाल जी का अभिभाषण था, उस पर बोलने का मौका दिया।

लेकिन अध्यक्ष जी मैं उससे पहले अपनी कुछ बात रखना चाहती हूँ। कल सदन में बैठे हुए सभी लोगों ने माननीय एलजी महोदय के मुंह से एक लाईन को बार–बार सुना; मेरी सरकार। मेरी सरकार ने ये काम किया, मेरी सरकार ने वो काम किया लेकिन वास्तव में इस सरकार के कामों को जो आज ये मेरी सरकार कह रहे थे, वो दिल पर पत्थर रखकर कह रहे थे, मजबूरी में कह रहे थे। वास्तव में अगर इस सरकार के कामों को रोकने का इस सरकार की एनर्जी को तोड़ने का इस सरकार को परेशान करने का काम केन्द्र सरकार के माध्यम से किसी ने दिल्ली के अंदर किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस दिल्ली के उप राज्यपाल श्री अनिल बैजल जी ने किया है। मुझे बहुत हँसी आ रही थी जब वो यहाँ से खड़े होकर बार–बार कह रहे थे; मेरी सरकार ने दिल्ली में पिछले चार सालों में विकास किया। जबकि वो कहना ये चाह रहे थे कि ये विकास कार्यो को मैं रोकना चाह रहा था लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी सरकार इतनी जिद्दी है कि जनता के हित के लिए चाहे उन्हें तपती दोपहरी के अंदर धरना देना हो या इनकी साथी विधायक के गर्भवती होने के बावजूद मोहल्ला क्लीनिक के लिए मेरे घर में आकर बैठना हो लेकिन अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करके इन विधायकों ने और इस दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया, अपने वादों को पूरा करने के लिए काम किया।

अध्यक्ष जी, ये मैं बात इस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपको भी याद होगा पिछले वर्ष जुलाई, मई–जून–जुलाई के समय में जब दिल्ली महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंकड़े पेश किये गए तो दिल्ली अव्वल दर्जे का राज्य बना, जहाँ सबसे ज्यादा महिलाएँ असुरक्षित हैं। जहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन–प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने ये फैसला किया कि दिल्ली की जनता को दिल्ली की महिलाओं को सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी वो निभाना चाहते हैं तो ये ही वो अनिल बैजल साहब थे जिन्होंने सीसीटीवी के कैमरे की फाइल को दबाकर रख लिया। कैमरे की फाइल को पास नहीं होने दिया। उस पर साइन नहीं होने दिया और दूसरी तरफ वही अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सारे विधायक थे, उनकी सरकार के सारे मंत्रीगण थे, जिन्होंने तपती दोपहरी के अदंर अनिल बैजल जी के घर के सामने प्रदर्शन किया, धरना दिया। अपनी सारी की सारी दिक्कतों को भूलकर सिर्फ एक लक्ष्य रखा कि इन महिलाओं को हम कैसे सुरक्षा दें। कैसे उन्हें इस बात का अहसास दिलाएँ कि वो अगर रात को चलें, दिन में चलें या दोपहरी में चलें, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को बहुत–बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, बुजुर्गो को सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए पूरी दिल्ली के अंदर डेढ़ लाख से ज्यादा सीसीटीवी लगाने का काम किया। मैं इसके लिए बहुत–बहुत दिल से पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को बधाई देती हूँ। उसी कारण अनिल बैजल जी जब बार–बार कह रहे थे कि मेरी सरकार ने स्वास्थ्य

के क्षेत्र में बहुत काम किया, तब मुझे फिर एक वाकया याद आया कि यही वो ही एलजी अनिल बैजल जी हैं, जब मोहल्ला क्लीनिक की फाइल पास नहीं हो रही थी, जब मोहल्ला क्लीनिक के लिए लगातार साइटें आईटैंटिफाइड कर ली थीं, मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए तमाम विधायक, मंत्री यह पूरी की पूरी सरकार तत्परता से लगे हुए हैं, तब ये ही अनिल बैजल जी थे जिन्होंने मोहल्ला क्लीनिक की फाइल के ऊपर कुंडली मार कर, उसे दबाकर बिठा लिया था। तब ये ही सारे विधायक हैं जिन्होंने रात बारह बजे तक उनके एलजी ऑफिस में धरना दिया और अपनी मोहल्ला क्लीनिक के फाइल को पास कराकर लाए और ऐसा इतिहास सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ देश में नहीं, बल्कि ऐसा इतिहास पूरी दुनिया में रचा कि उस मोहल्ला क्लीनिक के मॉडल को देखने के लिए अलग–अलग देशों की टीम आकर यहाँ पर सर्वे कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। तो मैं इस चीज के लिए स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने ऐतिहासिक कदम दिल्ली की जनता के लिए और देश के गर्व के लिए कार्य किये, इतने ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाए, वो मोहल्ला क्लीनिक जो गरीबों को भी सेवा देता है, वो मोहल्ला क्लीनिक जो अमीरों के भी स्वास्थ्य की चिंता करता है, वो मोहल्ला क्लीनिक जहाँ पर एक बुखार से लेकर बड़ी सी बड़ी समस्या का, बीमारी का हम जाकर समाधान करा सकते हैं, उस मोहल्ला क्लीनिक में सारे टेस्ट फ्री होते हैं, सारी दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं। तो ऐसी सरकार को हम बार–बार बधाई देते हैं जो सरकारें अपने से पहले अपने क्षेत्र की जनता अपने राज्य की जनता के बारे में सोचती है और आज देश के आप अलग–अलग राज्य

में जाएंगे, आपको भी जाने का मौका मिलता है। हम सारे विधायक साथी भी अलग–अलग राज्यों में जाते हैं। हम देखते हैं राज्यों के बड़े–बड़े अस्पतालों का ढाँचा किस प्रकार से चरमराया हुआ है। बड़े–बड़े राज्य जहाँ पर सो कॉल्ड दमदार केन्द्र की सरकार की नुमाइंदगी करने वाले राज्य सरकार के लोग भी हैं लेकिन उनके अस्पतालों में आप देखेंगे; इंसान क्या, जानवर भी अपना इलाज कराना पसंद नहीं करेंगे। वहीं एक आधे अधूरे राज्य का मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जिसकी आधी अधूरी शक्ति को भी छीनने के लिए लगातार तत्परता से श्री अनिल बैजल जी तैयार रहते हैं। उन्होनें इतनी विकट परिस्थितियों में इतनी कठिन परिस्थितियों में दिल्ली की जनता को इतना ऐतिहासिक तौहफा दिया मोहल्ला क्लीनिक के रूप में और आज दिल्ली की जनता उसे पाकर बहुत खुश है तो इसके लिए मैं अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट को, पूरे के पूरे विधायक साथियों को बहुत–बहुत बधाई देती हूँ।

इसी प्रकार से अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बातें करें तो मेरे अलावा अभी गोपाल राय जी और मेरे बाद भी जितने साथी बोलेंगे, वो सभी इसी बात पर बोलेंगे कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में इतने ऐतिहासिक कार्य करे। हमने इतने क्लास रूम बनाए लेकिन मैं आपका इशारा ले जाना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, एलजी की एक और करतूत के ऊपर जिसमें एलजी सर ने आपके माध्यम से जो हमने प्रस्ताव पास किया था कि हमारे तमाम जो गेस्ट टीचर हैं, उन्हें परमानेंट कर दिया जाए ताकि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा हम दे पाएँ। उन्हें एक बेहतर भविष्य दे पाएँ। दिल्ली का एक बेहतर

कल हम बना पाएँ। लेकिन एलजी साहब चूंकि इन्डॉयरेक्ट और डॉयरेक्टली नुमाइंदगी करते हैं केन्द्र सरकार की तो उन्हें ये नागवार गुजरा। उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि एक आधी अधूरी सरकार के लोग आकर किस प्रकार से दिल्ली की जनता को बेहतर शिक्षा दे पाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसे रोकना तो मेरा परम धर्म है और उस अपने परम धर्म को मोदी धर्म को, निभाते हुए एलजी साहब ने हमारे गेस्ट टीचर्स की फाइल को भी दबाकर रख लिया और आज फिर भी हम लोग अपने शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रच रहे हैं। ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने 27–28 जनवरी को पूरी दिल्ली के अंदर एक साथ लगभग ग्यारह हजार नए क्लास रूम बनाने का शुभारम्भ किया और ये उन्हें दिखाया कर के कि लाख बाधाएँ आ जाएँ लेकिन हम दिल्ली के बच्चों के शिक्षा के साथ, दिल्ली के उज्जवल भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। किसी भी प्रकार के जो बुरे इरादें हैं, उनको आगे नहीं आने देंगे। हम दिल्ली के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जितने बेहतर कदम उठाएँगे, जितनी कड़ी चुनौतियों से चाहे टक्कर चाहे लेनी पड़े, लेकिन वो टक्कर लेंगे और दिल्ली के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे।

इसी प्रकार से दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि आज से पहले आपने देखा होगा मंत्रीगण, विधायकगण, विधान सभाओं की कमेटियाँ विदेशों के टूर पर जाती थी। अलग–अलग राज्यों में जाकर वो टूर किया करती थी लेकिन एक मात्र ऐसी सरकार पिछले 70 साल के

अंदर देश में आई है जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम कर रही है। यहाँ पर मंत्रीगण विदेशों की यात्रा पर नहीं जाते, विधायक विदेशों में ट्रेनिंग नहीं लेते। यहाँ पर अगर कोई विदेशों में ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो वो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, हैड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं और अलग–अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। इसके लिए मैं भाई मनीष सिसोदिया जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि वो एक मात्र ऐसे शिक्षा मंत्री है देश के अंदर जो अपने दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर कल के लिए देश के आने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं अन्यथा 28 राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं और जो देश के आज जो राज्य, देश के जो शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर हैं, वो अपने घर भरने के लिए, अपने प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ 28 में से अगर 29वाँ राज्य गिनें जो एक आधा अधूरा राज्य है, जिसकी ताकत को छीनने के लिए लगातार पिछले चार सालों से तत्परता के साथ केन्द्र सरकार के माध्यम से अलग अलग...

माननीय अध्यक्षः राखी जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

सुश्री राखी बिड़लाः षडयंत्र किए जा रहे हैं। उस 29वें राज्य का ये आधा अधूरा शिक्षा मंत्री इतने ऐतिहासिक कार्य कर रहा है कि उसके इन कार्यों को देखने के लिए विदेशों से अलग अलग टीमें आ रही हैं और उनका सर्वे कर रही हैं।

इसी कड़ी में अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय इतना कम दिया लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने इतने सारे काम करे, अगर उनकी प्रशंसा करी जाए तो पूरा बजट सत्र भी कम पड़ेगा।

इसी कड़ी में तीर्थ यात्रा योजना का अध्यक्ष जी, अभी हम लोगों ने शुभारम्भ किया, ये तीर्थ यात्रा योजना सिर्फ योजना नहीं है, हमारी एक केन्द्र में बैठी हुई सरकार अपने आपको हिन्दुत्व की सरकार कहती है, हर तबके की सरकार कहती है, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार कहती है जो महज सिर्फ एक जुमला है। वास्तव में सबका साथ, सबका विकास कैसे होता है, वो मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने कर कर दिखाया और हमने अपने बुजुर्गों को सम्मान देते हुए, बुजुर्गों की आत्मा की आवाज को सुनते हुए तीर्थ यात्रा योजना अपनी शुरूआत किया और इस तीर्थ यात्रा योजना में हर जाति, हर मजहब, हर धर्म के 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने साथ ही विधायक कार्यालय में जाकर या अपनी सरकार के माध्यम से जाकर वो अपनी तीर्थ यात्रा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिक्ख हो, ईसाई हो, जो भी उसके धर्म का तीर्थ स्थान है वहाँ पर जा कर अपनी धार्मिक यात्रा कर सकता है। इसी प्रकार से अध्यक्ष जी, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार ने तो सिर्फ कुछ ही लोगों का विकास करा लेकिन वास्तव में अगर इस नारे को किसी ने जो है पूर्ण रूप से सफल किया तो वो अरविंद केजरीवाल है। इस अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम किया, बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए काम किया, इस सरकार ने न सिर्फ तीर्थ यात्रा का जो आयोजन कर

कर बुजुर्गों की बात सुनी बल्कि इस सरकार ने, इस दिल्ली देश की राजधानी में जो अलग–अलग राज्यों से आकर मजदूर बसे हैं, उन मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का, उन्हें आर्थिक समानता देने का भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया और उस कदम को उठाते हुए दिल्ली देश की ऐसी पहला जो है, राज्य है और दिल्ली देश की राजधानी में पहली बार किसी सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि बिना मजदूरों के हड़ताल किए, बिना मजदूरों की आवाज बुलंद किए, बिना मजदूरों के...

माननीय अध्यक्षः राखी जी, आप कन्क्लूड करिए, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

सुश्री राखी बिडलाः कुछ कहे उसको मिनिमम वेजिज को दिल्ली के अंदर देश में सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किया।

इसी प्रकार से आज देखेंगे, अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार से दलितों को शिकार बनाया जा रहा है कि इनका विकास न हो सके, ये समाज में एक तबके के बराबर न आ सकें, लेकिन ऐसे में मिसाल कायम करते हुए दिल्ली सरकार ने एससी/एसटी के लोगों को, हमारे छात्रों को मजबूत करने के लिए, हमारे समाज के बच्चे भी आईएएस, आईपीएस बनें, बड़े बड़े पदों पर आसीन हों, इसके लिए 'जय भीम मुख्य मंत्री प्रतिभा योजना' का आरंभ करा जिस के तहत अगर क्योंकि आर्थिक रूप से भी कमजोर है, सामाजिक रूप से भी समाज कमजोर है, तो उस समाज को हाशिये पर से उठा कर अग्रिम पंक्ति में लाने का काम अगर किसी ने किया तो वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व

में दिल्ली सरकार ने किया। मैं इस कार्य के लिए भी दिल्ली सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद राखी जी, धन्यवाद।

सुश्री राखी बिड़लाः पिछले चार साल से बिजली हब और पानी मार्क का जो नारा हमने चुनाव के दौरान दिया था, वो लगातार चार सालों तक अभी भी कायम है। मैं इसके लिए भी दिल्ली सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सबसे ज्यादा बधाई हमारे 70 के 70 विधायकों को कि हमारा 4 करोड़ का फंड ऊँट के मुँह में जीरे जैसा था कि उस चार करोड़ में हम अपनी विधान सभा में क्या काम कराएँ, क्या न कराएँ, उस विधान सभा के विधायक फंड को चार करोड़ से बढ़ा कर 10 करोड़ करने के लिए भी मैं दिल्ली के तमाम मंत्रियों का, मुख्य मंत्री का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने कम समय में दिल्ली की सरकार की उपलब्धियाँ गिनाना बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं चेयर का सम्मान करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे एलजी के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया।

अब मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो मनीष सिसोदिया जी, हमारे मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी गली–गली इन लोगों ने काम किया, जा के उस गरीब के झोपड़े तक पहुँचे जहाँ पर आज जिसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इन्होंने ने

उनके दुःख को जानने की कोशिश की कि किस तरीके से चार पाँच से छः हजार रुपये में वो अपना गुजर बसर करते हैं। उन्हीं सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आज जो तीन साल पीछे बीत चुके हैं, चार साल बीत चुके हैं, उसका जितना भी बजट बनाया गया, उन सारी बातों को ध्यान में रख के बनाया गया। आज कल हमारे उप राज्यपाल दिल्ली के जो बातें कर रहे थे, वो सारा उसका श्रेय जो है, हमारे उप मुख्य मंत्री, हमारी कैबिनेट और मुख्य मंत्री को जाता है। जहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि पाँच हजार, छः हजार देने वाला वो अपना किराया देने के बाद और अपने बच्चों की फीस और रोटी खाने के बाद उसके पास बिजली पानी के लिए पैसे नहीं बचते थे तो बिजली आधी करके, पानी माफ करके दिल्ली सरकार ने एक सबसे बड़ा उनकी जेब पे जो है, एक उनको आराम पहुँचाया। उनको एक उनके बजट में उनको हैल्प की और साथ साथ उनकी सेलेरीज जो बढ़ा कर उनके जख्मों पे मरहम लगाया कि मुझे मालूम है कि वो रस्ते में से छोटी छोटी बोतलें चुनते हुए ले जाते थे कि कबाड़ी की दुकान पे जा के वो कहते थे कि इससे हम लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इससे हम अपने घर की सब्जी ले के आते हैं। तो आज उनको ये 14 हजार रुपये जब सेलेरी मिलनी शुरू हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी सरकार ने किया और सबसे बड़ी बात जो हमारी सरकार ने की कि आज तक बाकी सरकारें हमेशा चिल्ला चिल्ला के आज कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वजह से दिक्कतें हैं। हमारे उप मुख्य मंत्री ने इसी पॉपुलेशन को जो है, अपना एक असेट बनाते हुए एजुकेशन... में काम किया ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख

के पूरे 190 कंट्रीज में जाकर जब वो काम करेंगे तो कहीं न कहीं इंडियन इकॉनॉमी को जो है, सपोर्ट करेंगे। एजुकेशन में जब ये बच्चे बड़े हो जायेंगे, चाहे वो छोटा बच्चा था या ग्यारहवीं का बच्चा था, या 12वीं का बच्चा था, जब ये कंप्यूटर इंजीनियर, आर्किटेक्चर, डाक्टर, इंजीनियर्स बन कर जब ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे होंगे तो ये कहीं न कहीं हमारे उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी को धन्यवाद देंगे कि इनकी वजह से आज जो है, इस लेवल तक पहुँचे हैं। और साथ ही साथ में पूरे कैबिनेट में जो अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री करने का और डॉयलिसिस मशीनें नहीं लगी होती थी, कल रात को 11 बजे एक आदमी मुझे धन्यवाद करने आया कि मेरी सिस्टर जो है, ये डॉयलिसिस की आपने जो मशीनें लगाई हैं दीन दयाल में, मैं अपनी बहन को बचा पाया। नहीं तो शायद मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉयलिसिस मैं करवा सकूँ। तो ये जो दवाइयाँ फ्री अस्पताल में हर तरीके की फैसिलिटी और मोहल्ला क्लिनिक बना के जो दिल्ली सरकार ने पूरे विश्व भर में अपना नाम ऊँचा किया है, उसके लिए मैं अपनी दिल्ली सरकार और हमारे उप राज्यपाल जो कल मेरी सरकार, मेरी सरकार कह के कह रहे थे, उनको धन्यवाद देता हूँ और गोपाल राय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये गरीब का पाँच सौ रुपये में कोई गुजारा नहीं चलता था, उनकी दवाई तक नहीं आती थी। एक बुजुर्ग, एक विधवा बहन के साथ अगर वो 60 साल की एज में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको पूरा साल वेट करना पड़ता था कि कब सीनियर सिटिजन पेंशन शुरू होगी, कब वो अपनी पेंशन लगवा पाएगी लेकिन हमारी सरकार ने एक नोटिफिकेशन पास करके कि विडो की पेंशन कभी भी लग सकती है, ये एक रिमार्केबल

काम उन्होंने किया और पाँच सौ से हजार रूपये, हजार रुपये से दो हजार, आज विधवाओं को ढाई हजार रुपये तक की पेंशन मिलती है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है हमारी सरकार का और विडो के बच्चों के लिए जो शादी के लिए 20 हजार रुपये खर्चा कर दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।

माननीय अध्यक्षः तीस हजार... तीस हजार थर्टी थाउजेंड।

श्री जगदीप सिंहः तीस हजार रुपया जो कर दिया गया और साथ ही साथ दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जो किसान हैं, उनको हम लोगों ने जो मुआवजा इतना बड़ा दे के पूरे देश भर में उदाहरण पैदा किया है कि दिल्ली में कोई भी किसान जो है, खुदकुशी नहीं करेगा। तो जहाँ पर हम लोग विजय माल्या का बड़े–बड़े धनाढ्यों का जो है, लोन माफ कर रहे हैं, यहीं से दिल्ली सरकार से केन्द्र सरकार को सीखना चाहिए किस तरीके से सबसे पहले आप अपने किसानों का लोन माफ करके या उनके साथ कभी ऐसी आपदा आती है तो उनको मदद करके अगर हम लोग कर सकें तो शायद एक भी किसान जो है, खुदकुशी नहीं करेगा हमारे यहाँ पर।

और ट्रांसपोर्ट में जो हम लोग ई. बसेज ले के आ रहे हैं, ये भी एक एनवायरन्मैंट को स्पोर्टिव है। सबसे बड़ी बात हमारे उप मुख्य मंत्री ने जो पहले जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते थे, वो कहीं न कहीं कनाट प्लेस में चाणक्य पुरी में ऐसी जगहों में होते थे लेकिन आज वही पंजाबी ऐकेडमी, हिंदी ऐकेडमी और जितनी ऐकेडमीज हैं, वो गली–गली, कूचे–कूचे में प्रोग्राम्स करके अपनी संस्कृति जिंदा किये हुए हैं। ये बहुत ही तारिफे काबिल उनका

ये काम है, जो उन्होंने किया है। आज 25–25 लाख रुपया हर विधायक को उन्होंने दिया है कि आप कल्चरल प्रोग्राम्स करा सकते हैं। अपनी पूरी विधान सभाओं में कहीं पर भी किसी भी भाषा का, किसी भी बोली का प्रोग्राम कराना चाहते हो, उन्होंने हर विधायक को छूट दी हुई है और लोग वहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम होना चाहिये। मेरे यहाँ पर राजस्थान समाज के लोग बहुत सारे लोग रहते हैं। पिछली बारी उन्होंने राजस्थान पर एक प्रोग्राम करके वहाँ पर एक राजस्थान की संस्कृति को जिंदा रखा। एक बहुत बड़ी बात है। बुजुर्ग लोग कई बारी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाते उनके पास फंड नहीं होता था। जो लोग सरकारी नौकरी में थे, उनको पेन्शन मिल जाती है। जो अपना गुजर बसर कर रहे थे, वो तीर्थ यात्रा के लिये हमेशा सोचते रहते थे। हमारी सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना जो शुरू की है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही एप्रिशिएबल एक स्टेप है जो हमारी सरकार ने किया है। और आज सिक्योरिटी के लिये जो पूरी दिल्ली में डेढ़ लाख से ज्यादा कैमरे लगाये जा रहे हैं, एक हुत बड़ी बात है। हर गली कूचे में हम लोग जो हैं, एक ऐप्प लाँच करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप अपने फोन पर ही देख सकते हैं कि आपके घर में जो है, आपका घर सुरक्षित है कि नहीं। आपके घर में जो आपके बूढे माँ बाप हैं, उनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। वो आप अपने फोन से चैक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमारी सरकार ने जो किया है और मुख्य मंत्री सड़क योजना जहाँ पर जो गली मौहल्ले की सड़क जो इंडस्ट्री की सड़क कहीं पर भी जो सड़क नहीं बन पाई, वो हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री सड़क योजना को लागू करके आज सारी सड़कों को ठीक

करने का प्रावधान किया है ताकि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम न हो, कंजैशन न हो जिससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं स्पीकर साहब, लेकिन बहुत सारे लोग और भी बोलना चाहते हैं तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हुए अपनी सरकार का एक बारी और धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने इतना सारे काम करके जो है, एक लास्ट में उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पर एक बूढी माँ ने बोला कि ये मेरा बेटा योगेश है। ये 27 साल का था तब हमारे यहाँ मीठा पानी आता था नहीं तो मैं पीर बाबा की मजार से मीठे पानी को भर के लाती थी लेकिन कहती बेटा, आज तुम्हारी सरकार आने की वजह से मेरे घर पर मीठा पानी आता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जब एक बूढ़ी अम्मा हमारी इस तरीके से कहती है।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद जगदीप जी, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जगदीप सिंहः तो अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि हमारी सरकार ने वाकई बहुत सारे काम किये।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जगदीप सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे उपराज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलने का मौका दिया।

सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूँगा। आज चार साल बीत जाने के बाद और मैंने यहाँ तारीफ भी की कि भई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। पर आज बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी विधानसभा या जो साथ वाली विधानसभा है, आज भी चार साल बीत जाने के बाद बच्चे को हफते में छह दिन पढ़ने के लिये भेजते हैं। मेरी विधानसभा में आज भी तीन–तीन दिन बच्चे पढ़ते हैं, इससे ज्यादा दुःख की बात, शर्म की बात दिल्ली वासियों के लिये नहीं हो सकती। मैंने जगह की बात करी। सिसौदिया जी ने काफी उसमें सहयोग किया कि भई जगह दिला दो, हम स्कूल बनवा देंगे। हम पैसे भी दे देंगे। जगह के, हमने बगैर पैसे के... एलजी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक रुपये की लीज पर वीर सावकर हॉस्पिटल करावल नगर के अंदर स्कूल बनाने के लिये तीन हजार गज जगह उपलब्ध करा दी। आज एक साल हो गया, आज तक उसमें बड़े–बड़े होर्डिंग लगे हैं दिल्ली में आज कि 'बदले स्कूल, बदला अस्पताल और बदले बिजली पानी के हाल।' आज एक साल जगह मिलने के बाद दिल्ली में 11 हजार नये कमरों की बात तो कही जा रही है पर विधान सभा मुस्तफाबाद, करावल नगर में एक कमरा भी नहीं बन पाया उस जगह पर। इससे ज्यादा दुःख की बात अगर...

माननीय अध्यक्षः नहीं, आपके यहाँ तो लगभग सौ कमरे बने हैं।

श्री जगदीश प्रधानः सर, वो तो बन गये दो वार्डो में।

माननीय अध्यक्षः आपने कहा एक भी कमरा नही बना।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः एक सैकण्ड, मैं ये कह रहा हूँ...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीश जी, मुझे इसलिये याद है, आप मेरे कमरे में आये थे और मुझे आग्रह किया था फिर मैंने कन्फर्म किया बने या नहीं बने। आपने खुद कहा, ''बन गये हैं।''

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः 72 कमरे मेरे यहाँ बने।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिये राजेश जी, प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः सर, कमरे मेरे यहाँ बने हैं। उसके लिये मैंने धन्यवाद भी किया। यहाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जगह दिलाने की बात कही गई थी। वो जगह हमने उपलब्ध करा दी, एक रुपये की लीज पर।

माननीय अध्यक्षः हाँ, अभी छह महीने पहले उपलब्ध हुई है।

श्री जगदीश प्रधानः उसके बाद आज तक उसमें एक भी कमरा नहीं बन पाया।

माननीय अध्यक्षः अब जो नया लॉट आ रहा है, उसमें बनेंगे। मैं माननीय मनीष जी से प्रार्थना कर रहा हूँ ये नया लॉट जो आ रहा है इस साल का, उसमें जगदीश जी के यहाँ भरपूर कमरे बनवा दिये जायें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: चार पाँच स्कूल बनवा दो ना।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान: ये जगह तीन साल से बाऊंड्री वाल हुई पड़ी है। दूसरी जगह उसमें भी एक कमरा आज तक नहीं बन पाया।

दूसरा, करावल नगर विधानसभा और हमारी मुस्तफाबाद विधानसभा लगती हुई हैं। करावल नगर में आलोक कुंज स्कूल के नाम से एक स्कूल चलता है जो ऐडेड स्कूल था, उसको इसी साल डेन्जर घोषित करके बंद कर दिया गया। उसमें 2500 बच्चे पढ़ते थे; करीब 1200 लड़कियां 1300 लड़के। उनका भविष्य आज अंधेरे में है क्योंकि वहाँ से बस के साधन भी नहीं है जो दूसरी जगह बच्चे चले जायें। माँ बाप ने बच्चों को घर में रोक लिया, आधे से ज्यादा को। उनकी हालत खराब है।

तो मेरा आग्रह है कि आलोक कुंज स्कूल के पीछे भी जो कपिल मिश्रा जी का एरिया है; तीन हजार गज जगह उसमें सरकारी पड़ी हुई है। मैं शिक्षा मंत्री जी को साढ़े तीन साल पहले वहाँ लेकर गया था। वो जगह दिखाई भी थी मैंने कि आप इसमें स्कूल बनवा सकते हो। एक तरफ तो दिल्ली सरकार कहती है कि हमें जगह नहीं मिल पा रही है और जगह मिलने के बाद यदि स्कूल न बने तो वाकई में दुखदायी बात है।

जहाँ तक दूसरी बात, जो पानी की बात अभी सरदार जी कह रहे थे कि मीठा पानी मिल रहा है, आज भी मेरे यहाँ 12 कालोनियों में पाइप लाइन तो डल गई हैं। डले हुए तीन साल हो गये। उनमें एक बूंद पानी नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राजेश जी, प्लीज।

श्री जगदीश प्रधानः और भी विधानसभाओं में यही हाल है या पानी बदबूदार आता है। जिसको हम कई बार यहाँ बोतलें भर–भर के लाये। आज भी मेरी विधानसभा में और आसपास की में बिल्कुल बदबूदार पानी आ रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पानी पर कुछ किया जाये और एक मेरी सत्येन्द्र जैन मंत्री जी से एक प्रार्थना है कि भजनपुरा से लेकर दमालपुर तक जो 80 फुट का रोड छः साल पहले बन के तैयार हो गया था, एमसीडी ने बनाया था और जमना पार विकास बोर्ड से उसका पैसा मिला था, मैंने कई बार आग्रह किया, जैन साहब से और आश्वासन भी दिया। इन्होंने सर्वे भी करा दिया उसका, तो मेरी विनती है आपसे कि उसको पीडब्ल्यूडी को दिलाकर उस रोड को हमारे को बनवा दें। आप चाहें मुख्य मंत्री जी से बनवा दें, पीडब्ल्यूडी से बनवा दें। सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि बन जाये। वहाँ एक–एक फुट के गड्ढे बने हुए हैं। बसें हमारे यहाँ नहीं आतीं। गहलोत जी ने एक बस चालू कराई थी। सड़क टूटी होने के वजह से वो बस भी बंद है। हमारे यहाँ मतलब ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि सरकार जो कह रही है, कम से कम उसको 10 परसेंट तो काम करायें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राजेश जी, प्लीज।

श्री जगदीश प्रधानः मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि कम से कम हमारे कामों में ध्यान दिया जाये, धन्यवाद, जय हिंद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद, जगदीश जी। श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने माननीय उप राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया।

जैसा राखी बहन कह रही थी, शुरू से ही एलजी साहब ने कहा कि यह मेरी सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे को लगता है कि कोई आदमी कितना भी असत्य कथन सारे दिन कहे, पर दिन में कभी न कभी एक बार तो सच बोलता होगा। मुझे लगता है यहाँ जब खड़े होकर बोलकर गए या ये लगा होगा इस हाउस के अंदर जो भी बोलेंगे, उसके लिए थोड़ी सी आजादी महसूस की होगी, तो दिल की बात कह गए और वो दिल की बात में उन्होंने कहा मेरी सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। और सच मायने में ये जो दिल्ली सरकार है, ये जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा के बार में, हर चीज के बारे में जो डेवलपमेंट के काम हैं, वो उन्होंने अपने अभिभाषण में कहे भी, आगे विस्तार में भी कहें जाएँगे।

परन्तु कुछ चीजें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रतिबद्धता है जनता के कामों के प्रति, उनके कल्याण के प्रति, वो कैसे सामने एकदम प्रत्यक्ष रूप से सामने आती हैं। बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएँ सर, आती हैं, बहुत सारे स्टेटस अनाउंस करते हैं और उसके बाद एक स्टेटसमैन की तरह से बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ये जो भलाई का पैसा है, ये जो जनता के हित का पैसा है, उसमें से पाँच पैसे, रुपये में पाँच पैसे जनता तक पहुँचते है, दस पैसे पहुँचते है। पर ऐसे मंत्री नहीं मिलेंगे सर, कि जब मिनिमम वेजेज की बात आए तो एक–एक अस्पताल में जा–जाकर मंत्री देखे कि वहाँ के लोगों को मिनिमम वेजेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल

रहे। ये इंश्योर करे, ऐसे मिनिस्टर सर, और कहीं नहीं हैं, ऐसे मिनिस्टर सिर्फ दिल्ली में ही हैं।

यही एलजी साहब जो अब मेरी सरकार कहकर और मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ कहते होंगे और स्टेटस के एलजीज और गवर्नर्स से जब मिलते होंगे तो बताते होंगे कि दिल्ली में हम कितना धाँसू काम कर रहे है। ये थोड़ी बताते होंगे, हम कामों को रोक रहे हैं। पर ये जरूर बताते होंगे, ''इतना बढ़िया, देखिए, हमारे यहाँ पर स्कूल में अमेरिका से लोग देखने आ रहे हैं, हमारी मोहल्ला क्लिनिक को देखने आ रहे हैं'' ये नहीं बताते होंगे कि ये जो फाइल होती है जिसमें कि टीचर्स को रिक्रूट किया जाए, वो हमें मनीष सिसोदिया नहीं दिखाते या नए स्कूल बनाने के लिए उन्होंने कह तो दिया कि जमीन मिली हुई है। पर जमीन मिली है, अभी कुछ दिन पहले मिली है, मिलते ही पहले दिन तो उसके अंदर ईट नहीं लग सकती। 8 हजार कमरें जो अब तक बनकर तैयार हुए हैं, वो किस तरीके से हुए हैं और 11 हजार और नए बन रहे हैं। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है!

उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि इस वक्त मोहल्ला क्लिनिक; 180 कुछ मोहल्ला क्लिनिक हमारे दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। अगर साथ दिया होता तो आज दिल्ली के अंदर एक हजार मोहल्ला क्लिनिक चल रहे होते। इस बात को भाषण में उन्हें बोलना चाहिए था।

इस बात को भाषण में बोलना चाहिए था कि... अब कह रहे हैं कि 10 हजार तक बेड बढ़ाए जाएँगे सरकारी अस्पतालों में। अगर साथ दिया होता तो 10 हजार बढ़ चुके होते और और 10 हजार की हम बात कर रहे होते। अगर साथ दिया होता!

अगर एलजी साहब ने साथ दिया होता तो ये जो बसेज हैं, इस बार कह रहे है एक हजार इलैक्ट्रिक बसेज और एक हजार सीएनजी बसेज आ रही हैं और हर 15 मिनट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा लोगों को उपलब्ध रहेगी और बहुत रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये अब से दो साल पहले हो गई होती। इतना सा साथ तो देकर देखो, अपनी सरकार को। इतना सा साथ देकर देखो कि ये सरकार कितने अच्छे इंटेंशंस के साथ आई है, कितनी अच्छी नीयत के साथ आई है और कितना बड़ा काम करके देगी। सहयोग दीजिए आप इस सरकार को।

आपने सहयोग दिया होता तो डेढ़ लाख सीसीटीवी कैमरा इस साल लगेंगे, डेढ़ लाख दो साल पहले लग चुके होते। आज चार–साढ़े चार लाख कैमरे की बात कर रहे होते हम दिल्ली के अंदर।

दिल्ली को, जो इन्कम टैक्स जमा होता है दिल्ली की तरफ से, पूरे देश में शायद सबसे ज्यादा जमा होता होगा, उसमें से 325 करोड़ रुपये मिलते हैं। अगर ये बात जाकर केंद्र में उठाई होती और दिल्ली को उसका हक मिल रहा होता तो आज की तारीख में विकास चौगुणा हो रहा होता दिल्ली के अंदर।

आज दिल्ली के अंदर मैट्रो फेज–4 के लिए जब बात करते है तो ऑल्मोस्ट 10 हजार करोड़ रुपये दिल्ली सरकार देगी। इन मैट्रो रेल्स, जितनी भी, जहाँ पर भी बनी हैं, फेज–1, फेज–2, फेज–3 इनके ऊपर से एलिवेटेड कॉरिडोर्स जाएँगे, जिससे कि ट्रैफिक जाम्स में हम लोगों को बहुत राहत मिले, उसके पैसे दिल्ली सरकार देगी। ये सब काम हो चुके होते। आप साथ तो देकर देखिए।

एक साल बचा है, एक साल साथ देकर देखिए एलजी साहब! एक साल साथ देकर देखिए एलजी साहब। जिस चीज को, ये जो छोटी सी किताब जो चार साल में पढ़ी है, ये अगले साल, एक साल आप साथ देकर देखिए, चौगुणी मोटी होगी ये किताब, चौगुणी मोटी होगी ये किताब हम लोग बहुत सहनशीलता के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में, चार साल से संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की ऊर्जा ये जो जनता का इस सरकार के अंदर विश्वास है, तो यही वजह है कि ये सहनशीलता और ये धैर्य हमारे अंदर है कि कामयाब तो हम होंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में जब बात करते है तो शिक्षा के लिए इतना काम हुआ है, शिक्षा के अंदर दिल्ली के अंदर कि उसको बता पाने के लिए मुझे लगता है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बहुत कम हैं। अस्पतालों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। जब हम किसी भी एक समाज की बात करते हैं और पूरे समाज के उत्थान की बात करते है तो सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, उस समाज में किस तरीके से शिक्षा मिल रही है, किस तरीके से स्वास्थ्य घर–घर तक पहुँच रहा है, उसके बारे में बात होती है। माननीय प्रधान मंत्री जी भी अपने भाषणों में आजकल कहने लगे हैं कि उनका सपना है कि हर घर में शिक्षा पहुंचे, हर घर में स्वास्थ्य पहुंचे। वो कहने तो लगे हैं। उन्होंने उसकी इम्पोर्टेन्स देखी है। अब इम्पोर्टेन्स देखिए, समृद्धिता की।

दिल्ली के ये विकास कार्य ही हैं कि 11 परसेंट आदमी की इन्कम के अंदर ऑन ऐन एवरेज बढ़ोत्तरी हुई है। कुछ तो होगा दिल्ली के अंदर! कुछ तो काम ऐसा हो रहा है कि हर चीज में बढ़ोत्तरी हो रही है और

पॉजिटिविटी है। क्यों कोशिश कर रहे हैं एलजी साहब नेगेटिविटी फैलाने की? कितनी लम्बी जिदंगी होती है आदमी की और किस नाम से जाने जाना चाहते है वो? कि जिसने दिल्ली के विकास को रोका या एक एलजी ऐसा आया दिल्ली के अंदर जिसने अपने कार्यकाल में केंद्र के गुंडागर्दी को साइड लगाकर और दिल्ली की जनता के विकास के लिए, दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर काम किया। ये उनको तय करना है। कोशिश तो करके देखें, दिल्ली के विकास के लिए किस तरीके से काम करना है।

हमारी सरकार ने, इस जनता की सरकार ने दिल्ली के अंदर चुनी गई आम आदमी की सरकार ने हर क्षेत्र में सर, काम किया। चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'तीर्थ यात्रा योजना' की तो बात करी, पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये भी बता दूँ कि पेन्शन जो एक हजार होती थी; 60 से 69 साल तक के लोगों के लिए, उसे एक हजार रुपये और बढ़ाकर सर, 2 हजार किया, जिनकी डेढ़ हजार होती थी 70 साल के ऊपर, उनको ढ़ाई हजार किया। जो विधवा हैं, उनकी पेंशन डेढ़ हजार से ढ़ाई हजार करी और उसमें एक और चीज जोड़ी, सर कि पहले 60 साल की उम्र तक विधवा पेंशन होती थी और उसके बाद वृद्ध पेंशन होती थी, वृद्धा पेंशन के एक लिमिटेशन होती है, वो हर साल एक सीमित नम्बर होता है जो कि हर विधान सभा को मिलता है, पर उसमें से हटाकर, विधवा पेंशन, उसमें से हटाकर, विधवा पेंशन की ऐज लिमिट हटा दी गई जिससे कि बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जो इसका लाभ ले पा रही हैं। ऐसे ही विकलांग पेंशन थी, विकलांग पेंशन भी डेढ़ हजार से उठाकर ढ़ाई हजार की गई और उसमें भी ऐज लिमिट थी 60 साल तक की, उसकी भी ऐज लिमिट

हटाई गई सर, और उसको भी, विकलांगों को जो है, अब वृद्ध पेंशन की कोटा की और लिमिट की वेट नहीं करनी पड़ती, वो कभी भी अप्लाई कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। सुनने में बड़ा छोटा सा जेस्चर है पर जिसके ऊपर बीतती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा जेस्चर है। इतनी सी बात ये दर्शाती है कि दिल में हर एक के लिए पीड़ा लेकर चलती है ये सरकार। हर एक की पीड़ा को छूती है ये सरकार। समझती है ये सरकार। महसूस करती है और उसके लिए काम करने की कोशिश करती है। हमें काम करने दो। हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएँगे। सहयोग करो, कोशिश करो कि ये जो काम हो रहा है, इसको बढ़ाओ, ये एलजी साहब से गुहार है। एक बार कोशिश तो करके देखें। जिस चीज के लिए भेजा गया है, वो न करते हुए, जिस चीज के लिए कुर्सी बनी है, उस कुर्सी का सम्मान करें।

हमारे यहाँ पर सर, 'जहाँ झुग्गी, वहीं मकान' का एक हम लोगों ने ये बात शुरू की थी। बहुत सारी सरकारें बहुत जगह पे इस तरीके की बातें करती है। हमेशा ऐसा होता है कि झुग्गी वालों को कहा जाता है कि यहाँ से झुग्गी हटेगी, उन्हें इतनी दूर भेज दिया जाता है लेकिन न तो वहाँ पे उनको किसी तरीके का रोजगार मिलता है और जो आस–पास के घर होते हैं, वहाँ पे भी उन घरों में भी जिनके यहाँ पे वो काम करते हैं, उनके साथ भी परेशानी होती है। हम लोगों ने काफी इस चीज के ऊपर काम किया और इस सरकार को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर, एक हजार से ज्यादा आवास आबंटित किए गए हैं। ऑलरेडी, साढ़े पाँच हजार से ज्यादा बहुमंजिली ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण किया जा रहा है और

कई जगहों पे लॉटरी लगा के फ्लैटस का ड्रॉ निकाला जा चुका है और कोशिश की जा रही है कि पाँच किलोमीटर से ज्यादा दूर लोगों को न भेजा जाए, वहीं रहें जिससे कि उनका रोजगार भी बना रहे और जहाँ पे भी वो जाते हैं तो उनके बच्चों का एडमिशन... सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कल को यहाँ पे झुग्गी तोड़नी है, यहाँ से उठाया ओर उनको दूर भेज दिया; नरेला भेज दिया, लक्ष्मी नगर से उठाके कहीं भेज दिया। न वो अस्पातल की वहाँ पे सुविधा हो, न बच्चों के एडमिशन की सुविधा हो। इन चीजों को देखते हुए कर रही है ये सरकार। इसको अगर सोच के देखें, दिल्ली में जहाँ पे लैंड की इतनी कमी है।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए प्लीज, नितिन जी।

श्री नितिन त्यागीः सर, कर रहा हूँ सर, अभी। यहाँ लैंड की इतनी कमी है वहाँ पे भी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इतनी लिमिटेसंस के बाद में अगर ये सरकार काम कर रही है तो कितनी संजीदगी होगी, एक–एक नागरिक के प्रति। हम लोगों को लैंड दिलवाने में अगर एलजी साहब थोड़ी सी मदद करें, वो चेयरमेन हैं डीडीए के, बहुत बार मैंने बग्गा जी ने, बहुत लोगों ने, हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, वहाँ पे अस्पताल बनाने के लिए। आज तक हमें लैंड नहीं मिला सर, वहाँ पे। बल्कि उसी लैंड को जो हम लैंड अस्पताल के लिए माँग रहे थे उसको कूड़े का खत्ता बनाया गया, जहाँ हम लोगों को आंदोलन करके वो कूड़े का खत्ता वो रैजिडेंसियल एरिया में से हटवाना पड़ा। इस तरीके के मजाक जनता के साथ न किए जाएँ। जनता ने बहुत प्यार से, बहुत विश्वास से इस सरकार को चुना है। एलजी साहब से बहुत छोटा सा आग्रह है हाथ जोड़के प्रार्थना है कि मेरी

सरकार जब बोलतें हैं तो सच्चे मायने में, मेरी सरकार मान के चलें और इस सरकार का साथ दें, जनता का साथ दें। ऐसे तो बहुत बार पॉलिटिकल व्यंगयता के तरीके से आपको इस्तेमाल किया जाएगा, एक बार इंसान के तरीके से भी काम करके देखें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद, राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि आपने बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं– 'एक माँ तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है।' मेरा अक्सर मानना है कि ऐसी माँ अक्सर सोतेली माँ होती है, क्योंकि जो अपनी माँ होती है, उसको तो इस बात का इल्म होता है कि बच्चे को कब खाना खिलाना है, कब उसकी देखभाल करनी है, रो क्यों रहा है, वो ज्यादा क्यों सो रहा है, वो कम क्यों सो रहा है। लेकिन जो सौतेली माँ होती है, माँ तो होती है लेकिन उसमें वो अपनापन नहीं होता। कल जब एलजी साहब यहाँ पे आए उन्होंने अपना, वो बैठे, बोलना शुरू करा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई 60–70 साल पहले शायद कोई रानी विक्टोरिया आए, बैठे, जिस देश से, जिस मुल्क से उनका लेना–देना न हो और उसके बारे में बात करें। न चेहरे पे कोई मुस्कराहट, न कोई खुशी कि मैंने कुछ काम करा है या मेरे लोगों ने कुछ काम करा है या मेरी सरकार ने कुछ काम करा है। न तकलीफ कि कुछ काम रह गए हैं जो मुझे करने चाहिए थे या मैं नहीं कर पाया, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सब साथियों ने देखा होगा विडियो की पूरी रिकोर्डिंग है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ पढ़ दिया। उनको कोई दुःख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं,

कोई कुछ नहीं। आपने खाने की व्यवस्था करी थी, बहुत अच्छा होता कि वो भी हमारे साथ में बैठते। लेकिन ठीक है हम बहुत छोटे लोग हैं लेकिन हमारे साथ बैठते, बात करते, मैं कहता हूँ कोई काम न करें वो, लेकिन बैठें जनता के प्रतिनिधियों के साथ बैठें, जनता के साथ में बैठें, जरा देखें जनता की क्या अपेक्षाएँ हैं। जब वो अपनी सरकार कह रहे हैं तो जनता की अपेक्षाएँ क्या हैं, या तो उनके प्रतिनिधियों के जरिए जो हम लोग हैं या डॉयरेक्ट जनता से जानने की कोशिश तो करें कि जनता चाहती क्या है। मुझे तो सच बताऊँ इस शब्द में ही आपत्ति है कि 'मेरी सरकार है।' हिन्दुस्तान एक गणतंत्र है, जनतंत्र है इसमें मेरा क्या? जब संविधान भी कहता है हम भारत के नागरिक तो मेरा कहाँ से आ गया? ये किसी व्यक्ति की कोई सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है, ये जनता ने चुना है किसी को। मेरी सरकार नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि ये लिख के भेज दीजिए आगे से कि मेरी न कहें बल्कि कहें कि जनता की सरकार ने ये काम करे जब जनता चुनती है तो। जो बातें इस किताब में लिखी हुई है हम सबने पढ़ी, एल जी साहब ने जो बोली। दरअसल ये वो बातें हैं जो अगर आप किसी विरोधी से, किसी दुश्मन से भी पूछेंगे तो वो भी उसके ऊपर मोहर लगा देगा कि हाँ भई, ये सब तो हुआ है। आपने पिछले साल हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री जी से सुना होगा आउटकम बजट, परिणाम। दरअसल ये सब चीजें जब हुई हैं, इनका परिणाम क्या रहा? बहुत आराम से ये बात होती हैं कि बहुत सारे क्लॉसेज बनें, नर्सरी क्लॉसेज वहाँ चालू हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ ही नहीं पाते थे, जो प्राइवेट स्कूलों में भागना पड़ता था, ये छः

साल तक की उम्र तक का इंतजार करते थे। ये एमसीडी स्कूलों में धक्के खाने भागते थे, नर्सरी क्लॉसेज तो वहाँ भी होती हैं, लेकिन आज उस बच्चे को इस प्राइवेट स्कूल के बच्चे की तरह वो मौका मिल रहा है कि वो नर्सरी में जब उसकी पहली शुरूआत है, वो जाके वो भी स्कूल को महसूस कर सके, वो भी जो पहली सीढ़ी है उसकी पढ़ाई की, उसपे जा सके। स्कूल सिर्फ नहीं है उसमें स्वीमिंग पूल्स हैं, कभी सोचा था किसी ने, पुस्तकालय! ये शुरूआत में ही जब बच्चे को आदत पड़ेगी, वो किताब पढ़ेगा, न सिर्फ वाट्सएप्प वो जहर पढ़े जो आजकल डाला जा रहा है। नए स्टेडियमस बनाए हैं, स्केटिंग ग्राउंडस, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलस में भी स्केटिंग ग्राउंडस नहीं हैं, लेकिन माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जिन्हें मैं बार–बार कहता हूँ कि हिन्दुस्तान के एकमात्र शिक्षा मंत्री है बाकी सब प्राइवेट स्कूल मंत्री हैं। उन्होंने वो ऐसा स्टेडियम बनाया जिसमें पिछले साल आठ बच्चे, सॉरी इस साल 8 बच्चे नैशनल के मैडल्स जीत के आए। स्केटिंग का ग्राउंड है जो दूर–दूर तक... उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए फ्री है, बाकी जो बच्चे आएँ, उनके लिए 200 रुपए है, वो बच्चे स्केटिंग कर पा रहे हैं जो पहले चलने में भी, इनको कोई पूछता नहीं था, इनके पास जूते नहीं थे, आज इनके पास में स्केटिंग की चीजें है। ऑडिटोरियम उन्हीं स्कूलस के अंदर, सिर्फ स्कूल्स के कमरों की बात हम बार–बार करते हैं, शानदार ऑडिटोरियम्स, जो साउंड प्रूफ हैं, ऐसे ऑडिटोरियम बने हैं जिनमें बच्चे जब प्रोग्राम करते हैं एनुअल डेज पे, सभी साथी विधायक आप, हमारे विपक्ष के साथी जाते होंगे, इतनी दिल को खुशी होती है, क्योंकि एक–दो बच्चों को तो सभी पढ़ाते हैं, सबके हैं, हमारे छोटे हैं, प्रधान जी के पोते–पाते

हो गए होंगे। लेकिन आज जो मौका मिल रहा है पाँच हजार बच्चों को, 10 हजार बच्चों को, 15 हजार बच्चों को पढ़ाने का। तो माननीय मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी, बहुत–बहुत धन्यवाद। एक ऐसा महसूस होता है कि हम छोटे बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं जो पहले सिर्फ गलियों में ऐसे घूम रहे थे, उनको आज ऑडिटोरियम में खेलने का, कूदने का, नये–नये प्रोग्राम्स करने का, योगा करने का बहुत अच्छे–अच्छे मौके मिलते हैं, दुनिया भर के वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मेरे अपने यहीं से दो बच्चे इस बार, एक बच्चा अभी अमेरिका गया हुआ है। झुग्गियों में रहता है वो बच्चा, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। अखबारों में लिखा आया, हिन्दुस्तान का हुसैन बोल्ट, झुग्गियों का बच्चा है। सिर्फ कमरों की बात नहीं है ओवर ऑल व्यवस्था, ओवरऑल विश्वास, वो प्रिंसिपल जो लड़ते रहते थे, सोचते थे हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम क्यों पढ़ाएँ बच्चों को? हमारी तो पक्की नौकरी लग गई, आज वो प्रिंसिपल्स कैम्ब्रिज होके आते हैं, ऑक्सफोर्ड होके आते हैं, वो सिंगापुर होके आते है। ये विश्वास उन टीचर्स को देना कि तुम्हारे को एक स्कूल नहीं दिया हुआ, दीवार नहीं दी, देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में दिया हुआ है। आपको इसको संवारना है, तो दीवारें नहीं हैं स्कूल, वो कमरे क्या हैं? क्या होता है कमरा? कमरे तो यहाँ भी है, वो स्कूल, वो देश की बुनियाद है, वो उनको दी गई है, उनको विश्वास दिलाया है, मनीष सिसोदिया जी ने कि ये तुमको सौंप दिया, तुमने देश का भविष्य बनाना है, हमें दुनियाँ की कतार में सबसे आगे आके खड़ा होना है और ये बच्चे लेके जाएँगे। किसी को भी, कोई सरकार किसी को कोठी बंगले में नहीं पहुँचाती, वो सपने जो उनके माँ–बाप ने देखें हैं, वो बच्चे पूरे करेंगे उनके।

और बच्चे तो ऐसे पूरे करेंगे जब उनको स्कूल मिलेंगे, जब उनको पढ़ाई का माहौल मिलेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ उसके लिए मनीष जी को, जितने दिए जाएँ, वैसे तो कम है।

दूसरी बात उन्होंने की होस्पिटलस की, मोहल्ला क्लीनिकस की। एक मोहल्ला क्लीनिक में जो अभी तक 180 चालू हैं, ऑन एन एवरेज 70–80 से लेके 110 तक आदमी आता है। सारे टैस्ट फ्री होते हैं 25 हजार तक के टैस्ट फ्री हैं। बहुत आसान है ये कह देना कि सारे टैस्ट फ्री हैं, सारी दवाइयाँ फ्री हैं। ये आसान काम नहीं है। पहले इनमें बहुत कम दवाइयाँ होती थीं। मैं आपको अभी बता दूँ मुश्किल से 100 दवाइयाँ थी जो जनरल ड्रग्स के अंदर आती थी, जिनको हमारी सरकार से पहले दिया जाता था। आज उसको बढ़ाके 1500–2000 के करीब ले आया गया है, जो फ्री दवाई हम दे रहें हैं लोगों को और उसमें लगातार लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छे–अच्छे घरों के लोग आते हैं मोहल्ला क्लीनिक में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब आदमी आ रहा है, फ्री के चक्कर में। एक स्टैंडर्ड है। उसमें लोग आते हैं और लगातार भीड़ लगी रहती है, लोग बहुत खुश होते हैं और इसीलिए इतनी डिमाण्ड है कि और बना दो और बना दो, और बना दो। हॉस्पिटलस... दिल्ली में लोग कहते हैं कि हॉस्पिटलस में बड़ी भीड़ है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, दिल्ली के आसपास किसी भी राज्य के पास में सरकारी अस्पताल नाम का भी नहीं है। यहाँ से ले के आप चंडीगढ़ तक जाएँगे, बीच में सरकार अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है। हालात ये बन जाते हैं कि हरियाणा के अंदर एक बच्ची नर्सरी के अंदर झुलस जाती है तो माननीय मुख्य मंत्री दिल्ली सरकार को एक मैसेज लिखना पड़ता

है कि ट्वीट के ऊपर कि हमारे विधायक यहाँ से उठके जाएँ और उसका इलाज जा के चंडीगढ में करा दें या दिल्ली लेके आ जाएँ। इतनी खराब हालत है। यहाँ से मेरठ तक जाइए, कोई सरकारी अस्पताल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जयपुर तक जाइए, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। जिसकी वजह से सबको दिल्ली आना पड़ता है। ये कहते हैं कि दिल्ली में भीड़ हो रही है। कौन करवा रहा है? ये सरकारें वहाँ पे क्या कर रही हैं? लेकिन हमने इस बात को ध्यान में रख के कि इन अस्पतालों में भीड़ कैसी हो, थ्री टियर सिस्टम बनाया। एक मोहल्ला क्लीनिक उसके ऊपर पॉलीक्लीनिक और उसके ऊपर हॉस्पिटल। जिसके पेट में हल्का सा दर्द है, हल्का सा जुकाम है, उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत न पड़े, वहाँ पे भीड़ न हो।

अभी जगदीश प्रधान जी बार–बार कह रहे थे कि मेरे यहाँ स्कूलों की दिक्कत रही, लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमने पॉलीक्लीनिक्स बनाएँ, पूरी दिल्ली में केवल 20 बनाए। 70 विधायक थे, 67 उस वक्त हमारे थे। लेकिन फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि जाकर एक हम विपक्ष के नेताजी के यहाँ पर खोलें और हमने खोला उस पॉलीक्लीनिक को जो इनके यहाँ पर खोला। जितनी भी चीजें बाकी चीजें मेरे बहुत सारे साथियों ने बताई। हायर एजूकेशन के लिए वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर अभी छः का उद्घाटन करा। लेकिन उस दिन क्योंकि हमारे जवान साथी मारे गए थे तो हमने उस तरीके से मनीष जी ने उद्घाटन नहीं करा। लेकिन लोगों को सौंप दिया और हालात ये थे कि ऑनलाइन उसके अंदर एवरीथिंग और लगभग सारी सीटें अभी से

ही फुल हो गई और वहाँ पर बात हो रही थी कि अगर मार्च में ही अब ये फुल हो गई हैं तो दोबारा जब हम सितम्बर में निकालते हैं तो जब तो जगह मिलनी नहीं है। इतनी जबरदस्त चीजें बच्चे टाई लगाकर उसमें आ रहे हैं। 42 हजार रुपये केवल फीस है और तीन महीने की स्कॉलरशिप है। हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट और सरकार से लोग चाहते क्या है? क्या कमी रह गई सरकार के पास में? मैं कभी–कभी सोचता हूँ कि एक रोल मॉडल की तरह सरकार है। किसी को छोड़ा नहीं; चाहे एससी/एसटी फंड है जो आता ही नहीं था पहले। आज आप देखिए सबकी विधान सभा में लगा हुआ है। पेन्शन की बात मेरे साथियों ने बता दी। झुग्गियों की जगह मकान आप देखें इतने शानदार बन रहे हैं। मेरी अपनी विधानसभा में 11 मंजिल के मकान! कभी किसी ने ऐसी चीजों को सोचा नहीं था। सीधे सिस्टम के बारे में कल उन्होंने बात करी। 69 में मेरे यहाँ सीवर डले थे 1969। जो आदमी 1969 में पैदा हुआ उसको 10 बीमारियाँ लग जाती हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से सिस्टम जो पूरा खत्म हो गया था। जिसके अंदर आज टॉर्च मारो तो आर–पार कुछ नहीं जाता।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ताः और सर, पाँच मिनट दीजिए। उसके अंदर ये हालात थे कि आज उसको तकरीबन 65 करोड़ की लागत से मेरी और मेरे आस–पास की चार विधान सभाओं के लिए उस सिर्फ चार के लिए ही काम हो रहा है। पूरे सिस्टम को जैपनीज टैक्नीक से चेंज किया जा रहा है ताकि रोड पर बड़े खड्डे न हों क्योंकि उस पर बसें निकलती हैं और रोड बंद हो जायेंगे और उसके अंदर आस्ट्रेलियन पाइप डाले जा रहे हैं

कि कभी उसके अंदर कुछ जाम ही न हो, कोई तकलीफ ही न हो। कहना बड़ा आसान है कि क्या होगा, क्या करा सरकार ने सीवेज तो नीचे दिखाई देता है। लेकिन जिनके घरों के अंदर गंदगी भरती है लोग पूजा–पाठ की बात करते थे; घर में गंदगी होगी तो वो कहाँ से पूजा करेगा? ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो सारी चीजें वो हैं, जो हमारे दुश्मन भी इस बात को मानेंगे कि भई, होती रही हैं–होती रहेंगी।

मेरा आपके माध्यम से एक अनुरोध है कि जब कभी भी कोई भी बात करे मेरी सरकार, अपनी सरकार उसमें अपनापन जरूर हो। उस बात को जरूर वो ध्यान रखें; मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। एक बात एमएलए फंड को जो बढ़ाया गया, उसमें भी मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी वजह रही कि कुछ काम उसके बावजूद भी अटकते थे, नहीं हो पाते थे, टेंडर नहीं हो पाते थे, लेते नहीं थे लोग। तो उसको एमएलए फंड को बढ़ाया गया ताकि आप अपनी मर्जी से क्योंकि आपकी मर्जी जनता की मर्जी है। जनता ने आपको चुना है। तो जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो जो चाहे वो आपसे करवा सके। तो मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बोलने के लिए कहा।

एक बात मैं जरूर कहूँगा कि क्योंकि हमारे साथियों ने बड़ी खूबसूरत टी–शर्ट्स पहनी हुई हैं। जिस पर लिखा हुआ है, 'नमो अगेन।' मैं बताना चाहता हूँ कि हिन्दी में जब हम कहते हैं नमो तो हमारी पूजा के लिए हम हिन्दू धर्म के लोग हैं। नमो हिन्दी में पूजा का माध्यम है। लेकिन जब इंगलिश में नमो लिखते हैं तो वो नमो नहीं पढ़ा जाता, न मो होता है न,

कभी नमो नहीं होता, पढ़ लीजिएगा। 'मे' होता है 'मे' क्योंकि सिलेबस ट्रेस इंगलिश में एक ही जगह पर आता है सर, और कभी लास्ट में नहीं आता। एल्टी में... पेनल्टी में प्रूव होता है। इंगलिश के अंदर तो न मो है थैंक्यू वेरी मच।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, इस सदन की इस अभिभाषण में रूचि और चर्चा, रूचि और इस अभिभाषण से जुड़ाव। इसी बात से सुनिश्चित हो जाता है कि सुबह कोरम के अभाव में ये चर्चा आधा घंटा देरी से हुई और विपक्ष बहुत कम है। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष के चारों सदस्य यहाँ उपस्थित थे और जिस पार्टी के सदन में 70 में से 66 सदस्य हों और वो हर सत्र में कई बार कोरम के अभाव में बैठक को स्थगित करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सदन का और क्या हो सकता है। अब कई सदस्य मुझसे कहते हैं अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे भई! अजय दत्त जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मुझसे कहते हैं, बिना मैं उनका नाम लिए ये कहूँगा, वो सैटायर करते हैं अपने लोगों पर ही कि भाई साहब, ये तो आप लोग जब सदन में होते हो तो फिर भी कोरम पूरा हो जाता है। अगर आप सदन से बाहर चले जाते हो तो कोरम पूरा करना और भी मुश्किल होता है क्योंकि सदन इतना उबाऊ हो जाता है, इतना नीरस

हो जाता है। कल इसी प्रकार का नीरस अभिभाषण उपराज्यपाल जी ने दिया। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती खड़े हैं, क्यों बोल रहे हैं? उससे उनका कोई नाता नहीं है। वो जो पढ़ रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, समय खराब हो रहा है। राजेश जी, समय खराब होगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उससे वो खुद ही कन्विंस्ड नहीं हैं। अभी इस अभिभाषण में आपने लिखा हुआ है कि हमने चौथे फेज की मैट्रो को मंजूरी दी है। ये तो उपराज्यपाल साहब भी जानते हैं कि कितने साल... चार साल चौथे फेज की मैट्रो को जान–बूझकर दिल्ली की सरकार ने रोका। इसकी जाँच होनी चाहिए, इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। सरकार श्वेत पत्र... मैं तो कहूँगा उपराज्यपाल महोदय...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं ना, उत्तर देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उपराज्यपाल महोदय से माँग करूँगा जो अभिभाषण आपने पढ़ा है, इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए; दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी हमारे सदस्य नादान हैं। मैं समझता हूँ जिन्होंने इस अभिभाषण पर उप राज्यपाल को ये कहकर कि भाषण तो हमारा है, सरकार तो हमारी है। लेकिन रूलबुक देखेंगे, आप एनसीटी एक्ट देखेंगे,

भारत का संविधान देखेंगे, संसदीय प्रणाली देखेंगे, परम्पराएँ देखेंगे तो ये भाषण लिखकर दिया था मनीष सिसोदिया जी ने। ये भाषण लिखकर दिया था मनीष सिसोदिया जी कि सरकार ने और केजरीवाल जी सोये हुए थे, उन्होंने सब कुछ मनीष जी को सौंप रखा है। उन्होंने कह रखा है कि आप ही सरकार चलाओ मेरे बस की सरकार चलानी रही नहीं है। तो ये लिखकर दिया है उन्होंने। अगर इसमें फुलस्टॉप और कोमा भी उप राज्यपाल हटाना या जोड़ना चाहें तो उसकी इजाजत मनीष सिसोदिया जी ने दी नहीं थी। क्योंकि इसमें कई मामले ऐसे आए जो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे, विज्ञापनों में नजर आ रहे हैं। आज विज्ञापनों से अखबार भरे पड़े हैं। रोजाना 4–4 पेज के फुल विज्ञापन और किसी अखबार ने 4 लाइन कम छाप दी तो उसके विज्ञापन रोक रहे हैं। मुझे मालूम है कोई अखबार मेरे विज्ञापन पर हो रहे अंधाधुंध खर्च पर जनता के खून–पसीने की कमाई पर जो व्यर्थ किया जा रहा है, एक शब्द नहीं लिखेगा। क्योंकि सरकार भी जानती है कि अखबार वालों की दुखती रग है विज्ञापन। उसको दबाओ, हाथ मरोड़ो और विज्ञापन...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः विज्ञापन के आधार पर नियमित पेजों में भी अपनी जगह सुनिश्चित करो।

लेकिन ओ.पी. शर्मा जी... सुनो आप, अपनी जगह सुनिश्चित कर ली तो ठीक है लेकिन विपक्ष की भी जगह ये तय कर रहे हैं कि भैया, चार

लाइन से ज्यादा मत छापना विपक्ष का। अगर विपक्ष की चार लाइन से ज्यादा छाप दी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अवसर है उनका बोलने का प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर विपक्ष के सदस्यों की विजेन्द्र गुप्ता की या ओपी की या मनजिंदर जी की या जगदीश जी की हेडिंग लगा दी चलते सत्र में तो तुम्हें हम देखेंगे। कई तरह से देख सकते हैं, कई तरह से देखे जा रहे हैं अखबार वाले, कई तरह से इमरजेंसी लगाई जा रही है ऐड बंद भी हो जाती है, ऐड बढ़ भी जाती है और ऐड के साथ कुछ और भी चीज जुड़ जाती है। कई तरह के मामले दर्ज हो जाते हैं, वो सब लोग जानते हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन इस पूरे–पूरे चार साल में एक अनधिकृत कालोनी नियमित नहीं की गई है। एक कालोनी नियमित नहीं हुई है। एक झुग्गी बस्ती को इसमें लिखा गया, 'जहाँ पे झुग्गी, वहीं पे मकान।' एक भी झुग्गी बस्ती पर उनको मकान बनाकर नहीं दिए गए हैं। एक झुग्गी वाले को मकान नहीं दिया गया है बल्कि 14 हजार झुग्गी वालों के जिनके पैसे जमा हैं 70–70 हजार रुपये छः साल से उनको भी बने हुए फ्लैट जर्जर हो रहे हैं, वो फ्लैट तक देने को सरकार तैयार नहीं है। झुग्गी वाले अदालत में जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। कोर्ट में सरकार के विरूद्ध केस दर्ज कर रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं कि हमने पैसा दिया है। मकान बने हुए खड़े हैं, आप वो मकान हमको क्यों नहीं देते? लेकिन अभिभाषण में बड़े–बड़े दावे एक रिसेटलमैंट कालोनी को,

किसी एक नागरिक को एक पुनर्वास बस्ती में मालिकाना हक नहीं दिया है। अगर दिया है तो सरकार... सदन चल रहा है, 66 सदस्य हैं आपके, आप बता दीजिए कौन–सी अनाधिकृत बस्ती को नियमित किया है, बता दीजिए? कौन–सी पुनर्वास बस्ती पे मालिकाना हक दिया है, बता दीजिए? कौन–सी झुग्गी बस्ती को... आप 'जहाँ पे झुग्गी, वहीं मकान' दे रहे हैं? लेकिन अभी यहाँ पर मैंने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वो आप लगा रहे हो और यमुना को स्वच्छ कर रहे हो। अब उस कार्यक्रम में तो मैं भी था। आदरणीय मुख्य मंत्री जी भी थे और आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी भी थे और भारत सरकार के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी थे। भारत सरकार का वो कार्यक्रम था। 1700 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने दिल्ली के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए और उनके विस्तार के लिए जीर्णोद्धार के लिए और यमुना को मेला होने से बचाने के लिए 100 प्रतिशन 1700 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। लेकिन इस अभिभाषण में जो झूठ का पुलिन्दा है, जो सच से कोसो दूर है, एक शब्द केन्द्र सरकार के पक्ष में यहाँ पर लिखा नहीं गया। मैं पूरे पन्ने बार बार पलटता रहा, मैंने कहा, शायद कहीं गलती न हो जाए क्योंकि अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बोलूँगा और मुझसे कोई गलती में कोई सूचना गलत यहाँ आदन–प्रदान हो जाएगी तो पूरे का पूरा सत्तारूढ़ दल मेरा वो एक शब्द पकड़ लेगा। लेकिन इसमें, इस पूरे उसमें सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्प पर कोई संकल्प नहीं लिया। क्या अब आपका मुद्दा नहीं रहा भ्रष्टाचार? क्या भ्रष्टाचार सारा सामप्त हो गया है? अब कॉंग्रेस के पीछे–पीछे

आप घूम रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। जिसकी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नाम पर आप सत्ता में आए, जिस शीला दीक्षित को 370 पेज की रिपोर्ट लेकर केजरीवाल जी सड़कों पर घूमते थे कि मुझे पॉवर दो, मैं जेल में भेजूँगा।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए विजेन्द्र जी कन्क्लूड।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार।

माननीय अध्यक्षः समय पूरा हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः भ्रष्टाचार इस सरकार में फल–फूल रहा है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः भ्रष्टाचार इस सरकार में।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मेरी बात समझ लीजिए, एक मिनट में कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः भ्रष्टाचार।

श्री ओमप्रकाश शर्माः थोड़ा तो समय दे दो।

माननीय अध्यक्षः भई 12 मिनट हो गए भाई, 12 मिनट किसी कोई इतना समय नहीं दिया अब तक।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः भ्रष्टाचार लगातार इस सरकार में बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार निवारण का कोई संकल्प कोई कमिटमेंट इस सरकार में दिखाई नहीं देता। न कोई कार्यक्रम हमारे सामने है। हाँ, यहाँ कहा गया हमने बिजली की कीमतों को कम किया है। मैं अभी आगे समय आएगा जब वित्तमंत्री

बजट पेश करेंगे और भी मौके आएँगे अपनी बात कहने के। मैं आपको विस्तार से बताऊँगा किस तरह बिजली कम्पनियाँ दिल्ली के लोगों को लूट रही हैं और सरकार के आशीर्वाद से लूट रही हैं। सरकार संरक्षण में लूट रही हैं। फिक्स चार्जेज, हममें सब जानते हैं। पिछले वर्ष जब यहाँ पर जुलाई के महीने में शायद जब नया टेरिफ आया था, हमने टेरिफ को देखते ही बता दिया था दिल्ली के लोगों पर बड़ी मार पड़ने वाली है। फिक्स चार्जेज के नाम पर अध्यक्ष जी, 6–6 गुणा लोगों से पैसा जबरन वसूली की जा रही है। वो फिक्स चार्जेज बिजली, बिजली की जो खपत है, उसके अगेंस्ट नहीं हैं। बिजली की कीमत पूरे देश में गिर रही है, बिजली का उत्पादन पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है आज देश में मोदी सरकार ने जिस तरह बिजली के पूरे क्षेत्र में एक कैरिस्मेटिक एक करिशमाई बदलाव किया है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दिल्ली के अन्दर फिक्स चार्जेज के नाम पे।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी, कन्क्लूड करिए प्लीज, भई।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बिजली कम्पनियों को 6–6 गुणा हजारों करोड़ अतिरिक्त दिया गया है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं अंत में, मैं अध्यक्ष जी का अनुरोध स्वीकार करते हुए, उनकी बात को मानते हुए, उनके आदेश का पालन करते हुए अपनी बात को सामप्त करूँगा लेकिन ये जंग जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी के

खिलाफ जनता के बीच में जाएँगे और जाकर के बताएँगे कि किस तरह से झूठ की बिसात पर ये सरकार चल रही है, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई महेन्द्र जी, अब नहीं प्लीज। नहीं, देखिए समय आधा घण्टा सदन का खराब हुआ है, वो आप लोगों का कटा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूँगा, प्लीज। मैं आज बहुत सख्त नाराजगी है। बहुत ज्यादा सख्त नाराजगी है। नहीं, मैं कुछ नहीं। माननीय मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय मैं माननीय उप राज्यपाल महोदय, श्री अनिल बैजल जी के अभिभाषण के ऊपर जो चर्चा हो रही है, उसमें शामिल होने के लिए सभी सदस्यों का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। कई एंगल से पक्ष–विपक्ष के सभी साथियों ने इसपे अपनी–अपनी राय रखी है। मैं अभी सोच रहा था कि विजेन्द्र गुप्ता जी कह रहे थे कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं। अब इन रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को जेल भेजने के लिए एसीबी पे तो तुम बैठे हुए हो, भेजो जेल।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई अब।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः ऐन्टी करप्शन ब्रांच तो कहते हैं, हमारी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, आप बोलने दीजिए। वो जनता को मालूम है, किसने भेजना है जेल। प्लीज, प्लीज।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः आप जेल भेजो ना, रोका किसने है? ऐन्टी करप्शन ब्रांच आपकी, पुलिस आपकी, सीबीआई आपकी, तोता आपका, मैना आपका, गीदड़ आपका सारे आपके। दिल्ली में ऐन्टी करप्शन ब्रांच को।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई देखिए, सिरसा जी, अब शांत रहिए प्लीज।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः आधी रात को अर्धसैनिक बल करके एसीबी के हेडक्वार्टर का...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जब विजेन्द्र जी बोले थे, मैंने कंट्रोल किया सबको। अब ऐसा नहीं करिए। ये उचित नहीं है प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माननीय उप मुख्य मंत्री बोल रहे हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वो जितना भर के भेजा है, उतना तो बजेगा ही ना। टेपरिकाडर है, उसे भी कैसे रोक लोगे आप? तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि ऐन्टी करप्शन ब्रांच इनके पास, सीबीआई इनके पास, तोता इनके पास, मैना इनके पास, चिड़िया इनके पास।

उड़ाओ, क्या उड़ गया जी? अब वो तोता कहाँ उड़ गया? अब वो मैना कहाँ उड़ गई? अब वो चिड़िया कहाँ उड़ गई? जब भ्रष्टाचार को रोकने... अभी इनके नेता जी ने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं भी कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार हो रहा है।

माननीय अध्यक्षः भई मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कम से कम आप तो शांत रहें, डिस्टर्ब न करें माननीय मंत्री जी को।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैं भी कह रहा हूँ अधिकारी पैसा खा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि आप गिरफतार कराइए ना, क्यों नहीं करवाते हैं? उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर–कर के पैसा खा रखा है। पैसे का ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चला रखा है इन लोगों ने। ऐसे–ऐसे पदों पे जहाँ बजट ज्यादा हैं, जहाँ सेंसिटिव पोस्ट हैं, सबसे भ्रष्ट अधिकारियों को ढूँढ–ढूँढ के, हमारी सरकार आई थी, तीन महीने सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास था। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट में खड्डे... लाइन लगाके जिन अफ्सरों को रखा, उनसे पैसा एलजी ऑफिस इस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चला रखा है वहाँ पे। एलजी ऑफिस के नीचे मुझे नहीं पता एलजी साहब पैसे लेते हैं कि नहीं लेते।

मुझे नहीं पता लेकिन एलजी साहब की नाक के नीचे ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चला रखा है। जिन अफसरों को, जिन कर्मचारियों को हमने खड्डे लाइन लगाके रखा हुआ था, सरकार आते ही उनको ऐसी ऐसी सेन्सिटिव पोस्टिंग पर बिठाया गया है ले जाके कि लास्ट में इस दीवाली से पहले

जब मुझे दिल्ली के कई व्यापारियों ने आकर कहा जी, रिश्वत माँग रहे हैं आपके लोग। मैंने लिस्ट देखी कौन से लोग हैं तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे ऐसे लोग जिनको हमने कोई एक चपरासी की पोस्ट देने लायक नहीं समझा था, उनको ऐसे ऐसे पदों पर बिठा दिया गया ले जाके। और मैंने पता किया, कहाँ से धंधा चल रहा है ये। सारे के सारे लोग इनको पैसा चढ़ा–चढ़ा के वहाँ आके बैठ गये। मुझे मजबूरी में देश के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में, तो मैं गारंटी देता हूँ पहली बार हुआ कि किसी फाइनेंस मिनिस्टर को वैट डिपार्टमेंट का इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का एक एक कर्मचारी सरेंडर करना पड़ा, मुझे कमिश्नर को निर्देश देने पड़े कि सरेंडर कर दो इनको, डिपार्टमेंट में मत रखो। एलजी साहब नहीं करेंगे। अगर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं करेगा तो मैं मानूँगा और मैं खुलकर कहूँगा और मैंने लिखकर दिया उनको कि अगर ये सरेंडर नहीं हुए तो मैं मानूँगा कमिश्नर पैसा खा रहा है और अगर सरेंडर हुए और उसके बाद भी हटाए नहीं गए तो इसका मतलब मैं मानूँगा रिश्वत लेकर ट्रांसफर किये गये हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाओगे, एसीबी में पैसा खाओगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ। आप माननीय मंत्री जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ में नहीं आता आपको!

माननीय उप मुख्य मंत्रीः सोमनाथ भाई, मुझ पर भरोसा रखो, चिंता मत करो। मैं भी जवाब दे सकता हूँ। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाओगे। एसीबी को चलाने में पैसा खाओगे और फिर यहाँ खड़े होके घड़ियाली आँसू बहाओगे, कि लोकतंत्र का तकाजा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ विजेन्द्र जी भी जानते हैं। सारे साथी जानते हैं यहाँ पर। एलजी साहब ने जो यहाँ बात कही, कई मेरे साथी टिप्पणी कर रहे थे मेरी सरकार, मेरी सरकार अभी मैं पढ़ रहा थाः 'कहीं हाथ जोड़ना पड़ता है और शीश झुकाना पड़ता है, दिल पर पत्थर रखकर आना जाना पड़ता है, दिल पर पत्थर रखकर आना जाना पड़ता है। जिस बापू के सीने में इन्होंने गोली मारी थी, आज उसी बापू के आगे इनको फूल चढ़ाना पड़ता है।'

ये लोकतंत्र का तकाजा है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कहा, 'निराशा... उसके बावजूद चार साल में इन्होंने जो एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये सरकार काम न करे। ये जितने विधायक बैठे हैं, इनके काम न हों। नगर निगम में तरह तरह के प्रस्ताव पास कराये कि एमएलए फंड से कोई काम न हो जाए। अफसरों को मना किया कि खबर... यहाँ तक प्रस्ताव पास किये कि अगर कोई अधिकारी एमएलए के साथ घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बावजूद इनके एलजी साहब आकर भाषण देकर गये कि ये सरकार काम कर रही है। निराशा तो आपको होनी ही होनी थी। निराशा तो होनी थी, लाजिमी था। हमें अपने ऊपर शर्म आती, अगर आप कहते कि हमें बहुत अच्छा लगा। हमें फख्र है इस बात का की विपक्ष निराशा महसूस कर रहा है। तमाम रोकने की कोशिश करने के बावजूद सरकार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। इस बात पर फख्र है।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के बारे में मैं कहूँगा, माननीय मंत्री गोपाल राय जी ने भी कहा, कई बार साथियों ने भी बात कही एक चुनी हुई सरकार

तमाम विरोधों के बावजूद लोकतंत्र में प्रधान मंत्री पद से लेकर इलेक्शन कमीशन पद से लेकर सीबीआई से लेकर, दिल्ली पुलिस से लेकर जो भी संस्थाएँ हैं, उन सबके दुरुपयोग के बावजूद दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जिस तरह से आम आदमी के लिए काम किया है, वो इतिहास में दर्ज होगा। प्रधान मंत्री जी की ये चिंता नहीं है कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है। प्रधान मंत्री जी की ये चिंता है कि हमारे भाई सोमनाथ भाई जी अपनी बीवी से लड़ रहे हैं या कि नहीं लड़ रहे हैं। प्रधान मंत्री जी की चिंता इस बात की है की प्रकाश जारवाल गाड़ी में बैठकर कहाँ शादी में जा रहा है वहाँ रास्ते में कैसे घेरा जाए उनको। तो, अरे! इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना हम अपने घर में लड़ें, प्यार से रहें। हम भी आम आदमी हैं, हम भी अपने घर में बैठकर लड़ेंगे झगड़ेंगे। यार! प्रधान मंत्री जी की चिंता यह है कि बॉर्डर पर देंखें। बार्डर से तो घुस आए आतंकवादी! प्रधान मंत्री जी फोटो शूट करा रहे हैं वहाँ कालागढ़ में बैठकर, चार चार घंटे तक। चालीस शहीद मारे गये, उसके बाद भी चार घंटे तक मॉडलिंग करवाई है इस देश के प्रधान मंत्री ने। ये देश याद रखेगा। ये देश और आज उसी माडलिंग के तहत यहाँ अपने लोगों को वही फोटो शूट कराने भेजा है कि नमो गेम की फोटो शूट कराके आ जाओ। चार–चार घंटे तक... और आज और किसी को यकीन न हो, आज अध्यक्ष महोदय, मैं सेल्यूट करता हूँ टेलीग्राफ की पत्रकारिता को, पिछले नौ दिन में प्रधान मंत्री जी ने... इतना पूरा देश सदमे में से गुजर रहा है। महिलाओं ने अपने गहने बेचकर के तेरह–तेरह लाख रुपये शहीदों की विधवाओं के लिए मदद भेजी है और प्रधान मंत्री महोदय करोड़ों करोड़ों और लाखों लाखों रुपये के रोज नये सूट पहन रहे हैं। नौ

सूट, फोटो छपी हैं, नौ सूट की। पिछले नौ दिन में प्रधान मंत्री ने कितनी... नौ आलीशान यूनिफॉर्म पहनी हैं, कितने आलीशान कपड़े पहने हैं, उनकी तस्वीरें आज टेलीग्राफ ने नौ दिन की, नौ के नौ दिन अलग अलग शानदार कपड़े पहनकर जिस तरह से प्रधान मंत्री जी टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पर आज छपा हुआ है, मैं सेल्यूट करता हूँ उस पत्रकारिता पर। इस देश की पत्रकारिता... अरे! सारा मीडिया, मोदी मीडिया नहीं है। इस देश में पत्रकारिता अभी जिंदा है और सारा मीडिया, मोदी मीडिया नहीं है और सही कह रहे हैं, छपवाया किसी ने भी हो कपड़े तो प्रधान मंत्री ने पहने हैं। छपवा चलो हमने दिया। हमने छपवा दिया चलो, हम श्रेय ले लेते हैं लेकिन इस देश का प्रधान मंत्री नौ दिन में नौ फोटो सूट कराता घूम रहा है; अलग अलग कपड़े पहन पहन के। महिलाएँ अपने गहने बेच रही हैं। अध्यक्ष महोदय, महिलाएँ अपने गहने बेच रही हैं कि मैं शहीदों की मदद के लिए कुछ दे दूँ और प्रधान मंत्री जी कपड़े बदलते हुए फोटो शूट कराते हुए घूम रहे हैं, ठीक उस वक्त और उसके चार घंटे बाद तक। अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में एक सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है, हमारे लिए फख्र की बात है।

अध्यक्ष महोदय, जब कल एलजी साहब यहाँ बोल रहे थे मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी भी है। वो भी सोच रहे होंगे यार... बिलकुल ठीक कहा विजेन्द्र गुप्ता जी ने, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और वही एलजी साहब की मजबूरी है। एक तरफ जब एलजी साहब को प्रधान मंत्री जी से आदेश आता है कि भई ये डोर स्टेप डिलीवरी क्या है? यार! इसकी बड़ी तारीफ हो रही है, इसको रुकवाओ। तो एलजी साहब लिखकर भेजते हैं, ''अगर

ये डोरस्टेप डिलीवरी की सेवा लागू हो गई तो दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ जाएगा।'' दूसरी तरफ मैं इसीलिए कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ, एलजी साहब की मजबूरी को। तो प्रधान मंत्री जी की बात भी माननी पड़ती है। उनको फाइल पर लिखना पड़ता है। अगर इसको मंजूरी दे दी गई उसके बावजूद जब वो योजना लागू हो जाती है तो उन्हें यहाँ खड़े होकर कहना भी पड़ रहा है कि मेरी सरकार एक शानदार दुनिया में सबसे पहले ऐसी योजना लेकर आई है जिसको डोरस्टेप डिलीवरी कहते हैं। उनको मोहल्ला क्लीनिक रोकने के लिए खूब अफसरों को इन्होंने डंडा किया, ट्रांसफर किया, सस्पेंड किया, धमकाया बिठा–बिठा के अगर मोहल्ला क्लीनिक आगे बन गई, इनको, जो चल रही थी, वहाँ भी दवाइयाँ मिलने से लेकर डॉक्टर भेजने तक सब रोकने की कोशिश करी इन्होंने। अब उधर से मोदी जी के यहाँ से आता होगा। ये लोग भी जाकर बताते होंगे, ''जी हमारे मोहल्ले की मोहल्ला क्लीनिक भी अच्छी चल रही है कुछ तो करो। लोग हमें गाली दे रहे हैं।'' ये भी बताते होंगे। लोग इनको आकर बताते होंगे। तो वो एलजी साहब लिखते हैं कि ये मोहल्ला क्लीनिक बंद किये जाएँ। फाइल दबाकर बैठ जाते हैं। ये विधायक वहाँ जाकर वहाँ बैठ गये, करवा लाए। फिर यहाँ आकर खड़ा होना पड़ रहा है, ''मेरी सरकार शानदार मोहल्ला क्लीनिक चला रही है।'' क्या करें, बेचारे फंस गये, फंस गये बेचारे! सीसीटीवी रोकने की कोशिश करी, सिग्नेचर ब्रिज जैसी योजना, अफसरों को कहा गया था, कई जूनियर अफसरों ने प्राइवेट में आकर बताया, नाम लेना ठीक नहीं अननेसेसरी उसको बेचारे को पता नहीं–कहाँ काला पानी भिजवा दें। ये इसमें भी एक्सपर्ट हैं। तो अध्यक्ष महोदय, अफसरों को कहा गया था कि ये सिग्नेचर ब्रिज का उद्‌घाटन इस टेन्योर में हो नहीं जाना चाहिए, वर्ना यहाँ तुम्हारी खैर नहीं

है। उसके बावजूद लग–लगकर, लड़–लड़कर, खुद जा जाके वहाँ बैठ गया कई दिन, तो जाकर मैंने कहा, ''काम करवाओ, इंजीनियरों से काम करवाओ, देखें, कैसे नहीं होता।'' फाइलों पर बैठा तब जाकर सिग्नेचर ब्रिज का उद्‌घाटन हुआ। जिन एलजी साहब की तरफ से प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर उस सिग्नेचर ब्रिज को रोकने की भरपूर कोशिश हुई लोकतंत्र का तकाजा है कि आज सदन में खड़े होकर एलजी साहब को कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज का उद्‌घाटन कर दिया। आखिरकार बहुत बड़ी बात है!

अध्यक्ष महोदय, शहीद परिवारों को एक एक करोड़ रुपये की जो तुरंत फौरी मदद देने की योजना इस सरकार ने बनाई थी, उसकी फाइल पर एलजी साहब डेढ़ साल तक बैठे रहे, डेढ़ साल तक! और क्या क्या बहाने मारते रहे? बोले, ''केन्द्र सरकार से पूछ लो।'' अरे! दिल्ली सरकार का पैसा है, दिल्ली के टैक्स का पैसा है। अगर दिल्ली के सिपाही को दिल्ली के फौजी को दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार शहादत के सम्मान में उस परिवार को एक करोड़ रुपये की मदद देने जा रही है तो तुमको क्या दिक्कत है? क्यों पूछ लें केन्द्र सरकार से?'' फिर बोले, ''अच्छा चलो, उससे पूछ लो, फलाने से पूछ लो।'' कुछ–कुछ इतिहास... देखिये, ये रिकार्ड हो रहा है।

पत्रकार भी देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पत्रकार जरा उन फाइलों को टटोले। देखें आरटीआई डालकर दें। पढ़े उन फाइलों को। उन फाइलों में लिखा हुआ है, किस तरह से। एलजी साहब ने एक करोड़ की योजना को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। लेकिन लोकतंत्र

का तकाजा है कि उन्हें, एलजी साहब को आकर खड़े होकर कहना पड़ रहा है शान से कि मेरी सरकार ने शहीदों के लिए एक करोड़ की योजना की। ये ही लोकतंत्र का तकाजा है, अध्यक्ष महोदय।

मिनिमम वेजिज की जिस फाइल को घुमा–घुमा कर बहुत इधर–उधर घुमाया गया। दिल्ली के गरीब मजदूरों को... रिकार्ड है। मैं कोई अपनी तरफ से हवा–हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। सिग्नेचर हैं, नोट्स है एलजी साहब के जिन फाइलों पर। खूब इधर–उधर घुमाया गया। 'ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते।' और कुछ नहीं बोले मेरे से, कमिटी नहीं पूछी। हमने कहा, ''साहब, कमिटी अप्रूव कर दो।'' बोले, ''नहीं, दोबारा कमिटी बनाओ।'' हमने दोबारा कमिटी बनाई। फिर बोले, ''नहीं।'' फिर इधर से उधर से किया गया। उन सब के बावजूद आज दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेजिज मिल रहे हैं और एलजी साहब के... एलजी साहब को मैं ये नहीं कहूँगा, वो रोकना चाह रहे थे, मैं कहता हूँ, प्रधान मंत्री जी की तमाम कोशिशों के बावजूद एलजी साहब ने उनके कहने पर खूब रोकने की कोशिश की लेकिन आज वेजिज मिल रहे हैं, तो लोकतंत्र की ताकत है कि उन्हीं एलजी साहब को जिन्होंने प्रधान मंत्री जी के कहने पर रोकने के कोशिश की, इस भाषण में उनको यहाँ पर आकर कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार दिल्ली के मजदूरों को शानदार मिनिमम वेजिज दे रही है। दिल्ली के दोनो तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मिनिमम वेजिज गुडगाँव ओर नोयडा में सात हजार और आठ हजार रुपये हैं। आज दिल्ली में चौदह हजार रुपये हैं, अध्यक्ष महोदय और एलजी साहब को कहना पड़ रहा है। रोकने की खूब कोशिश की। ऐसा नहीं है कि रोकने की... तो मैं ये ही देख रहा था

कल कि खुद मदद... मैं उन पर क्या कहूँ? मैं सोच रहा था कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ से अपने बॉस से आ रहे निदेर्शो का पालन करनवाने में, जिन योजनाओं को रोकने की भरपूर कोशिश करी। फाइल पर खूब उल्टा–सीधा लिखा। आज लोकतंत्र के तकाजे के तहत रिकॉर्डिड... ऑन रिकार्ड विधान सभा के रिकार्ड पर आकर कहना पड़ रहा है कि ये योजनाएँ बहुत शानदार हैं। ये ही लोकतंत्र का तकाजा है, अध्यक्ष महोदय। इसी लिए देश में लोकतंत्र को सलाम करने का मन करता है। बार–बार सलाम करने का मन करता है।

मैं अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सदन का कि उन्होंने... मैं एक चीज और लिख कर बैठा था इसमें एनएसयूटी। आज हम गर्व के साथ कहते हैं, एनएसयूटी बना दी। इस एनएसयूटी को रोकने के लिए तीन साल लगाए। तीन साल मोदी सरकार इस पर बैठी रही। मोदी सरकार के कहने पर एलजी साहब ने भी खूब इधर–उधर लिखी। ''ये लिख दो, ये शब्द कर दो, वो शब्द कर दो।'' तीन साल भटका कर लेकिन इसी सरकार के इसी कार्यकाल में आखिरकार एलजी साहब को कहना पड़ा कि मेरी सरकार गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने एनएसयूटी स्थापित कर दिया। दिल्ली में एक नई युनिवर्सिटी स्थापित कर दी।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी साथियों का इस वक्तव्य के लिए, इस चर्चा के लिए और इस सदन का, आप का भी बहुत–बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए। थैंक्यू वैरी मच, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अब श्री गोपाल राय जी माननीय विकास मंत्री द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2019 को माननीय उप राज्यपाल महोदय के

अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव कि यह सदन उप–राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2019 को विधान सभा में दिये गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय उप राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना भिजवा दी जाएगी।

अब सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि दो बजे लंच के बाद सभी माननीय सदस्य बेल बजते ही सदन में उपस्थित हों। कोरम के कारण देर तक लम्बी बेल न बजे। मेरा आग्रह है माननीय सदस्यों से लंच के लिए आप सभी लोग आमन्त्रित हैं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 2:00 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय उपाध्यक्षा (सुश्री राखी बिड़ला पीठासीन हुई)

माननीय अध्यक्षा (सुश्री राखी बिड़ला): अल्पकालिक चर्चा नियम 55 सुश्री भावना गौड़ जी।

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

सुश्री भावना गौड: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।

अध्यक्ष महोदया, भारत के संविधान में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है यानी केन्द्र सरकार की ओर से गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र के करों में से हिस्सा राज्य सरकार को दिया जायेगा जिसे राज्य सरकार अपने विकास कार्यों के ऊपर खर्च करेगा। अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले 1998 में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इस माँग को उठाया गया। 2003 में दिल्ली को पूर्ण राज्य के अधिकार को लेकर के इस पर मसौदा तैयार किया गया जिसे संसद में भेजा गया। 2006 में मदन लाल खुराना जी जो उस समय दिल्ली के तत्कालीन मुख्य मंत्री होते थे, उन्होंने भारतवर्ष के तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी से मुलाकात की और उनसे इस बात पर दरख्वास्त की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उस पर बिल संसद के अंदर पेश किया जाए। अध्यक्ष महोदय, 2003 में बीजेपी की सरकार में उप मुख्य मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कानून बना कर के कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उस पर कानून बना करके उस मसौदे

को स्वयं संसद के अंदर पेश किया गया। अध्यक्ष महोदय, 21 सितम्बर, 2006 जिस तरह से आज दिल्ली सीलिंग को लेकर के त्रस्त है, इसी तरह की सीलिंग की दिल्ली को सील करने की व्यापारियों को सीलिंग करने की व्यवस्था 2006 में भी अपनाई गयी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विजय गोयल जी होते थे, उन्होंने भी क्योंकि शीला की सरकार थी, काँग्रेस की सरकार थी और उस समय लगातार वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसको लेकर के निरंतर अपने साथियों समेत सड़कों पर उतरते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। प्रधान मंत्री निवास दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, देश की संसद दिल्ली में है, दुनिया भर के डिप्लोमेट और उनके दूतावास, वो भी दिल्ली में हैं। ऐसे में सबसे प्रमुख समस्या अगर कोई है तो लॉ एण्ड ऑर्डर को लेकर के है। ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है और सही मायने में अगर मैं कहूँ तो दिल्ली सरकार जिस तरह से केन्द्र के रहमो–करम पर चल रही है, दिल्ली विधान सभा में प्रस्ताव जो पास किए जाते हैं, वो पूर्ण रूप से तभी लागू होंगे जब उसे केन्द्र सरकार अपने यहाँ से पास करके भेजेगी। तो बड़ी दयनीय सी स्थिति हमारी हो गयी है। आप देखिए, इस बार जो चुनाव हुए, दिल्ली की जनता ने 67 विधान सभाओं में अपने मनमुताबिक, अपनी पसंद की पार्टी के लोगों को दिल्ली विधान सभा के अंदर भेजा। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है जिस तरह का मॉडल... हम दिल्ली सरकार दिल्ली को जिस तरह का बनाने का प्रयास कर रहे थे, एक मॉडल जो उन्होंने अपने आप में प्रस्तावित किया, उसको लागू करने में कहीं न कहीं हमें दिक्कत हो रही है। अध्यक्ष महोदय,

आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की माँग काफी समय से करती रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में अभी तक सरकार से कोई लिखित रूप में अधिकारिक चिट्ठी नहीं मिली है। आरटीआई के तहत नोएडा के देवाशीष भट्टाचार्य ने गृह मंत्रालय से दिल्ली सरकार को पूर्ण राज्य की माँग पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जब उन्होंने आरटीआई के तहत जब ये जवाब माँगा तो उन्हें ये जवाब मिला कि अधिकारिक तौर पे दिल्ली सरकार की तरफ से कोई पत्र हमें नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, बड़े अचम्भे की बात है पूर्ण राज्य की माँग को लेकर के ये प्रस्ताव पाँच बार विधान सभा में पास हो चुका है, दो बार काउंसिल में पास हो चुका है, 29 अक्तूबर, 1953 में विधान सभा से पास हुआ, 12 मई, 1954 में विधान सभा से पास हुआ, 11 नवंबर, 1983 में फिर काउंसिल से पास हुआ, 3 जून, 1988 को फिर काउंसिल में इसको पास किया गया, 26 अगस्त, 1994 में विधान सभा के अंदर पास किया गया। उसके बाद में 11 सितम्बर, 2002 में इस प्रस्ताव को लाया गया और 25 नवम्बर, 2010 में इस प्रस्ताव को विधान सभा में पेश किया गया। उसके बाद में 11 सितंबर 2002 में इस प्रस्ताव को लाया गया और 25 नवंबर 2010 में इस प्रस्ताव को विधान सभा में पेश किया गया। इसका सीधा–सीधा स्पष्ट मतलब है कि दिल्ली की विधानसभा उसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो, इसके लिये लगातार वो विधान सभायें जो लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चुनकर के जो सरकार इस विधान सभा का रूप रही हैं, इस सरकार का मैम्बर रही हैं, उन्होंने बार बार इस प्रस्ताव को उठाया और आरटीआई के माध्यम से जो देवाशीष भट्टाचार्य

नोएडा के हैं, उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जब पूछा, तो उन्हें ये जवाब दिया गया कि अधिकारिक तौर पर कोई चिट्ठी उन्हें प्राप्त ही नहीं हुई है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की स्थापना... मुझे लगता है कि उसके दो बुनियादी अधिकार हैं; यहाँ एक तरफ तो चुनी हुई विधान सभा है। उसकी चुनी हुई सरकार है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 67 विधायक इस विधान सभा का अंग हैं एक ही पार्टी के और दूसरी और संविधान का अनुच्छेद 239 एए इस सरकार के अधिकारों की कटौती करता है। अब संविधान में संशोधन कैसे हो, संविधान में बनाये गये नियम और कानूनों को कैसे बदला जाये, ये सीधा–सीधा लोकसभा के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो सदस्य दिल्ली के भी सात सदस्य हैं, वो चुनकर के लोक सभा के अंदर जीतकर के गये। आज जैसा कि हम यहाँ बैठे हुए सभी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी है; दिल्ली ने सात लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जिताकर के लोक सभा में भेजे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, दिल्ली के लिये दुर्भाग्य है, दिल्ली की जनता के लिये दुर्भाग्य है, उन सात जीते हुए प्रतिनिधियों ने आज तक इस बात को वहाँ सरकार में खड़े होकर के नहीं दोहराया, नहीं अपनाया, नहीं बताया कि दिल्ली को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं होगा तब तक यहाँ के विकास कार्यो के ऊपर लोक सभा में बैठे हुए लोग और वहाँ की मोदी सरकार इसी तरह से उनके अधिकारों पर कैंची चलाती रहेगी और यहाँ के विकास कार्य एक जिस गति से होने चाहिए, उनको वो गति नहीं मिल पायेगी।

अध्यक्ष महोदया, दिल्ली में एक करोड़ 70 लाख से ज्यादा की आबादी में यहाँ लोग रहते हैं यानी अगर हम सीधा सीधा आकलन करें तो राष्ट्रीय राजधानियों के मामले में मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ राष्ट्रीय राजधानियों के मामले में दिल्ली सिर्फ टोक्यो से एक नंबर पीछे है। सबसे ज्यादा आबादी वाला जो एरिया है विश्व भर में, वो टोक्यो है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है।

अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक नवीनतम आंकलन जो उनका आया है, उसके अनुसार दो हजार 35 तक दिल्ली विश्व का सबसे बड़ा महानगर घोषित होने वाला है यानी दिल्ली की आबादी उस समय 2035 तक बढ़कर के लगभग चार करोड़ तीस लाख आबादी होने का अनुमान है दिल्ली में। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में दिक्कत है; दिल्ली विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव पास होगा, कोई भी कानून पास होगा, उसके लिये अनुमति केन्द्र सरकार से लेनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि ये समस्या का सबसे बड़ा केन्द्र बिंदु है; जनता के द्वारा चुनी गई इतनी बड़ी सरकार। 67 लोग हम चुनकर के आये। जनता के हित में कार्य करना है, जनता के विकास को लेकर के कार्य करना है लेकिन अनुमति हमें केन्द सरकार से लेनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर है, केन्द्र सरकार के अधीन है जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर कोई भी कंट्रोल दिल्ली सरकार का नहीं है और जब भी कोई क्राइम होता है अध्यक्ष महोदय, तो दिल्ली राज्य में रहने वाले लोग ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके रहते हुए क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता कहीं न कहीं अनभिज्ञ है इन सब चीजों से कि दिल्ली पुलिस के ऊपर सीधा–सीधा अगर किसी का हस्तक्षेप है तो केन्द्र

सरकार का है। सीधा–सीधा कोई हस्तक्षेप है तो एलजी साहब का है और दिल्ली सरकार इस समय दिल्ली में बढ़ रहे अपराधिक मामलों पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा पा रही। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली डेवलेपमेंट ॲथोरिटी यानी डीडीए...

माननीय अध्यक्षाः खत्म करें।

सुश्री भावना गौड़ः मेरे थोड़े से बिंदु हैं, मैं रखूंगी। ये बहुत गंभीर मामला है। पूरी दिल्ली अध्यक्ष महोदया, त्रस्त है, पूर्ण राज्य का दर्जा जब तक हमें नहीं मिलेगा, तब तक न आप काम कर पायेंगे, न हम काम कर पायेंगे।

दूसरा कारण है दिल्ली डेवलेपमेंट एथोरिटी यानी कि डीडीए जो दिल्ली की सारी जमीन पर नियंत्रण रखती है, ऐसे में जब दिल्ली सरकार को कोई जमीन चाहिए तो उसे डीडीए के पास में जाना पड़ता है और डीडीए सीधा–सीधा केन्द्र सरकार के अधीन है। तो यानी जब भी हमें कोई काम करना है तो हम सीधा डीडीए के पास में जायें; डीडीए केन्द्र सरकार के पास में जाये। केन्द्र सरकार से बिना अनुमति के कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा, कोई जमीन हमें नहीं मिलेगी। अगर दिल्ली सरकार की योजना है कि जनता के हित में बढ़िया स्कूल बनाएं, बढ़िया हॉस्पिटल बनाएं उसके लिये सीधा–सीधा जमीन अधिकार क्षेत्र में हमारे नहीं है लेकिन अगर हम डीडीए के पास जाकर के उनसे डिमाण्ड करते हैं कि दिल्ली सरकार चाहती है, जनता के हित में कोई हस्पताल बने, कोई स्कूल बने कोई और बहुत नये डेवलेपमेंट को उस जमीन को लेकर के हों तो सीधा–सीधा... उस पर

हमारा अधिकार क्षेत्र में डीडीए नहीं है इसलिये बहुत सारी योजनायें अभी लंबित हैं और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार कोई विकास की योजना को असली जामा नहीं पहना पा रही, इसके चलते दिल्ली सरकार में और केन्द्र सरकार में जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, इससे सीधा–सीधा नुकसान दिल्ली के लोगों को हो रहा है।

तीसरा अध्यक्ष महोदया, दिल्ली में एमसीडी है। दिल्ली नगर निगम पहले एक नगर निगम होती थी। आज उसको तीन भागों के अंदर बांट दिया। ये छोटे–छोटे काम सफाई से लेकर के टैक्स लगाने तक का काम जो दिल्ली नगर निगम के पास में है, दिल्ली के लोगों को जब छोटे छोटे कामों की आवश्यकता होती है तो उन्हें विभिन्न ऐजेंसियों के पास जाना पड़ता है और विभिन्न ऐजेंसियाँ क्योंकि उस पर अलग–अलग लोगों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है और किसी भी विभाग से उस काम को वो प्रति व्यक्ति जब जाता है किसी विभाग के पास में तो उस काम को तरीके से नहीं करवा पाता और उन्हें जब भी कोई परेशानी होती है और उसकी जवाब देही का सीधा–सीधा ठीकरा अगर किसी पर फूटता है तो दिल्ली सरकार पर फूटता है, एमसीडी के ऊपर सीधा–सीधा केन्द्र सरकार का अंकुश है। जवाबदेही नगर निगम की सीधी–सीधी केन्द्र सरकार को है। राज्य सरकार का उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है और अगर ये सब काम दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिले तो ये नगर निगम जो बने हैं; दिल्ली नगर निगम बने हैं जिनका सीधा–सीधा हर व्यक्ति से लगाव होता है, जुड़ाव होता है। हर छोटे काम के लिये व्यक्ति दिल्ली नगर निगम के पास में जाता है, उनके

अधिकारियों से मिलता है। ये अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होगा तो ये निकाय सीधा–सीधा दिल्ली राज्य सरकार के अंतर्गत आयेंगे।

अध्यक्ष महोदया, जन लोकपाल बिल पास किया, कानून बनाया दिल्ली सरकार ने अपनी विधानसभा में बैठ कर के...

माननीय अध्यक्षाः भावना जी कंपलीट करिये, पंद्रह मिनट हो गये।

सुश्री भावना गौड़ः लेकिन उसे रोक दिया गया। केन्द्र सरकार से उस प्रस्ताव को पास नहीं किया गया। मैट्रो दिल्ली के अंदर चलती है। उसमें निम्न और मध्यम वर्गीय लोग सफर करते हैं। मैट्रो के किराये को बढ़ाया, राज्य सरकार, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन केन्द्र सरकार में बैठे हुए लोगों ने सीधा सीधा मैट्रो के किराये को बढ़ाया। हमने तय किया, सीसीटीवी कैमरा लगायेंगे। सीसीटीवी कैमरा को लगाने में देरी हुई, इसका सीधा–सीधा कारण केन्द्र सरकार रही और जब कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, तब हम इस काबिल हुए कि सीसीटीवी कैमरा को लगा पायेंगे ।

अध्यक्ष महोदया, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना जरूरी है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, ये एक बहुत बड़ा कवैश्चन मार्क है। दिल्ली में विधानसभा है। बहुत बड़ी वाली विधान सभा जिसने इतिहास को बदला है। कांऊसिल आफ मिनिस्टरस हैं, फुल स्टेट हुड की डिमाण्ड बार बार अध्यक्ष महोदया, उठती रही है और मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर की जनसंख्या जो लगभग दो करोड़ है तो मतलब है कि जनसख्ंया के हिसाब से ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर हो गया है। इसी की वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था काफी बढी है। क्राइम एक बहुत

बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में कई ऐजेंसियां काम कर रही हैं। जिनके तालमेल में कमी है, आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा केन्द्र सरकार के पास में जाता है जो कि अगर हम पूर्ण राज्य का दर्जा लेंगे तो वो सब इकट्ठा होने वाला टैक्स, वो दिल्ली सरकार के पास आयेगा जिसके द्वारा योजनाओं को अमली जामा हम लोग पहना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो लॉ ऐण्ड ऑर्डर हमारे पास होगा। पुलिस के अधिकार क्षेत्र में जो कार्य आते हैं, वो सब दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे। और विशेष तौर पर व्यवस्था को बदलने की जो शक्तियां हैं, वो सीधा–सीधा दिल्ली सरकार के हाथ में आएँगी। सरकार चलाने का जो मॉडल हमारे पास है, उस मॉडल को राजधानी में लागू करने के बाद में हम पूरे देश को ये दिखा पाएँगे कि अच्छी और सच्ची नीयत वाली अगर सरकारें आयें और हमारी राज्य सरकार को अगर पूर्णतः अधिकार हों योजनाओं को बनाने का, योजनाओं को लागू करने का तो स्वाभाविक तौर पर हम दिल्ली को एक विशेष मॉडल के तौर पर उपस्थित कर पाएँगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षाः श्री गोपाल राय जी।

माननीय श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष महोदया अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात को लेकर के आज रूल–55 के तहत चर्चा शुरू हुई है। सदन में पहले भी पूर्ण राज्य को लेकर के चर्चा हो चुकी है। दुबारा ये पूर्ण राज्य को लेकर के चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूँ, उसके पहले दो–तीन

बातों को रखना चाहता हूँ। पूरे दिल्ली के अंदर इस बात को लेकर के, हर व्यक्ति इस बात को सोचता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले चार सालों में जितना काम किया है, आज तक जनता के हित में चुनी हुई कोई भी सरकार आजादी के बाद नहीं कर पाई है। प्रश्न आ रहा है कि अगर सरकार इतने अच्छे काम कर रही है तो फिर पूर्ण राज्य तो नहीं है। अगर बिना पूर्ण राज्य के ही सरकार इतने अच्छे काम कर रही है तो पूर्ण राज्य की जरूरत क्या है? ये प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी और काँग्रेस पार्टी के लोग उठाते हैं। अध्यक्ष महोदया, आज मैं सदन के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर 29 फुल स्टेट बनें। अगर पूर्ण राज्य बनने से राज्यों को कोई फायदा नहीं होता तो फिर सारे राज्यों को केंद्र शासित राज्य ही बना दिया गया होता। फिर उत्तर प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की क्या जरूरत थी? हरियाणा को पूर्ण राज्य बनाने की क्या जरूरत थी? महाराष्ट्र को पूर्ण राज्य बनाने की क्या जरूरत थी? यहाँ तक कि आजादी के लम्बे समय बाद तक गोवा गुलाम था। गोवा, जब देश आजाद हुआ, उसके लम्बे समय बाद गोवा आजाद हुआ। गोवा जैसे 15 लाख आबादी वाले राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जरूरत क्या थी? जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जरूरत क्या थी? मणिपुर जैसे छोटे से राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जरूरत क्या थी? असम जैसे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जरूरत क्या थी? उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जरूरत क्या थी? तमाम जो बॉर्डर के हमारे स्टेट हैं, जिससे राष्ट्र के इस देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह पैदा होते रहते हैं, देश की सुरक्षा एजेंसियां जूझती रहती हैं, उन राज्यों

को केंद्र सरकार के अधीन रखने की जगह पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जरूरत क्या थी? कई लोग प्रश्न उठाते है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने से दिल्ली को क्या फायदा होगा। पूर्ण राज्य का दर्जा देने से दिल्ली को बहुत ज्यादा फायदा होगा और मैं ये विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि एक बात कि आज इस सदन के सारे सदस्यों के सामने कि आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता, पिछले चार साल में जो साफ नीयत और नीतियों वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, आज पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो आज दिल्ली के अंदर काम की रफ्तार दस गुणा ज्यादा होती और पूरी दुनिया के अंदर आज दिल्ली का नाम रोशन होता। आज पूर्ण राज्य का दर्जा न होने की वजह से आज काम की रफ्तार कम है और इसलिए आज दिल्ली की जरूरत है कि दिल्ली की रफ्तार को बढ़ाने के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।

दूसरा प्रश्न उठाया जाता है, कहा जाता है दिल्ली देश की राजधानी है। दुनिया की उस एक राजधानी का नाम बताओ, जहाँ पर राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया हो? कई लोग कहते हैं कि जब संविधान बन रहा था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे उस संविधान की रचना की नींव में। डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बड़े–बड़े दिग्गज थे। स्वतंत्रा संग्राम सेनानी थे संसद के अंदर। उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? कुछ तो सोचा होगा। जब संविधान बन रहा था, उस समय दिल्ली की आबादी और दिल्ली का आकार आज 70 साल में कई गुणा बढ़ चुका है। उस समय नई दिल्ली देश की राजधानी हुआ करती थी। उस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेन्द्र

प्रसाद को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक बुराड़ी भी बनेगा इसी दिल्ली के अंदर, एक बदरपुर भी बन जाएगा, एक बाबरपुर भी बनेगा, एक किराड़ी बनेगा। उनको नहीं पता था कि दिल्ली का इतना बड़ा विस्तार होगा और दो तरह की दिल्ली, दिल्ली में पैदा हो जाएँगी। आज दिल्ली के अंदर लगभग–लगभग दो करोड़ आबादी है दिल्ली की।

कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार यहाँ पर बैठती है, दुनिया के दूतावास हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, मंत्री–केन्द्रीय मंत्री बैठते हैं, सांसद बैठते हैं। सारे सीएजी के दफ्तर हैं, तमाम दुनिया के और देश के जो महत्वपूर्ण हैं, रक्षा विभाग यहीं पर है, विदेश विभाग यहीं पर है। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो... एक दिन कह रहे थे विजय गोयल जी, माननीय सम्मानित मंत्री हैं, नेता हैं दिल्ली से जुड़े हुए। जिन्होंने बार–बार बार–बार, अभी भावना जी ने जिक्र किया कि कैसे दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य के लिए लड़ते रहे, कह रहे थे कि दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य मिल जाएगा तो केजरीवाल को ताकत मिल जाएगी और केजरीवाल उस ताकत का दुरूपयोग कर लेगा। मुझे लगता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने में जो माँग पार्टी करती रही है, बार–बार करती रही है और इतिहास में ये दर्ज है कि इस दिल्ली के अदंर पूर्ण राज्य का दर्जा की डिमाण्ड सबसे मजबूती के साथ किसी पार्टी ने उठाया, बार–बार उठाया और कई नेताओं ने उठाया, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। चाहे वो साहिब सिंह वर्मा जी हों, चाहे वो मदन लाल खुराना जी रहे हों, चाहे खुद लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, जिन्होंने संसद के अंदर इस प्रस्ताव को रखा था। लेकिन आज उस भाजपा को डर लग रहा है। पूर्ण राज्य से

डर नहीं लग रहा है, वो डर केजरीवाल से लग रहा है और केजरीवाल से इसलिए नहीं लग रहा है कि केजरीवाल तोप चलाने लगेगा, केजरीवाल से इसलिए लग रहा है कि बिना किसी पॉवर के, सारी ताकतों को काम रोकने के लिए लगाने के बावजूद भी केजरीवाल अगर इतना काम करता है, अगर ये खुदा न खास्ता पूर्ण राज्य होगा तो कितना काम करेगा! और अगर दिल्ली में इतना काम होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का देश की राजधानी में स्थान कहाँ बचेगा? इसलिए आज बयान बदला जा रहा है। इसलिए भाजपा के द्वारा बार–बार झूठ बोला जा रहा है। बार–बार वही नेता झूठ बोल रहे हैं जो बार–बार पूर्ण राज्य के लिए लड़ते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, बार–बार आम आदमी पार्टी ने और इस सरकार ने अपनी मंशा को रखा है। हमारी मंशा केंद्र सरकार से टकराने की नहीं है। हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति उतनी ही ज्यादा है जितना दिल्ली राज्य के प्रति है, या यूँ कहें कि जब देश की बात आती है तो दिल्ली निश्चित रूप से पीछे आती है। दिल्ली की बात और देश की बात में चुनना हो तो देश की बात को हम चुनना पसंद करते हैं। लेकिन हम समाधान चाहते हैं, हम संघर्ष नहीं चाहते हैं। और समाधान है आज दिल्ली के पास और बार–बार हमने प्रस्ताव में रखा है कि दिल्ली के अंदर अगर ये व्यवस्था बनाई जाए, जितने एरिया में राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, जितने केंद्रीय मंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, जितने दूतावास का एरिया है, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, उस सारे एरिया को केंद्र सरकार अपने अंडर में रखे। जैसे वाशिंगटन डीसी, वहाँ अमेरिका की सरकार अपने अंडर में रखे हुई है लेकिन

उसका संचालन वो करती है। हम चाहते हैं कि देश के, दुनिया के तमाम देशों में जो राजधानियों में जो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ एरिया है, उस सारे एरिया का नियंत्रण, संचालन, सारी ताकत केंद्र सरकार अपने पास रखे। वहाँ की कानून व्यवस्था भी रखे। वो जैसे चंडीगढ़... चंडीगढ़ में चुनाव नहीं होते, वहाँ का सारी व्यवस्था का नियंत्रण होता है लेकिन चंडीगढ़ के अंदर राजधानियाँ हैं; हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हमारा प्रस्ताव ये है कि केंद्र सरकार एनडीएमसी का पूरा एरिया का सम्पर्णू नियंत्रण, सम्पूर्ण नियंत्रण अपने पास रखे लेकिन बाकी दिल्ली का पूरा अधिकार, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो लैंड का हो, चाहे पब्लिक ऑर्डर का हो, चाहे सर्विसेज का हो, क्योंकि ये चार चीजें ऐसी चीजें हैं।

जो चार खाने हैं, जिसके आधार पर किसी भी सरकार की इमारत खड़ी होती है। अगर पुलिस को बाहर आप कर देते हो, तो कोई सरकार नहीं चलती है। अगर लैंड को बाहर कर देते हो, तो विकास के नए पायदान नहीं रखे जाते। अगर सर्विसेज को आप बाहर कर देते हो तो कोई चीज पास तो होती रहेगी, जैसे इस सदन में आप बार–बार प्रस्ताव पारित करते हो, केंद्र सरकार कहता है, चिट्ठी भी नहीं आई। आई भी तो नहीं मानेंगे, क्या कर सकते हो? उसी तरह से कैबिनेट प्रस्ताव पारित करती है, ये योजना लागू करेंगे, वो योजना लागू करेंगे, वो योजना लागू करेंगे। वो नहीं लागू करेंगे तो क्या कर लोगे? पास करते रहो। एक बार कैबिनेट ने पास कर दिया, दूसरी बार पास कर लो, तीसरी बार पास कर लो। साल में रोजाना बैठके पास करो, लागू तो नहीं होना तो नहीं होना। इसलिए ये जो चारों पाएदान हैं, पूर्ण राज्य बनने से दिल्ली के लोगों के विकास का रास्ता खुलेगा,

रफ्तार बढ़ेगी और इसलिए ये बार–बार इस बात को महसूस भाजपा भी करती रही है, इस बात को महसूस कॉंग्रेस भी करती रही है। पिछली बार जब बात उठी, कॉंग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री हैं; शीला दीक्षित जी ने कहा, हम भी तो मुख्य मंत्री थी, 15 साल हमने तो करके दिखाया। एक बार जरा पुडुचेरी के अपने मुख्य मंत्री को समझा लें कि हमने भी तो काम करके दिखाया, तू तो कॉंग्रेस का ही मुख्य मंत्री है। तू क्यों एल जी के खिलाफ बैठ जा रहा है धरने पर? एल जी के खिलाफ वहाँ भी धरना चल रहा है। क्योंकि ये सिस्टम की बात है। बात न भाजपा की है, न कॉंग्रेस की है, न आम आदमी पार्टी की है। बात सिस्टम की है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आने के बाद कोई दोयम दर्जे का नागररिक नहीं बन जाता। जब हम बिहार से चलते हैं, कोई बिहार का व्यक्ति आता है दिल्ली के अंदर, बिहार के अंदर बटन दबाता है, उसके वोट की कीमत पूरी है, दिल्ली में आ के बटन दबाता है, उसकी वोट की कीमत आधी हो जाती है। कोई हरियाणा में वोटर लिस्ट में नाम है उसका, हरियाणा का नागरिक जब तक है, बटन दबाएगा, पूरा है। दिल्ली में आ गया, आधा हो गया, उत्तर प्रदेश का आदमी, उत्तर प्रदेश में है, बटन दबाएगा, पूरा है, दिल्ली में आते ही आधा हो गया, तमिलनाडु का आदमी बटन दबाएगा, तमिलनाडु में उसके वोट की कीमत पूरी है, दिल्ली में आते ही आधी हो जाती है। ये जो चमत्कार दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, ये न तो लोकतंत्र के पक्ष का काम है, न संविधान के पक्ष का काम है। इसलिए दिल्ली बार–बार चाह रही है कि दिल्ली के लोगों के साथ जो दोयम दर्जे के नागरिक का व्यवहार किया जा रहा है, इस अपमान को बंद किया जाए और आज दिल्ली के अंदर, अगर ये पूर्ण राज्य बनता है, इसकी रफ्तार 10 गुणा ज्यादा होगी।

मैं उदाहरण दे के आपको बताना चाहता हूँ। हमारी विधान सभा के अंदर नॉर्थ–ईस्ट सबसे सघन आबादी वाला इलाका है, नॉर्थ–ईस्ट के अंदर आठ विधान सभाएँ आती हैं, उस आठ विधान सभाओं के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल है; जीटीबी हॉस्पिटल जो नॉर्थ–ईस्ट की विधान सभाओं के साथ–साथ पूरे पूर्वी–पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के, दवा और सारे इलाज का बंदोबस्त करता है। सबसे ज्यादा भीड़ उस हॉस्पिटल में रहती है। चार साल पहले हमने अपने विधान सभा के अंदर एक हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया, फाइल यहाँ से लेकर के एल जी साहब तक गई, सारा कुछ हुआ, जल बोर्ड ने उस प्रस्ताव को पारित करके हमारी विधान सभा में जमीन नहीं है, जल बोर्ड के पास 60 एकड़ जमीन थी, उन्होंने तीन एकड़ जमीन हॉस्पिटल के लिए एलॉट कर दिया, बोर्ड ने पास कर दिया, एक साल हो गए, एक साल से जल बोर्ड द्वारा तीन एकड़ जमीन एलॉट होने के बावजूद भी डीडीए लैंड यूज चेंज करने के लिए फाइल 13 बार ऊपर जा चुकी और 13 बार नीचे जा चुकी, डीडीए ये बताने को तैयार नहीं है कि वो लैंड यूज क्यों नहीं चेंज कर रहा। एक साल हो गया।

दूसरी मैं घटना बताना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है; आजादपुर मार्केट। आज वहाँ पर व्यापार काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन वहाँ जगह की शॉर्टेज है। कुछ साल पहले एपीएमसी ने 11 एकड़ जमीन जो उस मण्डी के बगल में है, खरीदा। मुफ्त में नहीं, खरीदा जितना डीडीए ने पैसा उसके लिए मुकर्रर किया, सारा पैसा एपीएमएस ने डीडीए को जमा कर दिया, सारा पैसा। आज तक एक इंच जमीन डीडीए से जो है, एपीएमएस को नहीं मिली है, एक इंच जमीन नहीं मिली है, सारा

व्यापारी परेशान है, पैसा दे चुके, जमीन दिल्ली वालों की, टैक्स का पैसा दिल्ली वालों का, डीडीए को दे दिया गया, आज तक एक इंच नहीं दी गई। फाइल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये फर्क पड़ रहा है दिल्ली के ऊपर। आज दिल्ली के अंदर अगर किसी की विधान सभा में कुछ हो जाए, सबसे पहले जनता आती है अपने विधायक के पास, हमारी सुरक्षा करो जी। पूरे दिल्ली के अंदर हर मोहल्ले में छोटे–छोटे अवैध शराब के ठेके खुले हुए हैं, कोई ऐसी विधान सभा नहीं है जिस विधान सभा के अंदर गली–मोहल्लों में अवैध शराब के ठेके की दुकान न खुली हो। जब आप जन–सुनवाई करने जाओ, 10 लोग आ जाते हैं, ''ठेका बंद कराओ।'' विधायक एप्लीकेशन लिखता है थाने को, पुलिस को। तीन दिन बाद पुलिस आती है। ठेका फिर खुला हुआ है। फिर वो आते हैं, फिर पुलिस में जाते हैं, फिर ठेका खुल जाता है। फिर वो आते हैं, फिर पुलिस में जाते हैं, फिर ठेका खुल जाता है। क्या करेगा विधायक! विधायक मंत्री से कहता है, मंत्री मुख्य मंत्री से कहता है, मुख्य मंत्री किससे कहने जाए? अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता और दिल्ली पुलिस होती तो आज पूरे दिल्ली के अंदर जो जगह–जगह और जितने ठेके खुले हुए हैं अवैध सारे, महिलाओं के अपमान के, सारे महिलाओं के बेइज्जती के केंद्र बने हुए हैं। सुबह–सुबह से लेकर के शाम तक अड्डा लगता है। वहाँ से कोई महिला निकल नहीं सकती है। आज पूरी दिल्ली के अंदर ये परिस्थिति बनी हुई है। आज दिल्ली के अंदर कई ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाएगा तो केंद्र सरकार जो पैसा देता है, वो बंद हो जाएगा। दिल्ली को बहुत घाटा हो जाएगा। माननीय सदन के सामने मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली सवा लाख

करोड़ रुपए का टैक्स देती है, हम देश को भी चलाना चाहते हैं, इस सदन के सामने हम प्रस्ताव रखना चाहते हैं सवा लाख करोड़ में से आधा आप देश को दे दो, लेकिन आधा तो दिल्ली वालों को मिलना चाहिए, आज इसलिए नहीं मिल रहा है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। 365 करोड़ रुपए से, काँटे की सुंई एक इंच आगे नहीं बढ़ती है। साल दर साल गुजर रहे हैं, साल दर साल मंहगाई बढ़ रही है, साल दर साल दिल्ली की जरूरत बढ़ रही है लेकिन 365 करोड़, तो 365 करोड़ पर फुल स्टाप लगा हुआ है, 325 करोड़। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बने तो आप सोचो 60–65 हजार करोड़ रुपया दिल्ली को आएगा, अगर जमीन दिल्ली के पास आती है, 60–65 करोड़ रुपया दिल्ली के पास आता है, आप सोचो दिल्ली की तस्वीर क्या होगी? आज दिल्ली के हर गार्जियन की एक चिंता होती है कि अगर हमारा बेटी–बेटा इंटरमीडियट पास करके 80 परसैंट नम्बर लेकर के आता है, एडमिशन लेने कहाँ जाएगा? बिहार जाएगा या झारखंड जाएगा? असम जाएगा या जम्मू कश्मीर जाएगा, कहाँ जाएगा एडमिशन लेने? अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाए, 65 हजार करोड़ दिल्ली को मिले, जमीन दिल्ली को मिल जाए, आज दिल्ली के अंदर इतने कॉलेज–यूनिवर्सिटी खुलेंगे, दिल्ली के किसी भी बेटा–बेटी को एडमिशन लेने के लिए तरसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज दिल्ली के पास ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से ये फायदा होगा। तीन लाख से ज्यादा आज पढ़े–लिखे नौजवान दर–दर भटक रहे हैं। लालीपॉप दिया जा रहा है; एक लाख करोड़ कर्जा देंगे–लेंगे, पाँच साल चला गया। कहाँ गई नौकरी, कहाँ गया वादा? छोड़ दीजिए।

दिल्ली सरकार के अंदर आज तीन लाख वैकेंसियाँ खाली पड़ी है। चार साल गुजर गए, सर्विसेज के नाम पर क्या कहते हो? मेरी बपौती है सर्विसेज और जब नौकरी देने की बात आती है तो सांप सूंघ जाता है। तीन लाख में से आज एक वैकेंसी नहीं निकली, आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाए, अगले एक हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और तीन लाख नौजवानों को, बेटे–बेटियों को नौकरी का रास्ता खुल सकता है। ये फायदा है दिल्ली को पूर्ण राज्य बनने से।

दिल्ली के अंदर, आज सुबह बात कर रहे थे माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी कि दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों को पक्का क्यों नहीं किया? कोई एक कालोनी बता दो, एक घर बता दो। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली के पास कॉलोनियों को पक्का करने का अधिकार नहीं है। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनता है, एक महीने के अंदर दिल्ली की सारी कॉलोनियों को पक्का करने का अधिकार इस विधान सभा और सरकार को मिल जाता है। ये फायदा है दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने से। आप कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात, इसी सदन में और सब माननीय सदस्यों के सामने जन लोकपाल बिल पास हुआ है, ये कमरे में तो पास नहीं हुआ था? ना अध्यक्ष जी के कमरे में वो पास हुआ था, न माननीय मुख्य मंत्री जी के रूम में पास हुआ था। इसी सदन ने लगभग साढ़े तीन साल पहले इसी सदन ने, जन लोकपाल बिल को पास किया, एँटीक्रप्शन ब्रांच की तो हम चर्चा करते ही हैं, छीन लिया गया। डर किस बात का था? जन लोकपाल तो दे देते। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो साढ़े तीन साल से जन लोकपाल बिल लटका नहीं होता। दिल्ली के अंदर जन लोकपाल देश का पहला बनता

और क्या कारनामा वो कर सकता है, वो करके दिखाता भी। ये पूर्ण राज्य बनने का फायदा होता। इसलिए अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम देश का भी हित करना चाहते हैं और दिल्ली का भी हित करना चाहते हैं। इसलिए साफ–साफ प्रस्ताव इस सदन के अंदर बार–बार आया है कि केंद्र के अंदर में जितने केंद्र सरकार से और दुनिया से संबंधित जितने भी दफ्तर हैं उनका काम भी सुचारू रूप से चले और ससम्मान के साथ देश–केंद्र की सरकार को चलाए, इसके लिए हम चाहते हैं कि केंद्र एनडीएमसी का एरिया केंद्र सरकार अपने पास रखे, वहाँ का पुलिस भी अपने पास रखे, वहाँ की सारी योजनाओं को लागू करने का अधिकार अपने पास रखे। उस एनडीएमसी एरिया में अपने एलजी को भी बिठा ले और हम चैलेंज करेंगे तब कि तुम्हारा एलजी कितना काम करता है और हमारा दिल्ली का मुख्य मंत्री कितना काम करता है। तुमको करके दिखा देंगे। एक बार मुकाबले में आओ तो एक बार मुकाबले में तो आओ। अच्छा–अच्छा गप–गप करते हो और जो भी बुरा होता है थू–थू करते घूमते रहते हो। ये दोहरी मापदंड की पालिसी अब नहीं चलने वाली है और इसलिए मैं सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि कब तक चुपचाप बैठे रहोगे ऐसे? हर बार प्रस्ताव पारित करते हो, चला जाता है ठंडे की टोकरी की बस्ती में। अरे! दिल्ली वालों ने तुमको चुनकर भेजा है, औकात है तो दिल्ली वालों की बात को उठाओ, बार–बार लड़ने से बेहतर है... जाकर के गिड़गिड़ाते हो, एलजी हाउस में बैठकर के एक फाइल पास करवाने के लिए, मुख्य मंत्री जाकर के धरने पर सड़क पर बैठता है, एक फाइल पास कराने के लिए दस–दस दिन तक जाकर के उप मुख्य मंत्री अनशन पर

बैठता है फाइल पास कराने के लिए। अरे! लड़ना है तो एक बार लड़ो पूरा राज्य लेकर आओ और दुनिया को दिखाओ, दिल्ली क्या होती है।

इसलिए अध्यक्ष महोदया, सदन से कहना चाहता हूँ कि माननीय दिल्ली के नागरिकों ने कुछ सोचकर के आपको यहाँ भेजा है। अगर लड़कर के दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं ले सकते हो तो विधायक बने रहने का कोई अधिकार हमें भी नहीं है। शुक्रिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय उपअध्यक्षाः सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पूर्ण राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया... और अभी नाच भी सिखायेंगे चिंता न करो। अध्यक्ष महोदया, आज सदन में कुछ नमो–नमो पहनकर आए हैं। पहली बात तो ये सदन की मर्यादा के खिलाफ है इस तरह से कोई–कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना ये राजनीतिक प्रचार करे सदन के अंदर, ये तो गलत है।

माननीय उपअध्यक्षाः भारती जी, आप मुद्दे पर आइए सीधा।

श्री सोमनाथ भारतीः दूसरी बात अध्यक्ष महोदया, आज जिस तरह से माननीय गोपाल राय जी ने अपनी बात रखी और हम सबको चुनौती दी और कहा कि आर–पार की लड़ाई लड़ी जाए। हमने इस सदन के अंदर बहुत बार चर्चा कर लिया, बहुत सारे रेजुलेशन पास कर लिए, लेकिन केन्द्र सरकार के कान के ऊपर जूँ तक नहीं रेंगी है। आज भाजपा के सदस्य यहाँ भी नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए तुले हुए हैं। पूरे देश के अंदर चर्चा है कि जो सरकार... आज एक सवेरे विडियो आ रहा

था अमित शाह जी का– भाई बहनों... एक बार फिर दे दो नरेन्द्र मोदी जी को मौका फिर मौका दे दो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। साढ़े चार साल क्या सब्जी बेच रहे थे बैठकर के? पाँच साल क्या किया? क्या बेच रहे थे? चाय बेच रहे थे। अध्यक्ष महोदया, शूटिंग कर रहे, शूटिंग कम से कम जो अंग्रेज हैं, शूटिंग वहाँ कश्मीर के बॉर्डर पर करते, दो–चार पाकिस्तानी मरते। तुम शूटिंग करने मगरमच्छ देखने गए थे मगरमच्छ, मगरमच्छ देखने गया था। अरे! भाई काहे को? यहीं देख लेते शीशा देख लेते। अध्यक्ष महोदया, इस देश के अंदर जो चल रहा है ये संविधान और पीपल्स मेंडेट के खिलाफ है कि किसको प्रधान मंत्री बनाना है। पूरे संविधान के अंदर कहीं भी किसी भी प्रोविजन में प्रधान मंत्री के चुनाव का उल्लेख नहीं है। उल्लेख किसका है? सांसद के चुनाव का और ये फिर संविधान की मर्यादा के खिलाफ पीपल्स मेंडेट की मर्यादा के खिलाफ वही झूठा प्रचार, 'एक बार फिर मोदी सरकार।' अरे भैया क्यों वही झूठा प्रचार? क्योंकि अब न आ रही, चिंता ना करो। जुमलों की सरकार, अब नहीं आ रही मोदी सरकार। अभी हमारे साथी ने वो कहा, ''नमो नेवर अगेन।'' और इसका संदर्भ विस्मरण डिस्कशन से इसलिए है विजेन्द्र गुप्ता जी आप दिल्ली के हैं। आप सारे साथी भी दिल्ली के हैं, दिल्ली की जनता के वोट की ताकत यूपी के जनता के वोट की ताकत से कम क्यों है? हरियाणा के जनता की वोट की ताकत दिल्ली के जनता की वोट की ताकत से ज्यादा क्यों है? इस पर ये आज जो ये चर्चा हो रही है। आज जो हम सबकी पीड़ा निकलकर आ रही है। उस पीड़ा में आपको सम्मिलित होना चाहिए। अगर आप दिल्ली के जनता के प्रति वफादार हैं तो, अगर आप... वो बतायेंगे हैं तो।

अध्यक्षा महोदया, ये संविधान के प्रारूप के खिलाफ है। एक राजा पहले चुन लो और उस राजा के राज्याभिषेक करने के लिए 543 लोग पूरे देश में से ऐरा–गैरा नत्थू–खैरा, सबको वोट दो। ये तो गलत है। ये दिल्ली के अंदर जिस तरह से सातों सांसदों को वोट मिला और इनकी पार्टी की नाकामी है कि एमसीडी के चुनाव में भी ये मोदी को लेकर आते हैं। ये मोदी के नाम पर एमसीडी के चुनाव में वोट देते हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आज भी कहीं सवेरे कह रहा था... कि चर्चा में था अगर दिल्ली की जनता एक सशक्त, शिक्षित, मजबूत, ईमानदार सांसदों को चुन ले और इस तरह से पूरे देश के अंदर 543 सशक्त व्यक्ति चुनकर के पार्लियामेंट में आ जाएँ तो ऑटोमेटिकली सशक्त लोग एक सशक्त प्रधान मंत्री चुन लेंगे। ये तो बेइमानी है, ये तो संविधान का बेइज्जती है कि भई आप सीधे कहते हैं कि नहीं, मोदी जी को वोट दो। राहुल जी को वोट दो। इस दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को इस बार देखना है कि न तो हमको मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाना है, न तो हमको राहुल जी को प्रधान मंत्री बनाना है। हमें सात सशक्त उन व्यक्तियों को पार्लियामेंट में चुनकर भेजना है जो दिल्ली की समस्याओं के ऊपर संसद में आवाज उठा सकें। दिल्ली का विधायक, आज जिस तरह से गोपाल राय जी ने अपनी बात रखी, दिल्ली के विधायक के पास, यूपी के विधायक के जैसी पूरी शक्ति नहीं है। दिल्ली के विधायक के पास जब दिल्ली की जनता आती है कि पुलिस की समस्याएँ, डीडीए की समस्याएँ, लैंड की समस्याएँ, लॉ एण्ड आर्डर की समस्याएँ, इन समस्याओं के ऊपर दिल्ली वाली जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए, इसका एक इमिजिऐट और तत्काल जो समाधान दो महीने के भीतर दिख

रहा है, थोड़ी बहुत उसकी खानापूर्ति हो सकती है कि दिल्ली की जनता उस पार्टी के सांसदों को चुनें जिस पार्टी का शासन दिल्ली में है। क्योंकि अगर यूपी का सांसद जनता को उपलब्ध नहीं हो पाता है तो जनता के पास च्वॉइस है कि जनता वहाँ यूपी के अंदर विधायक के पास जा सकता है लेकिन दिल्ली में नहीं है। यहाँ तक कि जो थाना लेवल कमिटी था अपना, जिसके जरिए हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते थे, कह सकते थे पुलिस को बता सकते थे। लेकिन माननीय उप राज्यपाल महोदय ने एक ही नोटिफिकेशन... इस नोटिफिकेशन के जरिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी बनती थी और उसी के जरिए थाना लेवल कमिटी बनती थी। थाना लेवल कमिटी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक पुलिस के ऊपर कंट्रोल करने लगेंगे। पुलिस से काउंटेब्लिटी माँगने लगेंगे लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी बनाने दिया। क्योंकि सारे भाजपा के ही मेंबर आफ पार्लियामेंट थे जिनको की उसका चेयरपर्सन बना दिया। अगर आज ये मेंबर आफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के होते तो जो माननीय मोदी जी ने या जिस किसी की सरकार अगर सेंटर में होती, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के मेंडेट को बेइज्जती करने का काम किया है वो इनकी औकात नहीं हो पाती।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके जरिए सदन को कहना चाहता हूँ कि इस बार दिल्ली के अन्दर इस बात को सब साथी मिलकर के जनता के घर—घर तक पहुँचाए कि दिल्ली के अन्दर यूपी जैसी स्थिति नहीं है। इसलिए हम सबको मिलकर के चूँकि हम लोग बहुत पीड़ित रहते हैं। जनता तो पीड़ित है ही। लेकिन जनता की पीड़ा का जो समाधान हम नहीं कर पाते तो हम भी पीड़ित हो जाते। इसलिए दिल्ली के अन्दर बड़े मुहिम पर घर—घर

जा करके इस बात को बताना पड़ेगा कि दिल्ली के जो सातों सांसद चुने गए थे भाजपा के, उन्होंने न तो एक बार पार्लियामेंट के अन्दर कोई बात कही, दिल्ली के लोगों की हित की बात। इतनी बड़ी सीलिंग हुई कोई बात नहीं हुई और न तो इन्होंने कभी जनता को अपनी उपलब्धता दर्ज कराई; पुलिस के मामलों के लिए, लैंड के मामलों के लिए।

अध्यक्ष महोदया, इसलिए वो बात बतानी बहुत जरूरी है। साथ में, अगर दिल्ली का पूर्ण राज्य का जो हमारा ये जो आज डिबेट है और हमने कई बार डिबेट कर लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी जानना चाहते हैं भई क्या दिल्ली के जब लोग वोट डाल रहे थे तो क्या उन्हें कहा गया था कि भई तुम्हारे वोट की ताकत कम होगी? सब्जेक्ट टू एक स्टार करके नीचे लिखा होताः subject to Delhi becoming full State your vote will not be giving you the powers of Police, powers of land etc. etc. etc… It's an absolutely confusional crisis in a way. जनता वोट देती है। वोट के बाद जनता आशाएँ करती है, रखती है। लेकिन हम मजबूर हैं। हम कह नहीं सकते। एमपी महोदय को फोन कर लो कि मैडम एक पुलिस की समस्या, लैंड की समस्या... महोदया कहती हैं कि सोमनाथ जी, 10 बजे से पहले फोन मत करना, मेरी नींद नहीं खुलती। इनके सांसद ऐसे बताते हैं, इनकी नींद नहीं खुलती। हमारे यहाँ पाँच बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। आज जिस तरह से विजेन्द्र गुप्ता जी ने एलजी महोदय के भाषण को एलजी से अलग करने का प्रयास किया, लगा अगर उनके भाषण को हम साथ में कह देंगे तो एलजी महोदय का कहीं अपमान न हो जाए। भइया! ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। एलजी हों या

प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हों, उनको सदन के सामने वही पढ़ना पड़ेगा जो वहाँ की सरकार कहेगी और सुन लो, सुन लो, इसीलिए यहाँ पर आपकी न चल पाई। जहाँ चल पाती है, वहाँ पे आपने ऐसी–तेसी कर रखी है। वहाँ पे रोज जाके वहाँ, वहाँ चले जाते हो ये बिल पास न करो, वो बिल पास न करो। ये साइन न करो, वो साइन न करो। आज बड़े कड़े शब्दों में गोपाल राय जी ने कहा तीन लाख वेकैंसी हैं, दिल्ली वाले जानना चाहते हैं आपसे विजेन्द्र गुप्ता जी, ये तीन लाख वेकैंसी जितने बेरोजगार जो आपने प्रॉमिस किया था पूरे देश को कि दो करोड़ हम नौकरी देंगे हर साल। ये तीन लाख तो कम–से–कम उपलब्ध करा दो दिल्ली वालों को, करो दो ना।

माननीय अध्यक्षाः सोमनाथ जी, कम्प्लीट कीजिए।

श्री सोमनाथ भारतीः भई अगर आप चाहते हैं नहीं, अभी तो हमने शुरूआत हुई है।

माननीय अध्यक्षाः कम्प्लीट कीजिए।

श्री सोमनाथ भारतीः हमने तो शुरूआत की है।

माननीय अध्यक्षाः आप अपनी बात कहिए, कम्प्लीट कीजिए।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदया, ये तीन लाख नौकरी की बात हो या ये भ्रष्ट अधिकारियों की और भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजने की बात हो, आज मुझे वो कह रहा था, आप भी कह रहे थे आज कि जी, शीला दीक्षित जी को आपने जेल नहीं भेजा। जेल नहीं भेजा आपने शीला दीक्षित

जी को। अरे! कैसे भेजे? कैसे भेजे? क्योंकि चाची से समझौता आपका हुआ है कि चाची चिंता मत कर, इनके हाथ बांध रखे हैं हमने, चाची चिंता मत कर आपके यहाँ समझौता हुआ है। झूठ तो नहीं कह रहा? समझौता इनका हुआ है कि चाची तू चिंता मत कर ''इनके हाथ बांध रखे हैं। एसीबी छीन लिया है। कैसे करेंगे तुमको अन्दर? चिंता न कर।'' और साथ में वो जो आपका मामा मुकेश अंबानी, उसको भी कह दिया, ''चिंता मत कर। ये कुछ नहीं कर पाएँगे, जब तक मैं हूँ।'' 56 इंच का सीना मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अनिल अंबानी को... दिखाया कुछ नहीं। 56 इंच का सीना सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मोदी जी ने कहा है और किसी के लिए नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदया, क्योंकि ये मुद्दे बार–बार भाजपा के लोग पब्लिक में उठाते हैं और हमें नीचा दिखाने के लिए कि भई शीला जी जेल नहीं गई। लेकिन साथ में ये बता देते कि भइया! एसीबी हमने छीन लिया था। ये नहीं कहा। भई नौकरी नहीं मिल रही। साथ में ये भी बताते। भई, सर्विस हमने छीन लिया था। इसपे पूरी कम्पलीशन बताया करो ना दिल्ली की जनता को। उनको जिस तरह से आप भुलावे में रखते हो और गलत बयानी करते रहते हो, उससे तो दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है। ये नहीं, छित्तर तो पड़ेंगे वैसे भी जो है ना, चिंता न करो उसकी। भई, ये मत लिखना। अध्यक्ष महोदया, आज दिल्ली की जनता जो कन्ट्रीब्यूट करती है; ट्रेजरी में सवा लाख करोड़ रुपया। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो इसका 42 परसेंट स्टेट को मिलता और जैसा गोपाल राय जी ने कहा कि अगर हम आज उदार दिल करके कह दें कि भई देश को हम 50 परसेंट देने

को राजी हैं, कम–से–कम 50 तो हमें 42 परसेंट का दे दो। अगर उतना भी मिल जाए तो हम पहली सरकार वैसे भी पहली सरकार हैं जिसने कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी जिस तरह का काम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में करके दिखाया है, अगर पूर्ण राज्य मिल जाए और इस सवा लाख करोड़ का 22 परसेंट, 42 परसेंट का आधा भी मिल जाए तो हम लोग इसकी एक वो गवर्नेंस की और गवर्नेंस के अन्दर उन कीर्तिमानों को स्थापति कर पाएँगे जिसको क्रॉस करना किसी के लिए संभव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदया, चूँकि आज बड़ी बात चल रही थी डेमोक्रेसी की, अभी बग्गा जी आए कि नहीं आए? जिसको दिल्ली की जनता ने हरा दिया एमएलए के चुनाव में, उनको डेमोक्रेसी की क्या मखौल उड़ाते हैं, मोदी जी। दखिए, डेमोक्रेसी की मखौल उड़ाते हुए माननीय मोदी जी ने उनको एलजी बना दिया। एलजी बना दिया पुडुचेरी का और वो एलजी जो हैं, चुने हुए मुख्य मंत्री का मजाक उड़ाते उनको कौआ का दर्जा दे रहे हैं। मतलब तमिल के लोगों ने समझा नहीं ढंग से नहीं तो तमिलियन बड़े सेंसिटिव लोग हैं और उनको ये मखौल समझ में आ गया ना कि तमिल के लोगों को आपने उनके कलर के ऊपर और उनकी भाषा के ऊपर जिस तरह से मखौल उड़ाया है तो आपको वहाँ से वापस नहीं आने देंगे वो। आज दिल्ली देश के अन्दर दो ही लेजिस्लेचर हैं; एक पुडुचेरी और एक दिल्ली है जहाँ कि असेम्बली भी है और वो यूटी भी है। तो या तो भइया, असेम्बली ले लो पूरा–पूरा, इसको यूटी कर दो या असेम्बली को पूरी ताकत दे दो। आठ दिन से अध्यक्षा जी, एक डर अरविंद केजरीवाल साहब का, जिस मुख्य मंत्री को पुडुचेरी के मुख्य मंत्री को उनकी पार्टी ने भी सहयोग नहीं दिया, जैसे

ही माननीय मुख्य मंत्री दिल्ली के पुडुचेरी गए, पुडुचेरी के सीएम के साथ बैठे, माननीय मनीष जी भी साथ में गए थे। वैसे ही शाम को किरण बेदी जी ने तुरंत मीटिंग बुला ली कि भइया, केजरीवाल जी यहाँ भी आ गए। अब अगर यहाँ आ गए तो ये युद्ध लंबा खिच सकता है और पुडुचेरी और दिल्ली की लड़ाई इकट्ठी है, माननीय केजरीवाल साहब कह के आए हैं।

अध्यक्ष महोदया, ये डेमोक्रेसी का जो मखौल उड़ाते हैं कि भई जिसको जनता हरा देती है, उसको भी ये मंत्री बना देते हैं इनके सारे जो केन्द्रीय मंत्री हैं जो पॉवरफुल हैं।

माननीय अध्यक्षाः भारती जी, आप कम्प्लीट करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः अमित शाह जी हों, अरूण जेटली जी हों, रविशंकर प्रसाद हों, ये सारे मंत्री, स्मृति इरानी हों, लोकसभा में... अरे! आप काहे को डर रहे हो? अरे! सुशील गुप्ता हो या एनडी गुप्ता हो सुनो। सिरसा जी, सुन लो ऐसा है, मैं सुशील गुप्ता जी को और एनडी गुप्ता जी को मुबारकबाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि जिस तरह की विन्डिक्टिव सरकार आपकी है कि जो कोई भी थोड़ा बहुत पावरफुल कहीं दिखे, उसको हरासमैंट कर दो। वो दोनों आदमी की ईमानदारी का प्रतीक है कि आम आदमी पार्टी के अन्दर आकर के हमारे साथ खड़े हैं। नहीं तो तुम्हारी सीबीआई, आईसी ये पेन टेन टू जो मनीष जी कह रहे थे तोता, मैना, सुग्गा, कौआ, सब लगा दो पीछे।

माननीय अध्यक्षाः सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः आज दिल्ली की वोट की ताकत कम क्यों है, इसके ऊपर सब की निगाहें आनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए; साढ़े चार साल निकल गया हमारा चार साल निकल गया, हमारा सर्विसेज हमारे पास नहीं आया। मैं आज सदन के माध्यम से उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपके पास मुद्दा है। आपने तीन जज के बैंच के आगे भेज दिया है। कृपया करके सर्विसेज के मुद्दे को आप दिल्ली की जनता के फेवर में, केजरीवाल साहब के फेवर में मत करिए। लेकिन दिल्ली की जनता के फेवर में जरूर करिए। नहीं तो ये केजरीवाल साहब की कार और ड्राईवर मोदी जी का गाड़ी कहाँ जाएगी? ड्राईवर मोदी जी का तो जो आपका पॉलिटिकल कम्पीटेटिव है, जो कम्पीटीशन है, उसका ड्राईवर और गाड़ी आपकी तो गाड़ी तो चलने वाली नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी जितना काम हमने करके दिखाया है, उसका कोई इतिहास में कम्पैरिजन नहीं दिखता, अध्यक्ष महोदया।

अध्यक्ष महोदया, मैं याद दिलाना चाहता हूँ भाजपा के और काँग्रेस के साथियों को, दोनों को कि भई, आप दोनों ने वादा किया था। अपने–अपने मेनिफेस्टो निकालकर देखो। अभी हर्षवर्धन जी का एक वीडियो भी आ रहा था कि एक बार मौका दे दो, केन्द्र सरकार बनने दो, केन्द्र सरकार बनते के साथ ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। सबने कहा इनफेक्ट वो पूरे हिन्दुस्तान में चर्चा एक ही है कि भई, मोदी जी को हराने के लिए आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है। उनके पुराने भाषण दिखाओ, उनको जैसे कहते थे, ''मनमोहन सिंह जी, ये कहाँ से आते हैं आतंकवादी? बॉर्डर से आते हैं न?'' बीएसएफ के पास बॉर्डर है ना, बीएसएफ किसके आधीन

है? लव लैटर लिखने से काम नहीं चलेगा।'' अरे भइया! अब तो तुम्हारे पास है। करके दिखाओ ना। जो 40 शहीद हुए हैं जवान, डूब मरो अब पानी में। प्रधान मंत्री बने फिरते हैं। इनकी आह लगेगी तुम सबको। जिस तरह से तुम लोगों ने मजाक उड़ाया है देश के शहीदों का, यहाँ से यहाँ, यहाँ जवान शहीद हो रहे थे और वहाँ आप शूटिंग कर रहे थे, मगरमच्छ देख रहे थे। अरे! घर में देख लेते मगरमच्छ। फोटो के सामने खड़े हो जाते शीशे के सामने, डूब मरने वाली बात है! न इनको देश की चिंता है, न इनको दिल्ली की चिंता है, अध्यक्षा महोदया, और मैं अपनी इस बात के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ कि आर–पार की लड़ाई गोपाल राय जी के शब्दों में बड़े खुले तरीके से आ गई है। साथियो! हमारे पास एक साल का वक्त है दिल्ली वासियों को अगर पूर्णतया संवैधानिक अधिकारों की उपलब्धि करानी है तो हम सबको दिल्ली को पूर्ण राज्य बना के ही रहना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरीके से हम लोग मुसीबत में रहेंगे। न तो ये राम मंदिर बनाएँगे, न तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। हम सब मिलकर के ही इनसे छीन सकते हैं और दिल्ली वासियों को ये तोहफा दे सकते हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य बने और दिल्ली के निवासियों के वोट की ताकत भी उतनी ही हो जितनी कि यूपी की और हरियाणा के साथियों के वोट की ताकत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षाः आपका धन्यवाद बहुत–बहुत। नितिन त्यागी जी, संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री नितिन त्यागीः धन्यवाद, अध्यक्षा महोदया, एक बहुत ही मुद्दे पर आपने बोलने का अवसर दिया। हम लोगों का जो प्रिएम्बल है भारत के कांस्टीट्यूशन में।

अध्यक्षा महोदयाः नितिन त्यागी जी, आपको संकल्प प्रस्तुत करना है।

श्री नितिन त्यागीः संकल्प भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। हमारा प्रिएम्बल एक बार सबको याद दिलाने के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। वो हैः

"We the people of India having solemly resolve to constitute India into a soverign, democratic, republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation is a Constituent Assembly. On this 26th day of November, 1949."

ये सबको, सारे के सारे देश की जनता को इक्वेल स्टेटस देने के लिए ये पूरा का पूरा कांस्टिट्यूशन बना है और ये प्रिएम्बल उसका सार है। तो जैसा गोपाल जी कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो जाता है कि यहाँ की जनता की वोट की कीमत आधी रह जाती है। कहाँ गई इक्वेलिटी? तो मैं ये रेजल्यूशन हाउस के सामने रखना चाह रहा थाः

"This House resolves the following:

In keeping with the decades-old demand of the residents of National Capital Territory of Delhi for a better quality of life commensurate with their contribution to the country's economy,which have been strongly and unambiguously reflected in the views expressed by Hon'ble Members of this august House, the Ministry of Home Affairs,

Government of India, must take all necessary legal and legislative steps to declare NCT of Delhi a full-fledged state without any further delay;

This House notes with extreme disappointment that successive Central Governments have without any valid justification attempted to undermine the basic rights of the people of Delhi by denying them statehood;

People of Delhi can no longer be kept at the mercy of a Central Government appointed Lieutenant Governor, who has no accountability towards the public and enjoys absolute powerwithout any responsibility;

Elected representatives are directly accountable to the voters and are rightly questioned by thepeople on issues affecting their daily lives and developmental issues. It is, therefore, beyond any legal and reasonable understanding how a politically nominated LG be the super-boss of a democratically elected Council of Ministers which is collectively responsible to the Legislative Assembly;

Ever since 1952 and then later in 1993, when the Legislative Assembly was set-up in its present form for NCT of Delhi, every single elected Delhi government has strongly demanded statehood in order to be able to fulfill the aspirations of the people;

In 2003, the then Hon'ble Deputy Prime Minister and Home Minister Mr. LK Advani had on 18th August 2003 presented the Constitution Amendment Bill and the Bill foÙk statehood of Delhi in the Lok Sabha;

The Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, headed by the then Chairman Mr. Pranab Mukherjee in its 106th Report tabled in Parliament in December 2003 had strongly endorsed the Bill. Unfortunately, however, due to dissolution of the Lok Sabha a few months later, the Bill lapsed.

Strangely, no attempt was made to revive the Bill after that despite the same party having been in power at the Centre and in Delhi foÙk 10 years since 2004;

This House is of the view that now since almost 16 years have passed since the previous Delhi Statehood Bill was presented in Parliament and there were some shortcomings in that Bill,therefore the MHA must consult the elected government to be on the same page about the fresh draft Bill;

This House resolves that the NDMC area in Delhi, which is governed by the NDMC Act be kept under the exclusive control of the Central government and the rest of NCT of Delhi be declared a full-fledged state;

Therefore, the people of Delhi will not tolerate any further unjustified delay in granting them their rights, which have been denied foÙk decades despite promises having been made by all political parties repeatedly in their election campaigns;

This House strongly demands that the MHA must place the feelings of the people of Delhi before both Houses of Parliament in the form of a Constitution Amendment Bill to grant full statehood for Delhi.'

माननीय अध्यक्षाः ये प्रस्ताव जो अभी नितिन त्यागी जी ने अभी पेश किया सदन के समक्ष है। श्री नितिन त्यागी जी माननीय सदस्य दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं अतः पहले मैं श्री नितिन त्यागी जी से अनुरोध करूंगी की वह अपना प्रस्ताव सदन के सामने जो उन्होंने पढ़कर सुनाया है अब उसकी सदन में प्रस्तुती के लिए अनुमति माँगें।

श्री नितिन त्यागीः मैं इस प्रस्ताव को सदन में रखने के लिए अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षाः अब यह प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष हैः

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे हाँ, कहें

जो इस प्रस्ताव के विरोध में हैं,वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ, पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्रीमती बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः धन्यवाद, अध्यक्षा महोदया। आज सदन में दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। जब जब जो पार्टी आई है; कॉंग्रेस की रही या भाजपा की रही, हर किसी ने अपने अपने तरीके से दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए संघर्ष किया लेकिन हम

सबके लिए बहुत ही दुःख की बात है, दिल्ली के अंदर एक अलग से मेनिफेस्टो बना था 2014 में, उस मेनिफेस्टो का पहली लाईन थी, 'दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना।' और सौभाग्य रहा जो दिल्ली के सातों सांसद भाजपा के चुनके आए हैं और सातों सांसद का लगभग पाँच साल पूरा होने जा रहा है और उस पाँच साल में एक बार भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए या दिल्ली वासियों के किसी भी मुद्दे पर चाहे दिल्ली की बिगड़ती लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था हो या दिल्ली में लैंड की मारामारी चल रही हो या दिल्ली में सीलिंग हो। दिल्ली के किसी भी मुद्दे पर लोक सभा में कभी उन सभी सासंदों ने, जो भाजपा के चुने हुए सांसद थे, इन्होंने उस मुद्दे पर कभी आवाज नहीं उठाई। आज हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हम सब एक पूर्ण बहुमत से, प्रचण्ड बहुमत से दिल्ली के लोगों ने हम सभी 67 विधायकों को चुन कर भेजा है। आज हर मुद्दे पर दिल्ली की जनता ये समाधान अपनी चुनी हुई सरकार, आपकी सरकार, आपके विधायक के माध्यम से वो सभी समस्या का समाधान दिल्ली सरकार से चाहती है। चाहे लॉ एण्ड ऑडर की हो।

माननीया अध्यक्षाः अभी तो चर्चा ही हुई है अभी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, हटवा देंगे। अभी जब प्रस्ताव पास होगा, बैठे हैं अभी इस पर चर्चा ही चल रही है।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष महोदया, वो आज दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। दिल्ली की प्रचण्ड बहुमत से चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार आज दिल्ली की जनता किसी भी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार से हर मसले

पर समाधान चाहती है। चाहे दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके के लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे उनके घर के किसी भी तरह की मारपीट हुई हो या गली मोहल्ले में शराब की दुकान हो या उनके कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज एक बहुत ही दुःख के साथ मैं अपने क्षेत्र की एक छोटी सी घटना आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। बीते दस दिन पहले हमारे क्षेत्र की वार्ड–62 की निगम पार्षद और उनके बेटे ने मिलकर हमारे आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, उनके हसबैंड को अकेले जानकर पूरी तरीके से पीट दिया। अकेले थे वो अपनी साईट पर वो अपने ढेहा पर खड़े हुए, बिल्डिंग मैटीरियल का उनका काम है। वहाँ पर वो खड़े थे और उनके निगम पार्षद के बेटे ने बुरी तरीके से लहू लुहान करके उनको पीट दिया। पीटने के बाद वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद निगम पार्षद आई, उनके बचाव में निगम पार्षद भी आई, उनको पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वहाँ पर आधे घंटे बाद पहुँची। सभी व्यवस्था को लेकर जब थाने में मैं पहुँची तो बारह घंटे बैठने के बावजूद भी आज तक दस दिन बाद तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस गुहार को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? एक चुनी हुई प्रतिनिधि होने के बावजूद भी क्षेत्र की जनता मुझे कहती है, ''तुम्हारी कोई औकात नहीं है।'' आज इस सदन में बैठे होने पर मुझे बहुत शर्म लगता है जो कि आज हम अपने क्षेत्र की जनता की एक छोटी से छोटी समस्या का समाधान पुलिस का लॉ एण्ड ऑर्डर का नहीं कर पाते। एक छोटा सा छोटा एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं हमारे साथी, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। उनको बस किताबों में ऐसे ही रख दिया जाता है। जिससे जितने भी अपराधी तत्व के लोग

हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। आज हमारे शालीमार विधान सभा क्षेत्र में जितना हर दिन, आए दिन किसी दिन चाकू मार दिया जाता है... सरे आम बाजार के बीच में दो बच्चों को चाकू मार दिया गया। दोनों की उम्र 15 से 18 साल के बीच की थी और माँ के सामने, पूरे पड़ोस के सामने, पूरे बाजार के सामने दो बच्चों को चाकू मार दिया गया। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। माँ उसकी इन्साफ की गुहार लगा रही है लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। एक माँ के सामने लगातार गोली से धुन–धुनकर आठ गोलियाँ चली, माँ के सामने। माँ बैठी हुई थी, बेटे को गोलियाँ मार दी गई। माँ कुछ भी नहीं कर पाई। ''अपने बेटे की बॉडी लेकर कर जाओ।'' इस तरीके की घटना आज शालीमार बाग विधान सभा के अंदर हो रही है। थाने लेवल की कमिटी थी, उसको खत्म कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटी बना दी गई। हमारे बहुत सारे विधायक हैं उस कमिटी में। बता दें, एक दिन भी सांसद आए हों। आज हम अपने क्षेत्र की समस्या लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या लेकर हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? इसलिए आज हम सब की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाना। एक ही लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या इतनी बिगड़ी हुई है, इतनी बिगड़ी हुई है, सीसीटीवी में सारी बातें आती हैं। आज हम सीसीटीवी लगाने के लिए, हमारी सरकार की चार साल की जद्दो–जहद बाद आज हम सीसीटीवी कैमरे भी लगा दें अपने क्षेत्र में, सीसीटीवी कैमरे में सारी रिकार्डिंग आ रही है; ताला कैसे टूट रहा है घर का, कैसे चोरी हो रही है, कैसे सामान की लोडिंग हो रही है, कौन सामान की लोडिंग कर रहा है, कौन चुरा कर ले जा रहा है। लेकिन आज तक, आज तक

चोर नहीं पकड़ पाया। जिसका सारा सामान घर से चला गया, उसका एक रूपया भी नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जवाबदेही किस पर तय होगी? आज तक वो पुलिस ऑफिसर को एक सस्पेंड क्या... दो दिन के लिए भी उसको टर्मिनेट नहीं किया गया। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो आज उस एक दो को ट्रांसफर किया जाता, एक दो को संस्पेंड किया जाता। तो कहीं न कहीं एक दहशत बनती, एक डर होता और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो अपने काम को तरीके से करते। आज पुलिस को चार ईंट लेकर कोई जाए, चाहे झुग्गी में घर बनाना हो या गाँव में घर बनाना हो या महल बनाना हो, चार ईंट जाए, अभी आप लेकर जाओ पुलिस पीछे–पीछे पहुँच जाती है। उनको पता चल जाता है यहाँ मकान बन रहा है। यहाँ मकान बन रहा है। आप वैसे ही दुकान का खोखा लगाकर रख दो सिर्फ दिल्ली पुलिस पीछे–पीछे आ जाएगी और उनको ये पता चल जाता है आज यहाँ दुकान लगने वाला है। तुम कितने रुपये रोज दोगे, वो पहले बता दो? कितने रुपये रोज दोगे, कितने महीने रोज दोगे, ये पहले बता दो। ये पता चल जाता है पुलिस को। लेकिन कोई गुण्डा मार के चला जाता है, कोई गुण्डा चोरी करके चला जाता है, किसी को कुछ करके चले जाता है, वो पकड़ कर लाना, उस पर एफआईआर दर्ज करना, उसको जो उचित सजा है, वो देना, दिल्ली पुलिस का काम नहीं रहा गया है। आज हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय, इस सदन के लिए बहुत चिंता का विषय है और पूरा दिल्ली देख रहा है इस सदन की ओर जो हमें न्याय कौन दिलाएगा। बहुत उम्मीद के साथ हम सबको चुनकर दिल्ली की जनता ने भेजा था और ये उम्मीद की थी

जो अब हमें कुछ न्याय मिलेगा। अभी तक डर—डरकर दिल्ली की जनता जी रही है। अब शाम को सात बजे के बाद वो अपने बच्चों के साथ निकलना बंद कर दिया है। घर से कहीं बाहर अगर पूरा परिवार जाना चाहे तो वो नहीं जा पा रहा।

माननीया अध्यक्षाः कम्पलीट कीजिए मैडम।

श्रीमती बंदना कुमारीः उसी तरीके से आज हम सभी विधायकों के साथ ऐसा होगा जो हर डिपार्टमेंट में; चाहे पीडब्ल्यूडी, चाहे एमसीडी, चाहे डूसिब, चाहे डीडीए हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारी चार—चार फाइलें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें रोज भागना पड़ रहा है, रोज जाना पड़ रहा है। इस टेबल पर अगर एक महीना फाइल है तो इसी टेबल पर पड़ी रहेगी जब तक आप इस टेबल से उस टेबल पर उठा कर नहीं रखो। कभी बहाना बनता है; अभी छुट्टी पर है, कभी बहाना बनता है; अभी हम नहीं हैं, कभी बहाना बनता है; ये ऑब्जेक्शन लग गया, कभी ये ऑब्जेक्शन लग गया और ऐसी कम से कम हम सब ही विधायकों के यहाँ बीस—बीस पच्चीस—पच्चीस फाइलें होंगी जो फाइल हिलती नहीं। आज उस फाइल के नहीं हिलने पर हम मंत्री जी के पास जाते हैं, हम मुख्य मंत्री जी के पास जाते हैं। वो कहते हैं, ''हम क्या करें?'' क्यों? क्योंकि उनकी भी एक ट्रासंफर करने की एक पीयून को भी सजा देने की पॉवर हमारे दिल्ली की चुनी हुई प्रचण्ड बहुमत की सरकार को नहीं है। आज हम सबको ये सदन को निश्चित करना पड़ेगा जो इस दिल्ली की जनता को हम क्या जवाब दें। आज दो तीन चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमारी शालीमार विधान सभा के अंदर 49 दिन

की सरकार थी। अट्ठाईस सीटों वाली सरकार थी। एसीबी उस समय हम सबके पास था और सर्विसेज हम सबके पास था और उस 28 दिन में हम जिस भी ऑफिसर्स को बुलाते थे, वो ऑफिसर्स साइट पर आ जाते थे। आज की डेट में ऐसी स्थिति हम सबकी हालत बनी हुई है। शायद हमारे सभी विधायकों की होगी जब हम साइट पर ऑफिसर्स को बुलाते हैं, ऑफिसर्स वहाँ नहीं आते। जब तक वो साइट पर नहीं आएँगे, उनको कैसे पता चलेगा प्रोब्लम क्या है। आज एक बस टर्मिनल के लिए पाँच साल से हम धक्के खा रहे हैं, एक हमारे क्षेत्र में बस टर्मिनल नहीं है। एक बस घुमाने की जगह नहीं है। बस कैसे वो बहुत जाकर वो घुमा कर लाते हैं तब हमारे जो सुबह–सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो परेशान होते हैं। आज हमारे क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल नहीं है। आज हमारे क्षेत्र में 11वीं, 12वीं की क्लास जो गाँव के स्कूल वहाँ 10वीं तक की छात्र/छात्राओं के स्कूल हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, उस हैदरपुर गाँव में 11वीं, 12वीं की स्कूल के लिए लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अगल–बगल बहुत सारी डीडीए की लैंड खाली पड़ी है, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आज हमें 11वीं, 12वीं क्लास की स्कूल के बनाने के लिए जगह नहीं मिल पाया और जिस जगह नहीं मिलने के कारण आज 10वीं के बाद गाँव के लोग दूर अपने बच्चों को 11वीं पढ़ने के लिए भेजने में असमर्थ हैं, उनको डर लगता है जो हम दूर नहीं भेजें। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 11वीं क्लास को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि हम सब के पास जगह नहीं है और हम 11वीं, 12वीं गांव के अंदर स्कूल नहीं दे पा रहे। तो बहुत सारी ऐसी छोटी–छोटी समस्याएँ हैं, हम सब के सामने और आज मैं गोपाल जी की उन बातों

का समर्थन करती हूँ माननीय मंत्री जी ने जो बात रखी है; दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम सब को पूरी ताकत के साथ दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए एकजुट होके पूरा दिल्ली हमारे साथ है, पूरी दिल्ली संघर्ष करने के लिए साथ है और हम सब मिल के दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली को पूर्ण राज्य दिला के रहेंगे, जय हिन्द, जय भारत।

माननीया अध्यक्षाः सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद जी, स्पीकर साहिबा। दिल्ली के पूर्ण राज्य के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। स्पीकर साहिबा, ये विषय तो अभी आपने संकल्प में भेजा, बहुत सालों से है और सभी पार्टी ने अपने तरीके से इस बात को उठाया है। लेकिन मैंने पिछले 2–3 साल में ये देखा कि जब भी चुनाव आता है तब ये पार्टी इस मुद्दे को उठाती है और आज हमारे जितने भी वक्ता मेरे से पहले बोले, गोपाल राय जी बोले, हमारी बहन बंदना जी बोलीं, उससे पहले सोमनाथ जी बोले, एक बात की मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। जाने अनजाने में इन्होंने अपनी पार्टी की और अपनी सरकार की खूब सारी पोल खोली है। पूर्ण राज्य के नाम पर इन्होंने यह भी माना कि स्कूल बनाने में भी असमर्थ रहे, जो अरविंद केजरीवाल जी फुल पेज की एड देते हुए झूठी एड होती है, इनके अभी बंदना कुमारी जी ने माना। सोमनाथ भारती जी ने भी ये माना कि हम कुछ भी काम करने में नाकाम हैं। आज चार साल सरकार को हो गए, ये पूर्ण राज्य का जिन्न निकला फिर से बोतल में से। कब निकला? जब अरविंद

केजरीवाल जी ने पुरजोर कोशिश कर ली कि काँग्रेस के साथ किसी तरीके हमारा अलायंस हो जाए, यहाँ तक बोला मंचों के ऊपर जाकर, हमने तो बहुत उनको समझाने की कोशिश करी लेकिन वो अलायंस के लिए मानते ही नहीं। जब ये समझ में आ गया कि सातों की सातों सीटें हम बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, जब ये मान गए कि आने वाली लोकसभा के अंदर इनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं तो आज पूर्ण राज्य का जिन्न बाहर निकल कर आ गया। चार साल की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज इस पार्टी ने दिल्ली के लोगों को फिर से एक बार मूर्ख बनाने की कोशिश की है। 67 एमएलए चुन कर आए लेकिन 67 एमएलए के चुन आने के बावजूद दिल्ली की सबसे विफल सरकार जो रही है आज तक, वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। चार सालों में ऐसी विफलताएँ! बार बार इनको मजबूर कर दिया कभी पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाने के लिए, कभी देश के प्रधान मंत्री के खिलाफ बोलने के लिए और यहाँ तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ बोलने के लिए क्योंकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस पार्टी ने ये हथकंडा अपनाया। दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य हो, ये सब लोगों के लिए सुख–सुविधा की बात है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया, ऐसा नहीं था, वो ज्ञानी नहीं थे। ऐसा नहीं था उनको जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं था, उनके संविधान में कोई खामियाँ थीं। वो पूरा समझते थे, उनको यह भी ज्ञान था कि ऐसे लोग दिल्ली के अंदर शासन में आ सकते हैं जो इस सारे सिस्टम को तहस–नहस कर देंगे और वही आज हुआ। इस डर के चलते बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं दिया था। आज वो 70 साल बाद सच सामने आया,

इसलिए नहीं दिया गया था। ये संविधान के अंदर इसीलिए इनको ये ताकत नहीं दी गयी थी और मुझे इस बात का अफसोस होता अगर ये सरकार, ऐसे लोग जिन लोगों के पास ये ताकत देने की बात थी, चार साल इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। चार साल के अंदर विफल कर... पीने के पानी में विफलता हुई, बिजली में विफलता हुई, एजुकेशन में विफल हुए और मुझे इस बात का भी अचम्भा है ये किस मुँह से आज पूर्ण राज्य मांगते हैं, जो अधिकार क्षेत्र इनके अधिकार में था, उसके अंदर इनकी विफलताओं की लंबी–चौड़ी फेहरिस्त है। अब देखिए, ये दिल्ली की सड़कों पे घूमिए...

...(व्यवधान)

माननीया अध्यक्षाः त्रिपाठी जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपको सैकड़ों फलाई ओवर बने मिलेंगे।

...(व्यवधान)

माननीया अध्यक्षाः आप चुप रहें, उन्हें बोलने दें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः स्पीकर साहिबा, एक भी फलाई ओवर ऐसा नहीं मिलेगा जो आम आदमी पार्टी ने बनाया हो। आपको सैकड़ो अस्पताल मिलेंगे, लेकिन एक भी आपको अस्पताल नहीं मिलेगा जो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी ने बनाया हो, दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटियाँ हैं, दिल्ली के अंदर टेक्नीकल कॉलेज हैं, दिल्ली के अंदर सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हैं लेकिन एक भी मेडिकल कालेज, एक भी दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी ये सरकार बनाने में नाकाम रही है। आज कहते हैं, पूर्ण राज्य दे दो। जिस

पार्टी को 67 एमएलए होने के बाद देहात के लोगों की सार नहीं ली, यहाँ तक ये सरकार कभी एग्रीकल्चर का महकमा तक नहीं खड़ी कर पाई, आज वो सरकार ये कहती है, हमें पूर्ण राज्य दे दो। 1984 के अंदर कत्लेआम हुआ यहाँ पर, उन कातिलों के साथ आज ये सरकार उन लोगों के साथ गले चिपकने का काम करती है, उस पार्टी जिसको सिक्ख सबसे बड़ी अपनी कातिलों की पार्टी मानते हैं, उनको गले लगाती है और ये कहती है, हम इनको इंसाफ दिलाएँगे। हमें इस बात की आज तसल्ली है, ये पूर्ण राज्य अगर होता, 1983 के कातिल आज सड़कों पे घूम रहे होते। जो सरकार दिल्ली की विधान सभा के अंदर एक देश के राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधान मंत्री के संकल्प ले के आए कि इसका भारत रत्न छीना जाए, वो संकल्प पे न टिक पाई, वो सरकार के पास अगर पूर्ण राज्य होता तो मेरे बहन भाई 1984 वाले अपने कातिलों के लिए इंसाफ माँगते रहते। आज तक उनको इंसाफ न मिला होता। मुझे बड़ी हैरानगी है दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट को आपने बुरा भला बोला, सुप्रीम कोर्ट ने आपको गलत ठहराया। आपने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट गलत है।'' इलेक्शन कमीशन ने आपको गलत ठहराया। आपने कहा, ''इलेक्शन कमीशन गलत है।'' जिस भी सांविधानिक संस्था ने आपको गलत कहा, आपने कहा, ''हम गलत नहीं, वह गलत हैं।'' पूरा देश गलत है? और आप ठीक हैं? जो एक विकल्प के रूप में काँग्रेस को करप्ट बता कर, शीला दीक्षित को सबसे बड़ी करप्ट मुख्य मंत्री बता कर आपने लोगों को बरगला कर वोट ली, आज उस करप्ट को गले मिलने को तड़प रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, ''मैं मना मना के थक गया, वो मान नहीं रहे हैं।'' कमाल कर दिया आपने? ऐसा हमें हराने के

लिए, इस के देश के अंदर चोरों के साथ आपने गला मिलना शुरू किया, देश का सबसे बड़ा चोरों का परिवार मुलायम सिंह यादव के परिवार को गले मिलना चाह रहे हैं। देश के अंदर सबसे करप्ट मुख्य मंत्री जिसको आप कहते थे कहते थे, ए. राजा से बड़ा करप्ट नहीं है, आज उस ए. राजा को गले मिला जा रहा है। आप सबसे बड़े चोर जिसको ये कहते थे, ''माननीय मायावती जी सबसे बड़ी करप्शन का अड्डा है।'' वहाँ पर, आज आप उस करप्शन को गले लगा रहे हैं? आपने कहा देश के अंदर पी. चिदम्बरम सबसे बड़ा चोर है, आज उस पी. चिदम्बरम के तलवे चाटने का काम कर रही है ये सरकार। अलायंस नहीं, आपको पूर्ण राज्य नहीं, आपको केवल और केवल विधान सभा की अवाम के लिए, जो विधान सभा में आपका बुरा हाल होने जा रहा है, अपनी जमानतें जब्त कराने के लोकसभा में आपकी नोटंकी न चलेगी।

माननीय अध्यक्षाः बस खत्म कीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्षा जी, क्यो? आप दिल्ली के लोगों को कब तक इस तरह से बरगलाएँगे?

...(व्यवधान)

माननीया अध्यक्षाः भई एक बार आप चुप रहेंगे, सारे सदस्य?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मुझे...

माननीय अध्यक्षाः आप कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट कीजिए, सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपने कहा पूर्ण राज्य होता, हम अस्पताल बनाते। अरे एक ...(व्यवधान)... करते हैं लाखों रुपये की और कहते हैं हमने लाखों हमने सैंकड़ों अस्पताल बना दिए और आपके मंत्री गण यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हम बुरी तरह से विफल हो गये। आपके एमएलए बुला–बुला कर कहते हैं...

माननीय अध्यक्षाः कंप्लीट कीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चार मिनट में इतनी प्रॉब्लम हो गयी। ये कहा गया जो आज हमें... ऐड है कल की अखबार में। मैंने पहली सरकार देखी है, लोग ऐड लगाया करते थे, 'हमने अस्पताल बना दिया।' ये सरकार ऐड लगाती है, 'हमने बेड लगवा दिए।' लोग एड करते थे, 'हमने स्कूल बना दिया। ये अखबार में ऐड लगाते हैं, 'हमने बेंच लगा दिए।' सरकार कहा करती थी, 'हमने नए फ्लाई ओवर बना दिए।' ये कहती है, 'हमने बने फ्लाई ओवर और रंग करा दिए। अरे! ऐसी सरकार भी देखी है कभी किसी ने? आज के अखबार उठाओ, एक करोड़ रुपये की ऐड है आज के अखबार में। अब भी आप कहते हैं, ''हमारे पास पूर्ण राज्य होता...'' अरे! आपने निकम्मियों भरी बातें अपनी बताईं। खुद आपने माना कि आप निकम्मे हैं, आप कुछ भी करने में नाकाम रहे तो फिर अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपये की ऐड काहे के लिए अखबार में दे रहे हैं? ये निकम्मी सरकार जो हर मुहाने पे विफल रही है... हमें आज ये बात कहने को मजबूर होना पड़ रहा है, हम सब जानते थे दिल्ली को पूर्ण राज्य मिले लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों के कारण आज हमारी ये सबसे जो

सशक्त माँग थी, वह भी आज सबसे कमजोर माँग हो गयी। क्योंकि आपने जो पिछले चार साल में किया, जिस करप्शन के नाम पर आपने वोट माँगी, उस करप्शन को गले लगाने के लिए तड़प रहे हैं। वो आपके गले नहीं लग रहे, काँग्रेस आपके गले लग नहीं रही, आप तड़प रहे हैं और कह रहे हैं, ''मैंने इनको बहुत समझाया, आप मेरा साथ दीजिए।'' अरे! ऐसे भी कभी देखा है! इतने चेहरे, इतने रंग बदलते चेहरे मेरी बहन... आज आम आदमी पार्टी को देखकर गिरगिट भी आज शरमा रही है, आज आम आदमी पार्टी के इन रंगो को देखकर।

आज जब आप हार रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी खुद अपने बयान में कहते हैं, हमने सर्वे कराया, हम हार रहे हैं। काँग्रेस हमारा समर्थन करे, हम जीत जायेंगे। आप सीधी तरह कहिये ना, चोर, चोर को गले मिलेंगे तो फिर ईमानदार को गिराने की बात करेंगे। चोरों के गले मिलने से कभी ईमानदार आदमी का किला ढहाया नहीं जा सकता है। आज सब चोर इकटठे होने की बात करते हैं। आप उस किले को ढहा नहीं पायेंगे। मैं अध्यक्षा जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः बस, धन्यवाद।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्षा जी, मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं आपको एक ही मिसाल देना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः देखिये, दो वर्ष पहले जल बोर्ड 168 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रहा था। आज 800 करोड़ रुपये के घाटे में आ गया।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये साबित करता है... देखो, मान गये ना। ये खुद मान रहे हैं, ये चोर हैं। मैं नहीं कह रहा, ये विधान सभा सुन रही है। विधानसभा के अंदर आधे से ज्यादा एमएलए मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी चोर है।

माननीय अध्यक्षाः अच्छा बहुत—बहुत धन्यवाद।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आज ये खुद कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल चोर है। मैंने नहीं कहा, मैंने एक बार नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल चोर हैं। उनके एमएलए खुद...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चिल्ला—चिल्ला के कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल चोर है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः भई, शांत हो जाइए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः और मैं मनीष सिसौदिया जी से पुरजोर माँग करता हूँ उनके खुद एमएलए उनको अगर चोर कह रहे हैं, ऐसे एमएलएज को विधानसभा से बाहर करना चाहिये, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षा: पंकज पुष्कर जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा: पंकज पुष्कर जी।

माननीय अध्यक्षा: भई क्या बात है आप लोगों को? आप बैठिए। जरनैल सिंह जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा: बैठिए। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा: पंकज पुष्कर जी स्टार्ट कीजिये, शुरू कीजिये

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा: बैठिए आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा: बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा: शांत। सिरसा जी, जरनैल सिंह जी, शांत। पंकज पुष्कर जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा: बस सिरसा जी, शांत।

श्री पंकज पुष्कर: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इस अति महत्वपूर्ण विषय जिस पर कि ना केवल दिल्ली के दो करोड़ से ज्यादा नागरिकों का जीवन टिका हुआ है बल्कि जो कि इस देश का जो बुनियादी ढाँचा है, भारत के संविधान के जो बेसिक स्ट्रकचर हैं, उससे एक जुड़ा मामला है। उसको एक मखौल का विषय बनाया जा रहा है। माननीय विधायक श्री सिरसा जी ने इसको पूरा एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके सामने जो दिल्ली की जनता है, वो दो करोड़ से ज्यादा जनता और भारत के संविधान का बुनियादी ढाँचा, इन दो के संदर्भ में एक बात रखना चाहूँगा कि आज जो माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी ने जो बात रखी है कि किस तरह से वो दिल्ली के जनता के जो दिल की आवाज है जो कि इस सदन में पहले भी कई बार सामने आई है, उसको एक नई ऊँचाई तक पहुँचाने का जो आह्वान किया गया है, वो आज के समय की ऐसी आवश्यकता है, आज इस दिल्ली के नागरिक के किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं हो सकता, अगर हम इस सवाल पर चाहे वो सदन हो, अगर सदन पर कही गई बातें नहीं मानी जातीं तो सड़क में उतरने की जरूरत हो, जब तक इस सवाल को हल नहीं किया जायेगा, दिल्ली के किसी नागरिक के साथ न्याय नहीं हो सकता। ये बात आज इस सदन में बिल्कुल एक नई ऊँचाई के साथ, एक नये तेवर के साथ कही जानी आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि नेता विपक्षी दल और सदन के हमारे जो नेता हैं, हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदया आपके संज्ञान में ये लाना जरूरी है कि इस मामले को किस तरह

से एक शुद्ध राजनीति से ऊपर उठाना जरूरी है। बहुत साफ ये समझना जरूरी है कि जो दिल्ली की इस समय आबादी है, दिल्ली का जो इस समय आकार है, वो किसी एक शहर का आकार नहीं है। अगर दिल्ली अपने आप में एक पूरी दुनिया के देशों के सामने रखकर देखा जाये तो दुनिया के 180 देशों से ज्यादा बड़ी आबादी अकेले दिल्ली में रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदया, दुनिया के बहुत सारे देश हैं, बहुत ही विकसित देश हैं, प्रगतिशील देश हैं, उनसे बड़ी आबादी, उनसे बड़ी जनसंख्या, उससे बड़ा समाज दिल्ली के अंदर रहता है और जब भारत का संविधान सिरसा जी के मुँह से बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम सुनकर अच्छा लगा। अभी अभी उन्होंने सीखा है लेकिन 1947 और 1950 के जो भारत का दौर था, वो भारत के विभाजन की काली छाया थी। बहुत डरा हुआ राष्ट्रीय नेतृत्व था, उसको ध्यान में रखकर कुछ तात्कालिक निर्णय लिये गये लेकिन भारत के संविधान का जो बुनियादी पहलू है, एक तो चुना हुआ सदन और उसकी सर्वोच्चता विधायिका की सर्वोच्चता और दूसरा संघवार फैडरलिज्म ये दो बेसिक स्ट्रक्चर भारत के संविधान के बुनियादी तत्व दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की माँग करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दो करोड़ से ज्यादा आबादी को उसके बुनियादी, उसके मूल अधिकारों की रक्षा का मामला यहाँ पर है, वो सुनिश्चित हो, ये मामला क्योंकि उसका जो पूरा एक ऐतिहासिक संदर्भ है और राजनैतिक प्रसंग है, वो पूर्व वक्ताओं ने आदरणीय गोपाल राय जी ने माननीय मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से स्पष्टता से रखा है। मैं केवल मूल अधिकारों के ढाँचे में कैसे आज दिल्ली की स्थिति... आज दिल्ली को आधा अधूरा राज्य के तौर पर देखना यूनियन टेरिटरी कहना

किस तरह से दिल्ली के नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है, उसकी तरफ संकेत करना चाहूँगा। संक्षेप में कहूँगा, सबसे पहली चीज है कि आज इस दो करोड़ की आबादी के बीच जो कि लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर दस साल में दिल्ली की आबादी लगभग तीस प्रतिशत या चालीस प्रतिशत तक भी बढ रही है, इतना अधिक डेकेडल ग्रोथ पूरे देश में कहीं और नहीं है, ये दिल्ली में है। इसको ध्यान में रखते हुए आज जो दिल्ली की पूरी नागरिकता है, दिल्ली का जो पूरा समाज है, उसके जो बच्चे हैं, उनका अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है, मूल अधिकार है, उसका सतत उल्लंघन हो रहा है और इसमें इस बात के जो भागी हैं, वो लोग हैं जो कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के मामले में पाखंड कर रहे हैं। कभी कुछ और कहते हैं और आज वो क्योंकि विपक्ष में हैं, आज इस सदन में चार की संख्या में हैं इसलिये उनका स्वर बदला हुआ है। इस बात के भागी वे लोग भी हैं जो कि इस सदन में जिनको बैठने का सौभाग्य इस सदन में नहीं मिला है, इस वर्ष में, इस सत्र काल में लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किसी राजनैतिक दल का मामला नहीं है, दिल्ली की जनता के साथ न्याय का मामला है। मैं आपको माइक्रो लेवल पर बताता हूँ कि इस दिल्ली की जनता को, इस दिल्ली के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है या नहीं है। दिल्ली में अभूतपूर्व क्रँाति शिक्षा के क्षेत्र में हो रही है लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की बच्चियों को, छोटे बच्चों को, उनको दो किलामीटर के क्षेत्र के अंदर एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा पाने का अधिकार है, इसका सतत उल्लंघन बहुत जगह हो रहा है। इसलिये हो रहा है क्योंकि दिल्ली की जमीन, दिल्ली के स्कूलों के लिये नहीं दी

जा रही है क्योंकि जब पूरे देश में जमींदारी का उन्मूलन हुआ तो दिल्ली में एक जमींदार लाकर बैठा दिया गया जिसका नाम डीडीए है। दिल्ली के देहात की, दिल्ली के किसानों की, दिल्ली के पुराने निवासियों की जमीनों को अधिगृहीत किया गया लेकिन उसको एक बिल्कुल अनुत्तरदायी डीडीए के हाथ में दे दिया गया जो कि आज सैंट्रल गर्वनमेंट के इशारे पर काम करता है। दिल्ली के चुने हुए जन प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी नहीं मानता है तो इसके नाते जो दिल्ली के बच्चों का शिक्षा पाने का मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये दिल्ली के पूर्ण राज्य से जुड़ा मामला है। दिल्ली के नौजवानों का उच्च शिक्षा पाने का अधिकार, आज दिल्ली में हर साल ढ़ाई लाख बच्चा कक्षा 12वीं पास करता है। वो कहाँ जाये, क्या करे?

ये जो पूरा औपनिवेशिक शासन था, उसमें एक ऐसा एक्ट बनाया गया कि केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती, जिसमें कि नए कॉलेज एफिलिएट नहीं हो सकते, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी। आज दिल्ली के उप मुख्य मंत्री महोदय एक क्रॉंतिकारी एजेंडे के तहत नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते है, नए कॉलेजिज का विस्तार करना चाहते हैं जिसके लिए जमीन भी चाहिए और कानूनी स्वायतता भी चाहिए कि किसी भी अन्य प्रदेश सरकार की तरह दिल्ली की सरकार, दिल्ली की विधान सभा भी नए विश्वविद्यालय बनाने का काम कर सके। ये नहीं बनाने दिए जा रहा है। वो ढ़ाई लाख नौजवान जो हर साल बारहवीं पास करके निकलते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको सड़कों की तरफ धकेला जा रहा है, उनको हिंसा अपराध और गैर कानूनी चीजों की तरफ

धकेला जा रहा है, क्योंकि उनके लिए पढ़ने का अवसर नहीं है। उनके लिए विश्वविद्यालय, को–कॉलेजिज नहीं हैं। दिल्ली विधान सभा चाहती है। ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। दिल्ली को अपने नए विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दो करोड़ से ज्यादा जनता, नार्वे से ज्यादा बड़ी जनता है ये, डेनमॉर्क से बड़ी जनता है ये, ये न्यूजीलैंड से ज्यादा बड़ी जनता है, कजाकिस्तान से ज्यादा बड़ी जनता है ये। दुनिया के 160 देशों से ज्यादा बड़ी जनसंख्या दिल्ली में रहती है। लेकिन उस दो करोड़ जनसंख्या के लिए नया कॉलेज, नया विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार दिल्ली के मुख्य मंत्री, दिल्ली की विधान सभा के पास नहीं है। ये क्या मखौल है? दिल्ली जो कि पूरे देश का धड़कता हुआ एक राज्य है, उसके नौजवानों के साथ ये धोखा क्यों हो रहा है? दिल्ली की ये बात, दिल्ली की विधान सभा से निकली हुई आवाज, ये दिल्ली के एक–एक नौजवान के कान में पहुँचेगी कि उसके भविष्य को धूमिल करने का काम, उसकी जिदंगी को बर्बाद करने का काम, कुछ राजनेता अपने स्वार्थों की वजह से कर रहे हैं, जो कि पिछले 50 साल से कहते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनना चाहिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनना चाहिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनना चाहिए लेकिन आज क्योंकि दिल्ली के ऊपर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दीवाने लोग दिल्ली के दिल को जीत चुके हैं, इसीलिए वो अपने पुराने 50 साल के सपने को मिट्टी में मिला चुके हैं, धोखा दे चुके हैं अपने उन बुजुर्गों को।

शुरूआत हुई देशबंधु गुप्ता जी से, शुरूआत हुई चौधरी ब्रहम प्रकाश जी से, मदन लाल खुराना जी से, वी.के. मल्होत्रा जी से, साहिब सिंह वर्मा जी

से, इनमें से बहुत सारे अब दिवंगत हैं, उनकी आत्मा तड़पती होगी कि उनके शागिर्द, उनके राजनीति में जो उंगली पकड़कर जिनको वो लाए, आज वो गद्‌दारी कर रहे हैं; दिल्ली की जनता के प्रति, दिल्ली के उन नेताओं के प्रति, वो उस दिल्ली की जनता के संकल्प के साथ घात कर रहे है जो कि दिल्ली को न्याय दे सके। आज दिल्ली के नौजवानों को रोजगार का अधिकार नहीं है। आज दिल्ली का नौजवान जब पढ़कर निकलता है, कक्षा बारहवीं पास करके, बीए, एमए या कोई भी बीएससी या कोई भी डिप्लोमा लेकर निकलता है, दिल्ली की नौकरियों के ऊपर, जो कि सर्विस कहते हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार बैठी है। दिल्ली के मुख्य मंत्री चाहते है, दिल्ली के उप मुख्य मंत्री चाहते हैं, दिल्ली का मंत्री मंडल चाहता है, दो चीजें चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगारों का सृजन हो और उन रोजगारों में दिल्ली के नौजवानों को मौका मिले। आज दिल्ली का नौजवान तड़पता है। उसको न दिल्ली में नौकरी मिलती है और दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश में जाता है तो वहाँ जाकर वो दूसरे दर्जे का नागरिक बन जाता है। क्योंकि वहाँ पर स्वाभाविक तौर से उस प्रदेश के नौजवानों का पहला अधिकार बनता है। हम सम्मान करते है उसका। लेकिन दिल्ली के नौजवानों का क्या कसूर है? उनकी जवानी को क्यों मिट्‌टी में मिलाया जा रहा है? उनके साथ ये गद्‌दारी क्यों हो रही है? दिल्ली आज पूर्ण राज्य हो, तो उन दिल्ली के लाखों नौजवानों को हक मिले कि कम से कम तीसरे दर्जे की नौकरी में, दूसरे दर्जे के सेवाओं में, लोक—सवाओं में उनको उनका अधिकार मिले। ये उनका लगातार उल्लंघन हो रहा है।

माननीय अध्यक्षा, दिल्ली की बच्चियां, दिल्ली की महिलाएँ... यहीं पर निर्भया कांड हुआ। उसी से जन्म ये अन्ना आंदोलन के साथ–साथ, निर्भया के साथ, दामिनी के साथ जो क्रूरतम अपराध हुआ, उससे ये दिल्ली में क्रॉंति आई। आज क्या हो रहा है, सारे थाने लापरवाह हो गए हैं, सारी पुलिस जो है, आवारा हो गई है। नेताओं के आगे पीछे घूमती है। दिल्ली के एक राजनैतिक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एसीपी को, डीसीपी को धक्का देते हैं, मारते हैं लेकिन तब भी उनके आकाओं के सामने उनको दुम हिलानी पड़ती है। और आज वो पूरी पुलिस डरकर रहती है। न वो पुलिस अपने सम्मान की रक्षा कर पा रही है, न महिलाओं के सम्मान की रक्षा कर पा रही है, न दिल्ली की बच्चियों की जान सुरक्षित है। पूरी दिल्ली पुलिस का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? क्यों है ऐसा? दिल्ली की मेहनत करने वाली जनता, दिल्ली की कानून मानने वाली जनता, सवा लाख इन्कम टैक्स देने वाली दिल्ली की जनता, उसका अपराध क्या है? उसको किस बात की सजा दी जा रही है? केवल इस बात की कि उसने सपना देखा कि हम दिल्ली को एक अच्छा राज्य बनाएँगे। क्योंकि उसने वोट उस पार्टी को दिया जो कि वादा कर रही थी कि हम जन–लोकपाल लेकर आएँगे, इस बात की सजा दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, आज दिल्ली के नागरिक का हर वर्ग तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। जिन राजनैतिक पार्टियों को, जिन दलों को उसने अपने खून से, अपना पैसा देकर, चंदा देकर, वोट देकर सींचा, आज वो उनके प्रति लापरवाह

हो गए हैं, उनके सपनों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे है। आज दिल्ली में कोई बुजुर्ग...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः कम्पलीट कीजिए।

श्री पंकज पुष्करः आज दिल्ली में कोई महिला, दिल्ली में कोई अकेला चलने वाला नौजवान, आज दिल्ली में कोई बच्चा सड़क पार करने से कांपता है। कोई दिव्यांग, कोई विकलाँग सड़क पार नहीं कर सकता, क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस का काम उगाही करना हो गया है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस का काम दिल्ली के ट्रैफिक को संचालित करना, वहाँ से एन्क्रोचमैंट हटाना नहीं रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की कोई जिम्मेदारी, कोई उत्तरदायित्व, कोई एकाउंटेबिलिटी तय नहीं है। दिल्ली के सात सांसद, उन्होंने अपने लिए वाई श्रेणी की जगह जेड श्रेणी की उनको सुरक्षा दी जाए, इस बात के लिए माँग की। दिल्ली की बच्चियों के, दिल्ली के बुजुर्गों को, दिल्ली के वो लोग जो कि किसी भी तरीके की सारी समस्या के शिकार हैं, उनको अधिकार मिले, पुलिस उनकी देखभाल करे, ये उन्होंने नहीं किया।

तो माननीय अध्यक्ष महोदया, आज दिल्ली के एक–एक नागरिक के जो अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, राइट टु लाइव विद डिग्निटी है, कहाँ गया वो? दिल्ली के किस नागरिक की गरिमा सुरक्षित है आज? किसकी जान आज सुरक्षित है? सड़कों पर जिस तरह का एक लापरवाह माहौल है, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके

से असफल हो चुकी है। केवल इसलिए, गलती उस ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, गलती उन आकाओं की हैं जिन्होंने कि उनके उत्तरदायित्व का एक ढांचा जो बनना था, दिल्ली विधान सभा के प्रति उनकी जो जवाबदेही बननी थी, वो उन्होंने जड़ से समाप्त कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तरदायी शासन अगर दिल्ली की जनता को चाहिए, अगर दिल्ली की जनता को अपने सवा लाख करोड़ रुपये जो वो टैक्स के माध्यम से विभिन्न सरकारों को दे रहे हैं, उसकी जवाबदेही चाहिए। तो ये निश्चित रूप से दिल्ली को पूर्ण राज्य की तरफ बढ़ाकर काम बनेगा। जैसा कि माननीय विधायक साथी नितिन त्यागी जी ने अपने प्रस्ताव में कहा है, उसके पूरे समर्थन के साथ मैं कहना चाहूँगा, बहुत उदारता के साथ कह दिया गया है, ये तर्क दिया जाता है कि राजधानी है, राजधानी नई दिल्ली है, बुराड़ी राजधानी नहीं है, बाबरपुर राजधानी नहीं है, ये जो पूरा यमुना पार का इलाका है, वो दिल्ली की राजधानी नहीं है। देश की राजधानी नई दिल्ली है। उस एनडीएमसी के इलाके को केंद्र की सरकार अपने तरीके से चलाएँ, सारे दूतावासों को अपने तरीके से सुरक्षा दें लेकिन यमुना पार रहने वाले, बवाना–नरेला रहने वाले देहात के लोग, सारी अनअथोराइज कॉलोनी में जो कि दिल्ली को चलाने वाले, दिल्ली को बसाने वाले लोग रहते हैं, उनका कोई अपराध नहीं है, उनको कोई सजा इस बात की नहीं दी जा सकती कि उनके अधिकारों को छीना जाए, उनके मूल अधिकारों को छीना जाए। उनके यहाँ अस्पताल ना बनने दिए जाएँ। उनके यहाँ नए स्कूल न खुलने दिए जाए। उनके यहाँ विश्वविद्यालय और कॉलेज न बनने

दिए जाएँ। उनके इस अधिकार को इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि 1913 में कलकत्ता से उठाकर राजधानी इस नई दिल्ली में बसा दी गई। ये तर्क बिल्कुल खाली है। दिल्ली पूरी तरह से दिल्ली की जनता सक्षम है

माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से और जो प्रस्ताव नितिन त्यागी जी ने रखा है, उसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय श्री गोपाल राय जी ने जो एक आह्वान रखा, उसके संबंध में मैं इस आह्वान को, इस अपील को पूरे दिल्ली के एक–एक नौजवान तक, एक–एक बुजुर्ग तक, एक–एक महिला, एक–एक बेटी तक पहुंचाना चाहता हूँ और इस पर अपने सारे साथियों के समर्थन के साथ इस सदन का संकल्प एक बार फिर दोहराता हूँ कि ये 1942 में जो नारा दिया था कि 'या तो करेंगे या मरेंगे', दिल्ली के एक–एक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वो पूर्ण राज्य की माँग के साथ आगे बढ़ेगा, दिल्ली के साथ न्याय की तरफ बढ़ेगा। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सफाई का अधिकार हो, जीवन की रक्षा का अधिकार हो, इन सब गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, संघवाद को बचाने का, चुनी हुई विधायिका के अधिकार को बचाने का, इस पूरे संवैधानिक ढांचे का, बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का, अगर आज उन सपनों को बचाना है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना है, इस नारे के साथ, इस अपील के साथ, इस आह्वान के साथ, इस संघर्ष के संकल्प के साथ मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसको क्षूद्र राजनीति से उठाएँ, इसको याद करें। अपने उन बुजुर्गों के जिनकी आज आत्मा तड़प रही होगी...

माननीय अध्यक्षा: खत्म कीजिए।

श्री पंकज पुष्करः चौधरी ब्रहम प्रकाश जी से लेकर मदन लाल खुराना तक कि हम निश्चित रूप से दिल्ली को पूर्ण राज्य की तरफ बढ़े। ये भारतमाता के प्रति, भारत के संविधान के प्रति हमारा एक न्यनूतम कर्त्तव्य होगा। ये मेरी अपील, हर राजनेता और हर नागरिक से है। जय हिंद, जय भारत।

माननीया अध्यक्षाः विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः माननीया अध्यक्ष महोदया, अभी बहुत जोर–जोर से हमारे सत्तारूढ़ दल के लोग जो हैं और मंत्री भी पूरा दम लगा–लगाकर... बात भी ठीक है कमजोर आदमी दम लगा–लगाकर बोलता है। अब देखिए ना, मोदी जी ने बड़े शाँत स्वभाव से पाकिस्तान को दो लाइन में चेता दिया और पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। बहुत ही, बस दो लाइन बोली थी, दो लाइन कि पूरा विश्व हिल गया और वो भी बड़े...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये डर है आपका, ये डर जो है ना...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः सोमनाथ भारती जी, बंदना कुमारी जी।

....(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये डर जो है ना, आपका दिखाई दे रहा है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैडम, ये सीरियस नहीं हैं चर्चा पे, ये चर्चा पे सीरियस नहीं है, सीरियस होते, तो फिर सीरियसली बात करते। मैं दो बातों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। पहला इशू तो है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पहला इशू तो है।

माननीय अध्यक्षाः बंदना जी, सोमनाथ भारती जी, उनका जो बोलना हो, उनका समय लेने दीजिए, आप चुप रहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये बिल जो है।

माननीय अध्यक्षाः सारे साथी विधायकों से निवेदन है, शांत रहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः कोई बात नहीं, देश सब कुछ जानता है और जनता भी जानती है। आप लोग शांत रहें, देश और जनता सब कुछ जानती है, उन्हें सुनिए, जी, गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जी, ये बिल दो तरह से, पहला तो मैंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में बताया था कि इसके अंदर आपने लिख दिया कि यूनैनिमसली अडॉप्टेड, यानी प्रिज्युडिस्ड हो गया, चर्चा से पहले ही...

माननीय अध्यक्षाः वो प्रस्ताव जब पास होगा, उससे पहले कर लेने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर बिल के ऊपर ही, प्रस्ताव के ऊपर ये शब्द लिखकर भेज दिए, तो ये वैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि साँप निकलने के बाद लाठी पीट रहे हैं।

श्री सोमनाथ भारतीः साँप किसको कह रहे हो?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देखिए, ये जो चर्चा है, ये क्यों... अभी बताता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये जो चर्चा है, ये दो, एक 11 जून, 2018 में इसपे बिल पारित किया गया था सदन में। कब? जब नगर निगम में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ था और दूसरी बार ये बिल उस समय लाया जा रहा है जब लोकसभा में आम आदमी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। यानी कि ये पूर्ण राज्य के दर्जे का जो शगूफा है ये तभी बैग में से बाहर आ रहा है जब–जब आपका राजनैतिक भविष्य खतरे में जा रहा है। यानी कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ये सर, ये पार्टी इस बात को छेड़ रही है। अगर आप वाकई संवेदशील होते तो जो पार्लियामेंट है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये जो संसद है, आपके माध्यम से मैं सदस्यों को बताना चाहता हूँ, इसका कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब संसद का कोई सत्र चुनाव से पहले बैठने वाला नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप तब ये बिल पास कर रहे हो, जब सदन बैठेगा ही नहीं। मुख्य मंत्री जी भी आए हैं। ये चर्चा तब की जा रही है क्योंकि ये विषय है पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट जो है, उसका सत्रावसान हो चुका है और वो अब चुनाव से पहले वो नहीं बैठेगी। तो इस बिल का और इस बिल में जो भाषा का प्रयोग किया गया है, उसका कोई, किसी भी प्रकार का कोई संवेदनशीलता नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल है इसके अंदर आपने।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः सोमनाथ जी, उन्हें बोलने दीजिए। दो मिनट आप चुप रहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपने लिखा है कि दिल्ली कैंट।

माननीय अध्यक्षाः कम्पलीट करने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर देखा जाए एनडीएमसी एरिया अर्थात् दो विधानसभा सीटें, एक तो मुख्य मंत्री जी जहाँ से विधायक हैं; नई दिल्ली और दूसरी दिल्ली कैंट, जहाँ से हमारे फौजी साहब बैठे हैं; सुरेन्द्र जी, वो विधायक है, ये दोनों क्षेत्र छोड़ के, यानी कि मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम दिल्लीवासी हैं, गर्व से कहते हैं हम देश की राजधानी में रहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का मंसूबा ये है कि हम दिल्ली से बाहर हो जाएँ, हम दिल्ली से बाहर हो जाएँ। हम देश की राजधानी से

बाहर हो जाएँ और अगर हम देश की राजधानी से बाहर हो गए, तो जो हम गर्व करते हैं पूरे देश में घूम–घूम के आज दिल्ली के बाहर हम जाते हैं, कोई पूछता है, ''भई कहाँ रहते हो?'' तो कहते हैं कि जी, हम दिल्ली में रहते हैं। तो कहता है, ''वाह, देश की राजधानी में रहते हैं। और मेरे साथ अगर गोपाल राय जी जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं आप कहाँ रहते हो? तो जी मैं गुड़गाँवा रहता हूँ, उदाहरण के तौर पे। कहेंगे, ''ओहो! ये तो हरियाणा में रहते हैं।'' तो ये जो दिल्ली का टाइटल है उसको राजधानी के साथ छोड़ के एक नया राज्य बनाकर दिल्ली से बाहर होने की जो योजना बनाई जा रही है, ये बात की जा रही है इस पर भी दिल्ली के नागरिक कभी एक मत नहीं होंगे। क्योंकि देश की राजधानी में रहना, ये हमारा अपना एक गौरव है जिससे कोई राजधानी वासी अलग नहीं होना चाहेगा। पार्लियामेंट का सैशन नहीं है, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है, हमें उनकी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये समझ लेना चाहिए कि देश की राजधानी, देश की राजधानी का जो महत्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता। उस महत्व को हमको कन्सीडर करके चलना पड़ेगा। इसके साथ–साथ आपने 11 जून को एक यहाँ पर 2018 में सैशन किया था, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। क्या हुआ उसका? कहाँ गए वो हस्ताक्षर? चुनाव देख के अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अगर हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि हम लोगों को डॉयवर्ट कर दें, आपकी यही भाषा तब थी जब 2013 में और 2015 में आप चुनाव लड़ रहे थे, बड़ी–बड़ी बातें की जा रही थी इसी तरह, बड़ी–बड़ी बातें की थी; शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, आज

भ्रष्टाचार में खुद सरकार डूबी हुई है। तो लोगों को जिस तरह से... ये बहानेबाजी छोड़ो आप। ये बहाने हैं, 'नाच न आवे, आँगन टेढ़ा, ये साफ रूप से इस बात को सच सिद्ध करता है कि आपको अब काम करना नहीं आ रहा है। साथियो! एक बात कहकर मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आपके पास लोगों को बताने के लिए अचीवमैंटस नहीं हैं, आपके पास लोगों को चेहरा दिखाने के लिए चार साल का लेखा–जोखा जो आपका है, वो नहीं है। अभी तक आप... मुझे याद है मनीष सिसोदिया जी ने बहुत जोर–जोर से कहा था, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, ''सर्विसेज हमारे पास हैं, सर्विसेज हमारे पास है।'' तो अब कहाँ गई सर्विसेज? जब आपके पास हैं तो कहाँ गई? कहाँ चली गई वो? अब चुनाव आ गए हैं तो आपके पास नहीं है और जब चुनाव नहीं थे तो आपके पास थी। सवाल ये है, किसी सीमित अधिकारों के अंदर, दिल्ली के अंदर हर प्रकार का विकास हुआ है। आपने इन सीमित अधिकारों में ही दिल्ली के विकास को रोका है, आपने बढ़ाया नहीं है। आपने फोर्थ फेज रोका, आपने आरईटीएस रोका, आपने आयुष्मान भारत रोका और आपने प्रॉसीक्यूशन सैंक्शन की फाइल रोकी। आपने कहा, ''आपके पास पॉवर नहीं है?'' आपके पास हर नैगेटिव काम करने के लिए पॉवर है। दिल्ली के विकास को हतोत्साहित करने के लिए पॉवर है। आपको दिल्ली के विकास को रोकने की पूरी पॉवर है लेकिन दिल्ली का विकास करने में आपके पास पॉवर नहीं है। ये कौन सा आपका कैलकुलेशन और अर्थमैटिक्स है या आपका कौन सा फार्मूला है कि दिल्ली के विकास को ठप्प करने के लिए आपको मैं दो दर्जन ऐसी घटनाएँ यहाँ पर बता सकता हूँ जो आपकी वजह से,

आपके रोकने की वजह से दिल्ली का नुकसान हुआ है। लेकिन दिल्ली का विकास करने के लिए आपके पास पॉवर नहीं है, ये किस तरह की सरकार की, जो भ्राँति फैलाने की कोशिश है अध्यक्षा महोदया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पहले आपसे चार साल का हिसाब माँग रही है। आप अपने गिरेबान में झाँकिए, आप अपने अंतरमन में झाँकिए। चार साल पहले आप लोग जो बात कहते थे, केजरीवाल जी जो कहते थे, लोग उसको सुनते थे और उसको मानते थे। आज स्थिति ये है कि लोग न सुनते हैं, मानने की तो बात दूर की है। कितनी घोषणाएँ कर चुके हैं अभी तक आप। कितने आंदोलनों की घोषणा कर चुके हैं आप। इतनी बार आपने माफियाँ क्यों मांगी, हम ये जानना चाहते हैं? जब आपने कहा कि फलाँना भ्रष्टाचारी है, फलाँना भ्रष्टाचारी है, तो फिर आपने अब माफियाँ क्यों मांगी? आज लोग आपकी बात सुन नहीं रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी फ्रसट्रेशन है, यही आपकी सबसे बड़ी बौखलाहट है। आज लोग आपसे पीछे हट रहे हैं, आपका आइसोलेशन हो रहा है, सिर्फ राजनैतिक आइसोलेशन नहीं हो रहा, पब्लिक में भी आइसोलेशन हो रहा है। आप कभी ममता बनर्जी को लाते हैं, आप कभी चंद्रबाबू नायडू को लाते हैं, हमारा काँग्रेस से समझौता करवा दो, लोग देख रहे हैं। आपके मैंबर परेशान है।

वो ही नहीं समझ पा रहे हैं, हो क्या रहा है ये। आप क्या लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं दिल्ली की जनता को? लोगों को पता नहीं है? लोगों ने आप पर विश्वास करकर आपके मोहर लगाई थी और ये कहा था वोट डालते वक्त कि भैया, मेरा बटन दब गया। लेकिन मैं और एक बार दबाना चाहता हूँ इसको। सोचिए आपने कितना बड़ा विश्वासघात दिल्ली की जनता

के साथ किया है, ये सोचिए आप। अपने अन्तर्मन में झाँकिए। आपने जिस तरह से दिल्ली के साथ छल किया है। एक बार फिर से आप छल करने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका आंदोलन 11 जून, 2018 को भी टॉय–टॉय फिस्स हुआ था। आपका पूरा हस्ताक्षर अभियान टॉय–टॉय फिस्स हुआ था लोग अब आपकी बात सुन नहीं रहे हैं।

माननीया अध्यक्षा: कंप्लीट कीजिए, गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: लोग अब समझ रहे हैं कि ये सरकार काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करना चाहती है।

माननीय अध्यक्षा: विजेन्द्र गुप्ता जी, कंप्लीट कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: बहानेबाजी के रास्ते ढूंढ रही है। अध्यक्ष महोदया, मैं यहीं कहूँगा कि ये जो प्रस्ताव है, ये काँट्राडिक्टरी हो चुका है। पार्लियामेंट का सेशन समाप्त हो चुका है और दूसरा, दिल्ली को दो हिस्सों में बांटकर हम दिल्ली से बाहर होने की स्थिति में नहीं है। इसलिए इसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए और ये प्रस्ताव जो है, किसी भी रूप में दिल्ली के नागरिकों का हित नहीं कर सकता और ये प्रस्ताव पूरी तरह से एक शगूफा है दिल्ली के लोगों को चुनाव के समय गुमराह करने का। धन्यवाद, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षा: सदन की कार्यवाही 4.15 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। 15 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 4:15 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)

सदन पुनः 4.15 बजे सम्मिलित हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री राखी बिड़ला) पीठासीन हुईं।

माननीय अध्यक्षाः महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, जो आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो कि दिल्ली के लोगों का हक है पूर्ण राज्य का हक, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे बहुत से साथियों को देखते हुए जो इस सदन के साथी हैं, उनको देखकर बड़ा दुःख हो रहा है कि वो लोग जो अपने प्रधान मंत्री के द्वारा दिल्ली के पूर्ण राज्य की बात करते थे, आज उनके गौरे चेहरों से काले दिमाग की उपज पैदा हो रही है और वो दिख रहा है सामने। जिस हिसाब से सिरसा जी ने बोला और नेता विपक्ष ने बोला कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि जब जनता के बीच में जाओगे तो वो जनता आपके चेहरों के ऊपर कालिख मसलेगी ऐसा काम आप लोग कर रहे हैं आज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः समय बताएगा।

श्री महेन्द्र गोयलः समय बताएगा बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है और समय के लिए बता देता हूँ मैं आपको जिस हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा था, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, समय हमेशा परिवर्तनशील है। सुन लो बात समय की, पहले सुन लो समय के लिए कहता हूँ मैं 'वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, आदमी को चाहिए वक्त से डरकर रहे और कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त

का बदले मिजाज' और अहंकार से तीनों गए जैसे आप लोगों का अहंकार है, अहंकार से तीनों गए धन, वैभव और वंश और यकीन नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस, उसी हिसाब से आपका भी साम्राज्य जलकर खाक हो जाएगा ये बता देता हूँ और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। टी शर्ट, नेता प्रतिपक्ष... सुन लो जब मैं आप लोगों से पूछ रहा था ये टी शर्टें कहाँ से आईं, क्या मुख्यालय से हैं, आप लोगों ने कहाँ खरीदी हैं, अरे! जनता के दिल के अंदर बस के देखो। खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।

श्री ओमप्रकाश शर्माः खरीदेंगे क्या?

श्री महेन्द्र गोयलः ऐसी टी शर्ट नहीं चाहिए। आम आदमी के दिलों के अंदर राज करते हैं। लोगों के दिलों की बात जानो आप जो दिल्ली के साथ आप आज दुर्भावना के साथ व्यवहार कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के कामों को रोका जा रहा है। सिरसा जी कह रहे थे, स्कूल नहीं बने। जगदीश प्रधान जी तो अपने मुँह से कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पर दो स्कूल बने हैं या तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। अरे! यहाँ पर डीडीए चाहे जमीन न दे, उन्हीं स्कूलों के अंदर बिल्डिंग बनाने की हिम्मत दिल्ली के मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री रहते ये काम करके दिखाते हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्माः एक भी स्कूल नहीं बना है। बना है, तो बता दो।

श्री महेन्द्र गोयलः सभी बनाए हैं ये 8000 कमरे पहले वैसे बन गये। 11000 कमरे वैसे बनने जा रहे हैं। मोहल्ला क्लीनिक के लिए जगह नहीं

देंगे लेकिन चाहे रोड के ऊपर बनाने पड़ें तो ये दिल्ली सरकार ही है, दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि चाहे पीडब्लूडी की रोड के ऊपर भी या ड्यूसिब की जगह के ऊपर या स्कूलों के अंदर भी बनाना पड़े तो तब भी बना के रहेंगे लेकिन फिर भी और जलबोर्ड के अंदर जितनी भी जमीन थी तो लोगों के स्वास्थ्य को नजर रखते हुए उनके लिए मोहल्ला क्लीनिक बना के देंगे।

श्री ओमप्रकाश शर्माः सारी पटरी घेर रखी है।

श्री महेन्द्र गोयलः ये झूठ बोलने की आदत को छोड़ दो। ये झूठ बोलोगे तो जड़ से मिट जाओगे क्योंकि एक आम आदमी पार्टी ही है जो लोगों के लिए काम करती है। आप लोगों ने जो सात के सात सांसद दिल्ली से भेजे थे, दिल्ली की जनता ने भेजे थे, पूर्ण राज्य के नाम के ऊपर आप लोगों ने वोट माँगे थे। दिल्ली की जनता ने उस विश्वास किया।

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः क्या भेजे नहीं? वो सांसद नहीं थे दिल्ली के? वो दिल्ली की जनता के द्वारा नहीं थे? दिल्ली की जनता को इसका मतलब आप लोग...

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः जनता नहीं मानते। मैं अध्यक्ष महोदया से यह रिकॉर्डिंग माँगना चाहूँगा और उनको कहूँगा कि दिल्ली की जनता को ये बीजेपी के विधायक दिल्ली की जनता को जनता नहीं मानते ऐसे विधायक आप लोगों ने चुनके भेजे थे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः और कुछ भी है बोलने को?

माननीय अध्यक्षाः महेन्द्र गोयल जी, कंप्लीट कीजिए।

श्री महेन्द्र गोयलः सब कुछ है। कन्क्लूड तो आपको बता दिया 2019 आ गई है और 2019 के अंदर कन्क्लूड करके रख देंगे। ये आपको दिखा देंगे हम और आप ये बता दूँ, मैंने उस समय भी पत्रकारों ने पूछा था। बोला, विधायक जी, बोलूँगा, 70 में से 67 सीट आ गई आपकी ये तीन कैसे बच गई? तो मैंने जवाब दिया था उस समय कि झाडू ने कितनी कसके मार लो, कुछ न कुछ कूड़ा बच जाता है। ये वो कूड़ा है। इतनी घबराहट मत मानो। मदनलाल खुराना जी ने पूर्ण राज्य के दर्जे की माँग रखी थी। वो आपकी पार्टी के थे या नहीं थे, वो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ? साहब सिंह वर्मा जी ने यही कहा था कि दिल्ली की विधान सभा को अधिकार पूरे नहीं हैं। क्या वो आपकी पार्टी के थे या नहीं थे? लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने कहा दिल्ली की जनता के हक के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्या वो आपकी पार्टी के थे या नहीं थे? वो आपकी पार्टी के नहीं हैं वाकई में। क्योंकि मोदी जी कहते हैं यदि आज मैं प्रधान मंत्री हूँ तो ये आडवाणी जी की वजह से हूँ और आडवाणी जी की जो हालत है, वो मेरी वजह से है। यही बात है और यही बात आप लोगों की है। दिल्ली की जनता आपको दरकिनार करके रहेगी, ये बाल भी नहीं बचेंगे। अध्यक्षा जी, मैं सिर्फ...

माननीय अध्यक्षाः कंप्लीट कीजिए, गोयल साहब।

श्री महेन्द्र गोयलः आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली की जनता का हक है क्योंकि जुमलेबाजी कितनी कहेंगे, इनके

तो कान पर जूँ नहीं रेंगती, बेशर्म आदमी हैं ये तो। सिर्फ एक ही बात कहता हूँ मैं, जुमलेबाजी की क्या सुनोगे?

(सदन में प्रधान मंत्री मोदी जी की आडियो टेप चलाकर सुनाई)

माननीय अध्यक्षाः महेन्द्र गोयल जी, आप इसे खत्म करके अपनी बात कंप्लीट करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

(सभी विपक्षी सदस्य विरोधस्वरूप सदन के वैल में आए)

माननीय अध्यक्षाः विजेन्द्र गुप्ता जी और ओपी शर्मा जी, आप सीट पर चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः गोयल साहब, आप बैठिए।

श्री महेन्द्र गोयलः नहीं, कैसे बैठ जाएँगे? अभी पूरा कर दें, कन्क्लूड करवाएँ ।

माननीय अध्यक्षाः हाँ, तो आप कंप्लीट करिये ना।

श्री महेन्द्र गोयलः फिर इनको एक तरफ बिठाओ।

माननीय अध्यक्षाः कोई बात नहीं, ये जो कर रहे हैं, करने दीजिए। आप कंप्लीट कीजिए।

श्री महेन्द्र गोयलः अब सुन लो बात, मैं एक बात कहता हूँ। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती है और मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारा 56 किलो का सीएम उसकी छाती पर कूद–कूदकर पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है।

माननीया अध्यक्षाः चलिए महेन्द्र गोयल जी, कम्पलीट कीजिए।

श्री महेन्द्र गोयलः और इनको कहता हूँ, सुन लो, एक बार और। विजेन्द्र जी, सुन लो कानून को छोड़ दें।

माननीय अध्यक्षाः महेन्द्र गोयल जी, आप कन्टीन्यू रखिए। उन्हें सुना रहे हैं, सदन के सामने रख रहे हैं बात? आप अपनी बात कन्टीन्यू रखिए।

श्री महेन्द्र गोयलः देश के प्रधान मंत्री बार–बार कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है और दिल्ली का सीएम जो 56 किलो का है, उसकी छाती पर कूद–कूद कर पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, ये आपको बता दूँ।

माननीय अध्यक्षाः चलिए बहुत–बहुत धन्यवाद। कम्पलीट कीजिए।

श्री महेन्द्र गोयलः कम्पलीट कर दूँगा, इन्हें बैठा दो।

माननीय अध्यक्षाः वो बैठें, न बैठें, आप कम्पलीट कीजिए, महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः इनको बैठा दो, मैं कम्पलीट अभी कर देता हूँ।

माननीय अध्यक्षाः आप कम्पलीट कीजिए।

श्री महेन्द्र गोयलः इनको कहता हूँ, टी शर्ट खरीदने की जरूरत नहीं पडती। इनको कहता हूँ, काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें, न करो कुछ अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें, लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें। काम किया करो। बार–बार ना मार्शलों को उठा कर फेंकनें पड़े, ऐसा काम मत करवाया करो।

माननीय अध्यक्षाः चलिए बहुत–बहुत धन्यवाद गोयल साहब। माननीय मुख्य मंत्री।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः ओ.पी. शर्मा जी, आप बैठिए। आप बैठिए। पहले आप लोग बैठिए। जब तक आप नहीं बैठेंगे, कुछ होगा ही नहीं। आप शांत होकर बैठिए पहले। आप शांत होकर बैठिए पहले तीनों लोग। पहले आप लोग शांत होकर बैठें। पहले आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः माननीय मुख्य मंत्री जी शुरूआत करें। शुरू करें। आप जब तक बैठेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। आप बैठेंगे? नहीं। फिर आप बाहर जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः आप बैठेंगे पहले शांत होकर हाँ या न? आप पहले बैठेंगे शांत होकर। आप बैंठेंगे, आप नहीं बैठेंगे तो ठीक है फिर आप को बाहर... माननीय मुख्य मंत्री जी आप शुरूआत करें। आप जा सकते हैं फिर

बाहर। आप बाहर जा सकते हैं। आप जा सकते हैं बाहर। आप अगर पहले बैठेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोग बैठिए पहले।

...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन)

माननीय अध्यक्षाः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदया, आज सदन के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 70 साल से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली के लोगों का अपमान हो रहा है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी, 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, अंग्रेज चले गए और हमारे देश में जनतंत्र लागू हुआ। जनतंत्र मतलब जनता का शासन। जनता का शासन मतलब लोग वोट डालते हैं, वोट डाल कर अपनी सरकार चुनते हैं और वो सरकार लोगों के लिए काम करती है, लोगों की मांगें पूरी करती है, लोगों को सुरक्षा देती है, लोगों को न्याय देती है, लोगों के विकास के लिए काम करती है, पिछड़े दलित मजदूरों, किसानों के लिए काम करती है। ये सारे काम करने के लिए उस सरकार के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, सारी पॉवर होती है। उन शक्तियों और उन पॉवर को इस्तेमाल करके वो चुनी हुई सरकारें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हैं। पूरे देश के अंदर पिछले 70 साल में... 26 जनवरी, 1950 को पूरे देश में जनतंत्र लागू हो गया। दिल्ली के अंदर जनतंत्र लागू नहीं हुआ। 70 साल से दिल्ली के अंदर जनतंत्र लागू नहीं हुआ। 70 साल से दिल्ली के लोग बार—बार ये ही माँग कर रहे हैं कि दिल्ली में भी जनतंत्र होना चाहिए।

जब मैं कहता हूँ कि दिल्ली में जनतंत्र लागू नहीं हुआ तो एक प्रश्न ये उठ सकता है कि दिल्ली में जनतंत्र कैसे नहीं लागू हुआ, दिल्ली में भी तो लोग अपने वोट डालते हैं; दिल्ली में भी तो लोग सरकार चुनते हैं; दिल्ली में भी तो सरकार चुनकर सरकार को जिम्मेदारी देते हैं? हाँ, दिल्ली में लोग वोट तो डालते हैं; सरकार तो चुनते हैं लेकिन उस सरकार के पास दिल्ली के लोगों के काम करने की कोई भी पॉवर नहीं है। दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास कोई पॉवर नहीं है। दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने की दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास कोई पॉवर नहीं है। दिल्ली के लोगों के विकास के काम करने की दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास कोई पॉवर नहीं है। हरियाणा में लोग सरकार चुनते हैं, उसके पास पूरी पॉवर है। महाराष्ट्र में लोग सरकार चुनते हैं, उसके पास पूरी पॉवर है। मध्य प्रदेश में लोग सरकार चुनते हैं, उसके पास पूरी पॉवर है। दिल्ली के लोग सरकार चुनते हैं, उसके पास कोई पॉवर नहीं है। तो ये बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत बाकी देश के लोगों के वोट की कीमत से कम क्यों है? दिल्ली के लोगों को अपनी पूरी सरकार क्यों नहीं मिलती? दिल्ली पूर्ण राज्य क्यों नहीं है? दिल्ली आधा अधूरा राज्य क्यों है? दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? क्या दिल्ली के लोग पूरा टैक्स नहीं देते? क्या दिल्ली के लोग देश भक्त नहीं है? दिल्ली के लोगों में आखिर ऐसी क्या कमी है जो दूसरे देश के लोग करते है तो दिल्ली के लोग नहीं करते? दिल्ली के लोगों को जनतंत्र क्यों नहीं? अभी तक 70 साल में लागू हुआ।

अध्यक्ष महोदया, पिछले 70 साल के अंदर कभी बीजेपी ने, कभी कॉंग्रेस ने, कभी बीजेपी ने, कभी कांग्रेस ने हर बार चुनाव के पहले वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो पूर्ण राज्य दर्जा देंगे। अगर हमारी सरकार बनी, हमें वोट दो, हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। हमें वोट दो, हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहाँ तक कि पिछले 2014 के चुनाव के पहले मौजूदा प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खुद बोला था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएँगे। उन्होंने खुद वकालत की थी लेकिन दोनों पार्टियों की नीयत खराब थी शुरू से। दोनों पार्टियों को लोगों ने ट्राई किया। दो बार दिल्ली के अंदर सातों सीटें कॉंग्रेस वालों को दी। पिछली बार सातों सीटें बीजेपी वालों को दी। लोगों ने भरोसा करके दी। जब इन पार्टियों ने चुनाव में कहा कि हमें सातों सीटें दो, हम पूर्ण राज्य देंगे। लोगों ने भरोसा करके दे दी। लेकिन जीतने के बाद इन्होंने पूर्ण राज्य दिल्ली को नहीं दिलाया। और अब दुःख की बात ये है कि जब आम आदमी पार्टी ने पूर्ण राज्य की बात उठाई है तो दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पूर्ण राज्य की माँग का विरोध कर दिया। अब दोनों पार्टियाँ कह रही हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ये सरासर पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। ये तो सरासर दिल्ली के साथ विश्वासघात है।

एक प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली में आखिर महिलाएँ सुरक्षित क्यों नहीं है? दिल्ली के अंदर किसी आम आदमी के घर में अगर उसकी लड़की सवेरे–सवेरे कॉलेज के लिए निकलती है, स्कूल के लिए निकलती है, सारा दिन उसका दिल धक–धक करता रहता है। जब तक वो लड़की घर वापिस नहीं आ जाती। उसे ये लगता है; पता नहीं वापिस आएगी या वापिस नहीं

आएगी। वापिस आएगी, वापिस नहीं आएगी। पूरे दिल्ली में आज छेड़छाड़ की इतनी घटनाएँ बढ़ गई हैं, इतनी घटनाएँ बढ़ गई है, आखिर हमारी महिलाएँ सुरक्षित क्यों नहीं हैं? दिल्ली के अंदर चारो तरफ चोरियाँ, डैकैतियाँ, चैन स्नेचिंग, कार की चोरी, मोटर साईकिल की चोरी ऐसे हो गया है जैसे दिल्ली कोई देश की राजधानी न होकर क्राइम कैपिटल बनती जा रही है और बड़े शर्म की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली को रेप कैपिटल और क्राइम कैपिटल की तरह देखा जाता है। आखिर ऐसा क्यूं? दिल्ली के अंदर महिलाएँ सुरक्षित क्यों नहीं हैं? दिल्ली के अंदर महिलाएँ सुरक्षित इस लिए नहीं हैं क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों के अंडर में नहीं आती है। दिल्ली पुलिस सीधे प्रधान मंत्री के अंडर में आती है। अब अगर किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी के घर में चैन स्नेचिंग हो जाए। भगवान न करें किसी की लड़की के साथ कोई गलत काम हो जाए, वो किस के पास जाएगा? वो पहले थाने जाता है। थानेदार अगर उसकी नहीं सुनता, वो किस के पास जाएगा? वो अपने चुने हुए विधायक के पास जाता है। अब विधायक की दिल्ली पुलिस सुनती नही है। विधायक के अंडर में दिल्ली पुलिस आती नहीं है। तो वो बेचारा क्या करेगा? वो अपने मुख्य मंत्री के पास जाता है। अब मुख्य मंत्री की दिल्ली पुलिस सुनती नहीं है। मुख्य मंत्री के अंडर में दिल्ली पुलिस आती नहीं है। अब वो बेचारा प्रधान मंत्री के पास तो नहीं जा सकता। प्रधान मंत्री जी तो किसी से मिलते नहीं हैं। प्रधान मंत्री के साथ तो कोई मिल ही नहीं सकता। चार साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रधान मंत्री जी से मिलने की, मैं नहीं मिल सका। अभी चार साल के अंदर प्रधान मंत्री से,

दिल्ली के मुख्य मंत्री से नहीं मिलते प्रधान मंत्री, एक आम आदमी जिसके घर चोरी हो गयी, डकैती हो गयी, छेड़छाड़ हो गयी, वो किसके पास जाए फिर? आखिर दिल्ली के लोगों के साथ इस तरह से क्यों हो रहा है। आज पूरी दिल्ली चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, दिल्ली इतनी गंदी क्यों है? आप विदेशों में चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, वाशिंगटन चले जाओ, टोक्यो चले जाओ, पेरिस चले जाओ, चारों तरफ आप देखते हो, हर देश की राजधानी कितनी साफ–सुथरी है। इतनी साफ–सुथरी देश की राजधानी है? हम दिल्ली को साफ–सुथरा नहीं कर सकते क्या? हम भी कर सकते हैं अपनी दिल्ली को साफ–सुथरा। दिल्ली साफ–सुथरी क्यों नहीं है? क्योंकि एमसीडी दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती, क्योंकि एमसीडी दिल्ली के लोगों के अंडर में नहीं आती है। सीधे प्रधान मंत्री जी के अंडर में आती है। मैं प्रधान मंत्री जी को कहना चाहता हूँ आप पाकिस्तान संभाल लो, पाकिस्तान तो आपसे संभलता नहीं है। ये दिल्ली पुलिस, एमसीडी, ये दिल्ली के लोगों को दे दो। दिल्ली के लोग अच्छी संभाल लेंगे। दिल्ली के लोग अपना काम खुद कर लेंगे। आज दिल्ली में लोग कच्ची कालोनियों में घर लेने के लिए क्यों मजबूर हैं?

आज दिल्ली के लोगों के पास घर क्यों नहीं है? आज से 50 साल पहले डीडीए बनाई गयी थी। डीडीए का काम ही ये था कि दिल्ली के हर परिवार के लिए एक घर बना के देना। आज दिल्ली के लोगों के पास घर नहीं है। 50 साल में डीडीए ने क्या किया? केवल और केवल बिल्डरों, भ्रष्टाचारियों और माफिया का भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है डीडीए। क्यों? क्योंकि डीडीए दिल्ली के लोगों के अंडर में नहीं आती। क्योंकि दिल्ली

के लोगों के, दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती। प्रधान मंत्री जी के अंडर में आती है। उनको क्या लेना देना, प्रधान मंत्री जी को दिल्ली के लोगों से? उनसे देश की समस्याएँ तो संभलती नहीं हैं। उनका डीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस से उनको क्या लेना देना? आज पूरी दिल्ली के अंदर सीलिंग चल रही है, सीलिंग की वजह से सारे व्यापारी परेशान हैं, सारे दुकानदार परेशान हैं। केन्द्र सरकार के पास दिल्ली सरकार जो उनकी चुनी हुई सरकार है, कह कह के थक गयी, कह कह के थक गयी कि ये सीलिंग बंद कराओ। केन्द्र सरकार को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। केन्द्र सरकार के मंत्रियों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। प्रधान मंत्री के पास टाईम ही नहीं है दिल्ली के व्यापारियों के लिए। तो कौन बंद करेगा दिल्ली की सीलिंग? दिल्ली के व्यापारी आखिर किसके पास जाएँ? अगर डीडीए ने पूरी दिल्ली के अंदर कई दुकानें खोली होती, ढेरों दुकानें खोल दी होती तो आज लोगों को रेजिडेंशियल एरिया के अंदर दुकानें खोलने की जरूरत नहीं थी। वो लीगल दुकानें लेके अपना धंधा कर रहे होते। आज दिल्ली के अंदर हमारे युवा बेरोजगार क्यों हैं? दिल्ली सरकार आज जितने काम कर रही है, इतने नए स्कूल खोल रहे हैं हम, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, इतने अस्पताल खोल रहे हैं, हम डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं, कम से कम दिल्ली सरकार में दो लाख नई नौकरियाँ निकल सकती हैं। दो लाख नयी नौकरियाँ! लेकिन दिल्ली की सरकार के पास पॉवर ही नहीं है नयी नौकरियाँ निकालने की। दिल्ली सरकार के, दिल्ली के मुख्य मंत्री के पास पॉवर ही नहीं है नयी वैकेंसीज निकालने की। कितने लोगों के लिए नौकरियाँ तैयार हो सकती हैं! कितने युवाओं को रोजगार मिल सकता

है! आज दिल्ली के कच्चे कर्मचारी क्यों कच्चे हैं? वो पक्के क्यों नहीं होते? हमारी सरकार ने आने के बाद कम से कम दस बार ऑर्डर जारी कर दिये कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। हमने कैबिनेट में डिसीजन पास कर दिया कि सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो लेकिन निर्णय केन्द्र सरकार को लेना है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। सारी पॉवर केन्द्र सरकार के पास है। आज हमारे बच्चे बारहवीं पास करते हैं। बारहवीं में 99 परसेंट नंबर आने के बाद भी, 95 परसेंट नंबर आने के बाद भी बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। दर–दर की ठोकरें खाते हैं हमारे बच्चे। 95 परसेंट अगर बच्चे के नंबर आ जाएँ तो घर के अंदर खुशी नहीं मनायी जाती, मातम मनाया जाता है। क्यों? इस मनीष सिसोदिया ने चार बार लिख लिया केन्द्र सरकार को, हम नयी यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, हम नए कॉलेज बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, हमको कॉलेज नहीं बनाने दे रहे, हम को यूनिवर्सिटी नहीं खोलने दे रहे। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती, हम अपनी ढेरों यूनिवर्सिटी बनाते, ढेरों हम कॉलेज खोलते और दिल्ली वाले के बच्चों को एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं होती। आज जितने काम हम करना चाहते हैं, हमने दिल्ली में बिजली के रेट कम करे, केन्द्र सरकार ने उस फाइल के अंदर रोड़ा अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम नए स्कूल बनाना चाहते हैं, हमें जमीन नहीं देते, हम उन्हीं स्कूलों के अंदर कमरे बनाते हैं। चलो जमीन नहीं दे रहे, छोड़ो। हम उन्हीं में कमरे बना लेंगे, उसकी फाइल क्लीयर नहीं करते। हम मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उसके अंदर टाँग अड़ाते हैं, हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, उसमें टांग अड़ाते हैं। हर फाइल

मोदी सरकार अपने पास मंगा के, हर फाइल मंगा के उसके अंदर टाँग अड़ाती है। इन सब चीजों के बावजूद हमने इतना काम कर के दिखाया, इतना काम करके दिखाया है। आज अगर कोई जनता का आदमी मुख्य मंत्री के पास आके कहे कि जी, ये अफसर पैसे माँग रहा है, ये अफसर काम नहीं करता, ये अफसर भ्रष्टाचारी है, चोर है, डकैत है, ये अफसर। इसका कुछ करो, मुख्य मंत्री के पास पॉवर ही नहीं है उस अफसर को कुछ करने की। कैसे चलेगी ये सरकार! आखिर दिल्ली के लोगों को ऐसा क्यों कर रखा है केन्द्र सरकार ने? अब एक ही चारा रह गया; आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोगों को सबको, पूरी दिल्ली के लोगों को मिल के अब पूर्ण राज्य का दर्जे के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तभी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो कानून–व्यवस्था ठीक होगी दिल्ली की, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, पूरी दिल्ली के अंदर साफ सफाई होगी। ऐसा बना देंगे दिल्ली को, ऐसा चमका देंगे दिल्ली को; लंदन और सिंगापुर और पेरिस दिल्ली से पीछे छूट जाएँगे, दिल्ली को ऐसा शानदार बनाएँगे, गर्व होगा लोगों को दिल्ली के उपर। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, हर दिल्ली के परिवार को हम एक पक्का घर बना के देंगे, उनका अपना घर बना के देंगे। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा। जब हम दिल्ली के चुनाव लड़ा करते थे, गली गली में जा के मैं कहा करता था कि अगर हमारी सरकार बन गयी, हम दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर देंगे, ये बीजेपी और काँग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे, ''केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के रेट आधे नहीं हो सकते।'' हमने करके दिखाए। सरकार बनने के एक महीने के अंदर हमने

करके दिखाए थे। अब अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बन गयी, ये मेरा वादा है जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दस साल के अंदर दिल्ली में रहने वाले हर वोटर फैमिली को हम एक घर देंगे उनका अपना एक घर देंगे दोस्तों! दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, सारी कच्ची कालोनियों को पक्का करेंगे, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, ये सीलिंग बंद करेंगे, नए—नए बाजार खोलेंगे, पूरी दिल्ली के अंदर नए—नए बाजार खुलेंगे ताकि व्यापारियों को न इतनी दुकानें चलाने के लिए मिल सकें, वे नया व्यापार शुरू हो सकें। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी; युवाओं को रोजगार मिलेगा, कम से कम दो लाख सरकार में नई नौकरियाँ निकलेंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी दिल्ली के सारे कच्चे कर्मचारियों को, ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, आज मैं यहाँ पे सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इतनी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, इतने कॉलेज खोलेंगे कि बारहवीं के बाद 50 परसेंट नंबर मिलने वाले बच्चे को भी कॉलेज के अंदर, अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा दोस्तो! दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो एक भी फाइल मोदी सरकार नहीं मंगा सकती। आज हरियाणा की फाइलें नहीं मंगा सकती मोदी सरकार, पंजाब की फाइलें नहीं मंगा सकती मोदी सरकार, महाराष्ट्र अगर कहे कि हमें स्कूल खोलने हैं, मोदी सरकार फाइलें नहीं मंगा सकती। हमारी सारी फाइलें मोदी जी के पास जाती हैं, हमारी सारी फाइलें वहाँ पे अप्रूवल के लिए जाती हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी जो काम करने करने में आज तीन साल लग रहे हैं, मैं आज ये कह रहा हूँ, एक महीने के अंदर वो काम पूरे हो जाया करेंगे। खूब स्पीड के साथ दिल्ली का काम होगा और दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, जो अफसर

काम नहीं करेगा और जो अफसर भ्रष्टाचार करेगा, सीधे पकड़ के उसको कॉलर से, जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। 49 दिन में हमने करके दिखाया था। 32 अफसर जेल भेजे थे, काँपने लग गयी थी ये सारी अफसरशाही। ये दिल्ली पुलिस ठीक हो गए थे सारे के सारे। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, इस अफसरशाही को भी ठीक करेंगे। ये अभी मनमानी कर रहे हैं जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, ये सारे जनता की सेवा करेंगे, करके दिखाएँगे हम लोग दोस्तो।

दोस्तो! 70 साल से दिल्ली की जनता अन्याय बर्दाश्त कर रही है। 70 साल से जो भी केन्द्र में सरकार आती है, वो केवल और केवल दिल्ली वालों का खून चूसने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। दिल्ली के लोग डेढ़ लाख करोड़ रुपये का इन्कम टैक्स देते हैं, डेढ़ लाख करोड़ रुपये का, बदले में उनको तीन सौ करोड़ रूपये... 325 करोड़ रुपये देती है केन्द्र सरकार। इतना जुर्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं ढाया था! अंग्रेज भी यहाँ पे टैक्स वसूल–वसूल के सारा लंदन ले जाया करते थे लेकिन जिस तरह से केन्द्र सरकार ने दिल्ली वालों का खून चूसा है, उस तरह से तो अंग्रेजों ने भी खून नहीं चूसा था दोस्तो। हर सरकार ने दिल्ली वालों का शोषण किया है! दिल्ली वालों का शोषण किया है! इसको बंद करना है। ये अब दोस्तो, बंद होगा। दिल्ली के लोगों ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, हमारी कोई औकात नहीं थी... यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 2–4 को छोड़ दो तो आज तक हम कोई एक चुनाव तक नहीं लड़े थे। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। हम लोग गली में घूमा करते थे। एक छोटी सी एनजीओ

चलाया करते थे, कोई बिसात नहीं थी हम लोगों की। कोई औकात नहीं थी हम लोगों की। दिल्ली के लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, 67 एमएलए जिता दिये, मुख्य मंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया। दिल्ली के लोगों के इस एहसान के बदले आज अगर हमारी जान भी चली जाये तो जान हाजिर है, दिल्ली के लोगों के लिये। सात जन्म के अंदर भी सात जिंदगी दे के भी हम दिल्ली वालों का एहसान नहीं चुका सकते, दोस्तो। तो एक मार्च से आंदोलन चालू होगा। दिल्ली के अंदर एक मार्च से दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का आंदोलन चालू होगा और ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं मिल जाता। दिल्ली के लोगों को संगठित करने के लिये और दिल्ली के इस आंदोलन की शुरूआत करने के लिये अध्यक्ष महोदया, मैं एक मार्च से अनिश्चित कालीन समय के लिये उपवास के ऊपर बैठ रहा हूँ। मेरा मकसद केवल और केवल दिल्ली के लोगों को संगठित करना है, आज सारी दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले लेकिन उनकी इस माँग को संगठित करने के लिये और दिल्ली के लोगों को सबको तैयार करने के लिये एक मार्च से में अनिश्चित कालीन उपवास के लिये बैठूँगा। जैसा मैंने कहा कि अगर इस आंदोलन में हम लोगों की मौत भी हो जाये तो मंजूर है। हम खुशी–खुशी मौत को गले लगा लेंगे लेकिन अब आर या पार की लड़ाई है। दिल्ली को पूर्ण राज्य मिल के ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षाः श्री नीतिन त्यागी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के समक्ष हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब सदन की कार्यवाही सोमवार 25 फरवरी 2019 को अपराह्न दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है, धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्षा के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 25 फरवरी, 2019 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की गई।)